



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1991/फाल्गुन 18, 1912

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1991/PHALGUNA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India other than
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1991

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICE

New Delhi, the 25th February, 1991

का. आ. 633.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम
6 के अनुरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा
यह सूचना दी जाती है कि श्री राजेन्द्र नाथ घोष
ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के
अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि
उसे 24-परगना, पश्चिम बंगाल व्यवसाय करने के
लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास पास भेजा जाए।

[संख्या 5(10)/91—न्या.]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 633.—Notice is hereby given by the Competent
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956,
that application has been made to the said Authority, under
rule 4 of the said Rules by Shri Rajender Nath Ghosh for
appointment as a Notary to practise in 24-Parganas, West
Bengal.

2. Any objection to the appointment of the said person
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned
within fourteen days of the publication of this Notice

[No. F. 5(10)/91-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय
(भान्तरिक सुरक्षा विभाग)
(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1990

का. प्रा. 634.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या-44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ श्री बी. रामनाथ, विशेष सचिव, भूमि एवं भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन के द्वारा भी उनके अपने कार्य के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित शहरी एवं ग्रामीण निष्क्रान्त सम्पत्तियों के प्रबन्ध तथा निबटान हेतु प्रयोजना होंगे।

2. इसके द्वारा अधिसूचना संख्या 1 (3) विशेष सेल 89—एस. एस. एस. 11 (क) दिनांक 28-8-89 का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(3)/विशेष सेल/89 एस.एस. II(एस.)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Internal Security)
(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 20th November, 1990

S.O. 634.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (Act No. 44 of 1954) the Central Government hereby directs that powers exercisable by it under Section 33 of the said Act, shall be exercisable also by Shri V. Ramnath, Special Secretary, Land and Building Department, Delhi Administration, in addition to his own duties, in respect of the management and disposal of evacuee urban and rural properties and lands situated in the Union Territory of Delhi.

2. This supersedes notification No. 1(3) Spl. Cell/89-SS.II(A) dt. 28-8-1989.

[No. 1(3)/Spl. Cell/89-SS.II(S)]

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1991

का. प्रा. 635.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मध्य प्रदेश में राजस्व जिलों के समाह्वितियों को उन्हें अपने-अपने कार्य क्षेत्र में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत समाह्वितियों के बतौर अपने कार्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य के भीतर क्षतिपूर्ति पूल के भाग

के तौर पर भूमि एवं भवन के संबंध में बंदोबस्त आयुक्त के रूप में सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं. 1(4) विशेष कक्ष/89-एस.एस. II/(एस.)]

New Delhi, the 5th February, 1991

S.O. 635.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints all the Collectors of Revenue Districts in the State of Madhya Pradesh as Settlement Commissioners for the purpose of performing, in addition to their own duties as Collectors within their jurisdiction, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool within the State of Madhya Pradesh.

[No. 1(4)/Spl. Cell/89-SS.II(S)]

का. प्रा. 636.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूमि एवं भवन विभाग निष्क्रान्त सम्पत्ति कक्षा दिल्ली प्रशासन में सहायक बंदोबस्त अधिकारियों सर्वश्री सतीशचन्द्र एवं एच. एस. भाटिया को उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पूल के भाग के तौर पर संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित अधिग्रहीत निष्क्रान्त ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्तियों तथा भूमि के प्रबन्ध एवं निपटान के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन उन्हें प्रबन्ध अधिकारी के रूप में सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं. 1 (3) विशेष कक्ष/89 एस.एस. II—बंदोबस्त (क)]

S.O. 636.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints S/Shri Satish Chander and H. S. Bhatia, Assistant Settlement Officers in the Land and Building Department, Evacuee Property Cell, Delhi Administration, as Managing Officers in addition to their own duties, for the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act, in respect of management and disposal of acquired evacuee urban and rural properties and lands situated in the Union Territory of Delhi, forming a part of the Compensation Pool.

[No. 1(3)/Spl. Cell/89-SS.II(S(A))]

का. आ. 637.—निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भूमि एवं भवन विभाग निष्क्रान्त सम्पत्ति कक्ष दिल्ली प्रशासन में सहायक बंदोबस्त अधिकारियों सर्वश्री सतीश चन्द व एच एस. भाटिया को तत्काल प्रभाव से उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन उन्हें सहायक अभिरक्षक के रूप में सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से सहायक अभिरक्षक नियुक्ति करती है।

[सं. 1(3)/विशेष कक्ष / 89-बंदोबस्त (ख)]

रतन लाल, अवर सचिव

S.O. 637.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints S/Shri Satish Chander and H. S. Bhatia, Assistant Settlement Officers in the Land and Building Department, Evacuee Property Cell, Delhi Administration, as Assistant Custodians of Evacuee Property, in addition to their own duties, for the purpose of performing the functions assigned to such Assistant Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(3)/Spl. Cell/89-SS.II(SB)]

RATTAN LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1991

का. आ. 638.—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन तथा उक्त नियमों की अनुसूची 2 मद संख्या 3 के प्रवर्ग 1(ख) और 1(ग) की बाबत पंजाब की राज्य सरकार को जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 की घोषणा के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों से न्यस्त करती है, अर्थात्:—

- (क) पंजाब की राज्य सरकार इन कृत्यों का प्रयोग करने में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेगी ;
- (ख) पंजाब की राज्य सरकार इन कृत्यों का प्रयोग करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत नीति और अनुदेशों का पालन करेगी और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहमति के बिना उनसे असंगत जो केन्द्रीय सरकार के हैं, अनुदेश जारी नहीं करेंगी ;
- (ग) इन कृत्यों का प्रयोग पंजाब की राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन राज्य क्षेत्र तक सीमित रहेगा ;
- (घ) पंजाब की राज्य सरकार द्वारा इन कृत्यों का प्रयोग आरंभ में इस अधिसूचना के जारी किए जाने

की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए किया जाएगा।

- (ङ) इस प्रकार जारी की गई अनुरूपियों का, प्रत्येक दो वर्ष के अवसान पर उसके आधार पर धारित शस्त्रों की भस्तिता जांच के बाद नवीकरण किया जाएगा।

[सं. वी/-11014/1/91-आयुध]

टि. के. रविन्द्रनाथ/अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 1991

S.O. 638.—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government entrust to the State Government of Punjab which is under the proclamation of article 356 of the Constitution the functions of the Central Government under the provisions of the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 1962 in respect of categories I(b) and I(c) of clause (a) of item number 3 of schedule II to the said rules, subject to the following conditions, namely :—

- (a) The State Government of Punjab shall be in the exercise of these functions, be subject to the supervision and control of the Central Government;
- (b) the State Government of Punjab shall, in exercise of these functions observe the policies and instructions laid down by the Central Government and it shall not issue instructions inconsistent with those of the Central Government, without the prior consent of the Central Government;
- (c) the exercise of these functions shall be limited to the territories under the administration of the State Government of Punjab;
- (d) these functions shall be exercised by the State Government of Punjab, initially for a period of three months from the date of issue of this notification.
- (e) the licences thus issued shall be renewed on expiry of every two years after physical verification of the weapon possessed on the strength thereof.

[No. V-11014/1/91-Arms]

T. K. RAVINDRANATH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

महानिदेशक आयकर छूट का कार्यालय

कलकत्ता, 7 जनवरी, 1991

आयकर

का.आ. 639.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 पैतीस/एक/तीन की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

संगीत महाभारती

संगीत शिक्षालय, प्लॉट नं. ए—6

10 वी रोड, जुहु स्कीम, वीले पार्ले—(डब्ल्यू)

बम्बई-400049

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणः— संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपयुक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 329/फा. सं. डी जी/एम-23 कल.

35(1)(iii) / 89 आ. कर (छूट)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[Office of the Director General of Income Tax (Exemptions)]

Calcutta, the 7th January, 1991

(INCOME TAX)

S.O. 639.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax

Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions.

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sangit Mahabharati,

Conservatories, Plot No. A/6,

10th Road, Juhu Scheme, Vile Parle (W),

Bombay-400049.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 329/F. No. DG/M-23/Cal/35(1)(iii);89-IT(E)]

आयकर

का.आ. 640.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस एक दो: की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान

विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड,
नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (2) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा परीक्षित अपनी वार्षिक लेखों की एक प्रति-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

साइ-टेक सेंटर,
दलमल हाउस,
नरिमन पाइन्ट,
बम्बई-400021

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:— संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त, आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 330 फा.सं. डी. जी./एम-98 कल. 35(1)]
89—आ. कर (छूट)

(INCOME TAX)

S.O. 640.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bha-

wan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sci-Tech Centre,
Dalmal House,
Nariman Point,
Bombay-400021.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 330/F. No. DG/M-98/Cal./35/(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 641.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्-द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 पैरिस एक दो की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर, संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त

आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन रेजिस्टर आफ शिपिंग
72, मेकर रावर 'ए'
कुफे परेड,
बम्बई-400005

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अवधि उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं 331 फा. सं. डी. जी. एम 2 कल 35 (1)
(ii) 8 आयकर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 641.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited

annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

(INCOME TAX)

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Register of Shipping,
72, Maker Towers 'F',
Cuffe Parade,
Bombay-400005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of the Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 331/F. No. DG/M-2/Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता 18 जनवरी, 1991

आयकर

का. आ. 642.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैटीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संस्थान प्रवर्ग' के अधीन अनुमोदित किया गया है, —

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून, तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दें के. आर. कामा ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूट,
136, बम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट,
बम्बई-400023

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:— संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 332/फा. सं. डी. जी. /एम-89/कल 35 (1) (iii) 90 आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 18th January, 1991

(INCOME TAX)

S.O. 642.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The K. R. Cama Oriental Institute,
136, Bombay Samachar Marg, Fort,
Bombay-400023.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 332/F. No. DG/M-89/Cal./35(1)(iii)|90-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 643.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक आयकर छूट द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दें इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रिटरीज ऑफ इण्डिया
22, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 333/फा. सं. डी जी/एन. डी 14/कला. 35 (1) (iii) 89-आयकर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 643.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Company Secretaries of India.
22, Institutional Area Lodi Road.
New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax, the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of

the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 333/F. No. DG/ND-14/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 644.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गांधी मिमारिअल लेफ्टिस फाउण्डेशन,
हिन्दी नगर, वारधा - 4421031

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 334/फा. सं. डी जी/एम - 118 कल. 35/(1) (ii) 90-आ.कर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 644.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhi Memorial Leprosy Foundation, Hindi Nagar, Wardha-442103.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 334/F. No. DG/M-113/Cal./35(i)(ii) '90-ITC(E)]

7 (आयकर)

का.आ. 645 :-सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिमूर्चित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस एक दो) की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

474 GI/91-2

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री जयदेव इन्स्टिट्यूट आफ कार्डिओलॉजी,
विक्टोरिया अस्पताल काम्पनेक्स,
बैंगलूर - 560002

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन के अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 335 फा. सं. डी जी के टी 32 कल. 35(1) (ii).
90 - आ. कर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 645.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Jayadeva Institute of Cardiology, Victoria Hospital Complex Bangalore-560002.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax (the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 335/F. No. DG/KT-32/Cal/35(1)(ii), 90-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. :- 646 सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) तीन) की उपधारा (i) के खंड (iii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी, अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 3 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री सोहनलाल जैन विद्या प्रसारक समिति,
20/6, मथूरा रोड,
फरीदाबाद - 121006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर

आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 336 /फा. सं. डी जी/एच-2/कल./35/(1) (iii)/
89 - आ. कर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 646.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five one three) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :-

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Shri Sohanlal Jain Vidya Prasarak Samiti, 20/6, Mathura Road, Faridabad-121006.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax (the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 336/F. No. DG/H-2/Cal 35(1)(iii), 89-IT(E)]

कलकत्ता, 22 जनवरी, 1991

Calcutta, the 22nd January, 1991

(आयकर)

(INCOME TAX)

का. आ. 647:—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, का प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दो फाउंडेशन फॉर मेडिकल रिसर्च,
गोदरेज भवन, 4ए, होम स्ट्रीट,
बम्बई - 400001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन की अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 337/फा. स. डी जी/एम-131/कल./35(1) (ii)/
90 - आ. कर (छूट)]

S.O. 647.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (thirty five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

The Foundation for Medical Research, Godrej Bhawan,
4-A, Home Street, Bombay-400001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 337/F. No. DG/M-131/Cal.35(1)(ii)/89-II(E)]

(आयकर)

का. आ. 648 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/तीन) की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी, अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

- (2) या अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन नेशनल थियेटर,
19-21, हमाम स्ट्रीट,
बम्बई-400023।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 338/फा. सं. जी. जी/एम-50/कल. /35 (1)
(iii)/89 -आ. कर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 648.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 5 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) or Section 35 (Thirty Five) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax [Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian National Theatre, 19 21, Haman Street, Bombay-400023.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax [the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for tax extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 338/F. No. DG/M-50/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 24 जनवरी, 1991

(आयकर)

का. आ. 649.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक / दो /) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी, अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/प्रबर्ग" के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016, को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क)

महानिदेशक आयकर (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हिमालयन इन्स्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट
113/89, स्वरूप नगर
कानपुर—208001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:— संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करता है।

[सं. 339/फा. सं. डी. जी. /यू. पी. -9/कल. 35/
(1) (iii) /89 आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 24th January, 1991.

(INCOME-TAX)

S.O. 649.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year, and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Himalayan Institute Hospital Trust
113/89, Swaroop Nagar,
Kanpur-208001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 339/F. No. DG/UP-9/Cal./35(1)(i)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 650—मर्यादाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस / एक / तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक आयकर (छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "सरस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक आयकर (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिन के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री अरविन्द सोमार्हटी,
(यूनिट : श्री अरविन्द इन्स्टिट्यूट आफ रिमर्च
सोशल साइन्स रंगपिल्लवाई स्ट्रीट,
पाण्डिचेरी—605001.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी :—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपयुक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 340/फा. सं. डी जी / पोण्ड — 1 कल. / 35 / (1) (iii) 89—आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 650.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Shri Aurobindo Society,
(Unit : Shri Aurobindo Institute of
Research in Social Science), Rangapillai Street,
Pondicherry-605001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In

exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 340/F. No. DG/Pond-1/Cal./35(1)(iii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का. आ. 651—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(वैतीस / एक / तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक आयकर (छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय प्रवर्ग" के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली—110016, को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक आयकर (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बम्बई विश्वविद्यालय
(युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आफ केमिकल टेक्नोलॉजी)
महात्मा गांधी रोड,
बम्बई—400032

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन

प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 341/फा. सं. डी जी/एम-91 कल. 35 (1)
(ii)/89-आ. कर-(छूट)]

(INCOMETAX)

S.O. 651.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-Tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

(University Department of Chemical Technology)
Mahatma Gandhi Road,
Bombay-400032.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1993.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 341/F. No. DG/M-91/Cal. 35(1)(ii)/89-IT(F)]

(आयकर)

का. आ. 652:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन, को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस एक/दो) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय बर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली —110016, को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान, विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

भारतीय विद्या भवन,
मुंशी सदन, कूलपटी,
के. एम. मुंशी मार्ग,
बम्बई-400007.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी:—संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के आध्यक्ष से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने

के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 342/फा. सं. डीजी/एम-42/कल. / 35/(1) (ii)-89 आ. कर. (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 652.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year ; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhartiya Vidya Bhavan,
Munshi Sadan, Kulpati,
K. M. Munshi Marg,
Bombay-400007.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 342/F. No DG/M-42/Cal /35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 653 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (II) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन

विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-क्रमावली का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एम.एन. शाह रिसर्च फाउन्डेशन फॉर स्टोन इन्डस्ट्रीज, नॉबलज-ए. नीमरी मजिद, नेहरू त्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी :— संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिन के क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 343/फा.स. डीजी/जी-20/कल./35/(1) (ii)/89-आ. कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 653.—It is hereby notified for general information that the Organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department

of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) or sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-Tax Act, 1961 under the category, "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May. of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

M. L. Shah Research Foundation Store Industries,
Nobles-A, 3rd Floor, Opp Nehru Bridge,
Ashram Road,
Ahmedabad-380 009

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE :- The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No 343/F No DG/G-20/Cal /35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 654 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/तीन) की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छुट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016. को भेजेगा।

- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छुट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छुट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नालन्दा डैन्स रिसर्च सेंटर,
प्लॉट नं.-ए-7/1, एन.एम. रोड नं. 10,
जे.वी.पी.डी. स्कीम, विने पाल (वेस्ट),
बम्बई-400049.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छुट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छुट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदिन आवेदन उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदिन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 344/फा सं.-जी डी/एम-95/कल./35 (1) (iii)/89-
(आकर छुट)]

(INCOME-TAX)

SO 654.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/three) of the Income-Tax Act, 1961 under the category, "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research .
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the

organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Nalanda Dance Research Centre,
Plot No. A-7/1, N. S. Road No. 10,
J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West),
Bombay-400049.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1991.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No 344/F No. DG/M-95/Cal /35(1)(iii)/89-111(F)]

(आयकर)

का.आ. 655:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/दो) की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "मंच" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, प्राप्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नमिलनाडू साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर,
इंजीनियरी कॉलेज पोस्ट,
मद्रास-600025

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1989 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कनकता, को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये मुआव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 345/पा सं.-डी जी/टी एन-46/कल./35 (1) (ii)/
89-1110 कर (छूट)]

(INCOME-TAX)

S.O. 655.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May, of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Tamil Nadu Science and Technology Centre,
Engineering College Post,
Madras-600025.

This Notification is effective for the period from 1-4-1989 to 31-3-1992.

NOTE :—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as

soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 345/F. No. DG/IN-46/Cal./35(I)(ii)/89-JT(E)]

कलकत्ता, 25 जनवरी, 1991

(आयकर)

का.आ. 656.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षण वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मेडिकल रिसर्च सेंटर आफ इम्बई,
अस्पताल ट्रस्ट,
12, मेरिन लाइन्स,
इम्बई-400020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह को समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की

समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है

[स. 346/फा.स. डॉ. जा/एम-1/कल./35/(1)(ii)/89-आ० कर (छूट)]

Calcutta, the 25th January, 1991

(INCOME TAX)

S.O. 656.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (1) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category 'Institution' subject to the following conditions :

- (1) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Medical Research Centre of Bombay Hospital Trust,
12, Marine Lines,
Bombay-400020.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 346/F. No. DG/M-1-Cal./35(I)(ii)/89-JT(E)]

(आयकर)

का.आ. 657.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव,

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है —

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टी रिसर्च एसोसिएशन,
113, पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिसके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विरोध मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 347/फा.सं. डी जी/प. बं.-17/कल./35 (1) (ii),
89-आ. कर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 657.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes

of clause (1) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Tea Research Association,
113, Park Street,
Calcutta-700016.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1992.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 347/F. No. DG/WB-17/Cal./35(1)(ii)/89 IT(E)]

कलकत्ता, 28 जनवरी, 1991

(आयकर)

का.आ. 658 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बकुल फिनेचेम रिसर्च सेंटर,
स्टर्लिंग सेंटर, चौथी मंजिल,
16/2, डॉ. एनी बेसेन्ट रोड,
वारली, बम्बई-400018.

यह अधिमूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[स. 348/फा.स. डी जी/एम-35/कल/35/(1) (ii) 89-
आ. कर (छूट)]

Calcutta, the 28th January, 1991

(INCOME TAX)

S.O. 658.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (1) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and

(c) Commissioner of Income-tax (Director of Income-tax (Exemptions)) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Bakul Finchem Research Centre,
Sterling Centre, 4th Floor,
16/2, Dr. An. Annie Besant Road,
Worli, Bombay-400018.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 348/F. No. DG/M-53/Cal./35(1)(ii)/89-IT(F)]

कलकत्ता, 29 जनवरी, 1991

(आयकर)

का.मा. 659:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अहमदाबाद टेक्स्टाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च असोसिएशन,
पॉलिटेक्निक, पो सा,
अहमदाबाद-380015

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता का तीन प्रतियां में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामला में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथार्थाध अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का प्रस्तुत करना है।

[सं 349/फा स डी जी/जी-33/कल/35(1) (11)
/89-आयकर (छूट)]

Calcutta the 29th January, 1991

(INCOME TAX)

SO 659—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in consultation with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (1) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five one/two) of the Income tax Act 1961 under the category 'Association' subject to the following conditions

- (1) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research,
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan New Mehrauli Post New Delhi 110016 for every financial year by 31st May of each year and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemption) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities

NAME OF THE ORGANISATION

Ahmedabad Textile Industries Research Association
Polytechnic, P.O.
Ahmedabad 380015

This Notification is effective for the period from 1st April, 1990 to 31st March 1991

NOTI—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval to the Director General of Income tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax (the Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research

[No 349/E No DG/G 33 Cal/35(1)(ii) 89 IT(1)]

आयकर

का आ 660—सर्वगतार्थ यह सूचना के तहत पत्रद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन का, आयकर अधिनियम 1961 का प्रांग 35 (पंचम/एक/दो) की उपप्रांग (1) के खण्ड (11) के लिये सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "सघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यरताओं का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली पोस्ट, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह पत्र के तहत की 30 जून तक, सखा-परिभ्रित वार्षिक खाता की एक प्रति अपनी धन, प्राप्ति तथा धनदायिता के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ग) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

फाउंडेशन फॉर प्लास्टिक रिसर्च इन कैरर,
डी-131, पंचशील एनक्लेव,
नई दिल्ली 110017

यह अधिसूचना दिनांक 13-9-1990 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी संगठन का अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन

प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का प्रस्तुत करता है।

[सं. 350/फा. सं. री. जी./एन. टी.-54/कल/35 (1)
(iii)/90-आयकर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 660 -It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (1) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Foundation for Applied Research in Cancer,
D-131, Panch Sheel Enclave,
New Delhi-110017.

This Notification is effective for the period from 13th September, 1990 to 31st March, 1992.

NOTE—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 350/F. No. DG/ND-54 Cal./35(1)(ii)/89-IT(E)]

कलकत्ता, 31 जनवरी, 1991

(आयकर)

का.आ. 661 :- सर्वसाधारण की सूचना के लिये तद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 को धारा 35 (पैंतीस/एक/दो) को उपधारा (1) के खण्ड (99) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून, तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नैशनल सेंटर फॉर माप्टवेयर टेक्नोलॉजी,
ग्लोबोहर ग्राम रोड नं. 9, जुहु,
बम्बई-400049.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में

किंग गण आवेदन-पत्र को 6 प्रतिमा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 351/का.सं. डी. जी./एम-22/कल/35 (1)
(ii)/89/आयकर (छूट)]

Calcutta, the 31st January, 1991

(INCOME TAX)

S.O. 661.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (i) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

National Centre for Software Technology,
Gulmohar Cross Road No. 9, Juhu,
Bombay-400049.

This Notification is effective for the period from 1st April 1991 to 31st March, 1992.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 351/F. No. DG/M-22/Cal/35(1)(ii)/89-IT(F)]

(आयकर)

का.आ. 662 :—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकाव्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून, तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल इण्डिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
88/2, बजाज नगर,
नागपुर-440010

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1991 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिये मुज्ञाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करे। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किंग गण आवेदन पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 352/का.सं. डी. जी./एम-46/कल./35 (1)
(ii)/89/आयकर (छूट)]

(INCOME TAX)

S.O. 662.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (i) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific

fic research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Central Indian Institute of Medical Science,
88/2, Bajaj Nagar,
Nagpur-440010.

This Notification is effective for the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1992.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 352/F. No. DG/M-46/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

(आयकर)

का.आ. 663 :— सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर

आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति,
सवाई मानसिंह अस्पताल,
जयपुर-302004.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1990 से 31-3-1991 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां भेज कर आवेदन करने के लिये सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[स. 353/फा.स. डी.जी./यू पी-6/कल./35 (1)(ii)/90-आयकर (छूट)]

जे. चक्रवर्ती, उप निदेशक आयकर (छूट)

(INCOME TAX)

S.O. 663.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure and its assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Shri Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti,
Sawat Mansing Hospital,
Jaipur-302004

This Notification is effective for the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1991.

NOTE.—The Organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/the Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 353/F. No. DG/R-6/Cal./35(1)(ii)/90-IT(E)]

J. CHAKRABORTY, Dy. Director
(I.T. Exemptions).

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1991

का.आ. 664 :—केन्द्रीय सरकार, स्वापक अधिध और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68B की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 385 (अ), तारीख 29 मई, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद (3) में, “श्री जी.आर. पटवर्धन” शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “श्री एन.पी. भट्ट” शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/46/यू. एस. (कोई)/90-एनसीबी/11761]

एम. सी. मेहनाथन, अवसर सचिव

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 22nd January, 1991

S.O. 664—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue S.O. No. 385(E) dated the 29th May, 1989, namely :—

In the said notification in item (3) for the letters and words “Shri G. R. Patwardhan” the letters and words “Shri N. P. Bhat” shall be substituted.

[F. No. 1/46/US(Coord)/90-NCB/11761]

M. C. MEHNAATHAN, Under Secy

(अय्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

का.आ. 665 :—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध (धारा

6 क को छोड़कर) गूट-निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली नई दिल्ली के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[स. 4(1)-संस्था 5/90 (I)]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 20th February, 1991

S.O. 665—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except section 6A) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Research and Information System for the Non-aligned and Other Developing Countries, New Delhi

[No. 4(1)-E.V./90(1)]

का.आ. 666 :—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित लोक संस्थान को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल है :—

“गूट निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली, नई दिल्ली।

[स. 4 (1)-संस्था 4/90 (II)]

हुमेरा अहमद, उप सचिव

S.O. 666—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the schedule to the said Act the name of the following public institution, namely :—

“Research and Information System for the Non-aligned and Other Developing Countries, New Delhi.”

[No. 4(1)-E.V./90(II)]

HUMERA AHMED, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का.आ. 667 :—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, वित्त मंत्रालय (अय्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2815, तारीख 13-9-1988 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(i) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ख” में संबंधित भाग 1 में,—

(क) क्रम सं. 3 में, स्तंभ 5 में, “अपर उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक” शब्दों के पूर्व

निम्नलिखित शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे,
अर्थात्,—

“उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक”;

(ii) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ग” से संबंधित
भाग 2 में,—

(क) क्रम सं. 3 में, अनुभाग अधिकारी से
संबंधित मद (i) में, स्तंभ 2 में, “सहायक
नियंत्रक महालेखापरीक्षक” शब्दों के स्थान
पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—
“ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार/
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के
कार्यालय में समतुल्य पंक्ति के अधिकारी”।

[का.स. सो-11021/2/90-ई.जी. 1]

डी. त्यागेश्वरन, अवसर सचिव

नोट :

1. मूल अधिसूचना दिनांक 24-9-1988 के भारत के
राजपत्र भाग II, खण्ड 3(ii) में पृष्ठ 3474 से 3477
के अन्तर्गत का.आ. 2815 दिनांक 13-9-1988 द्वारा
प्रकाशित की गयी थी।

2. शुद्धिपत्र दिनांक 12-11-1988 के भारत के राजपत्र
में पृष्ठ 4120 पर का.आ. 3349, दिनांक 1-11-1988
द्वारा प्रकाशित किया गया था।

3. बाद में इसे दिनांक 29-3-1990 के भारत के
असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित
अधिसूचना का.आ. 266 (ई) दिनांक 22-9-1990 द्वारा
संशोधित किया गया।

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 667.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President after consultation with the Comptroller & Auditor General of India, hereby makes the following further amendment to the Notification of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 2815 dated 13-9-1988 namely:—

In the schedule to the said notification,

(i) in Part-I relating to General Central Services-Group-B;—

(a) at serial number 3 in column 5 before the words ‘Additional Deputy Comptroller and Auditor-General’ the following words shall be inserted, namely:—
“Deputy Comptroller and Auditor-General”

(ii) in Part-II relating to General Central Services—Group-C;—

(a) at item (i) of serial number 3 relating to Section Officers, in column 2 for the words ‘Assistant Comptroller & Auditor-General’ the following words shall be substituted, namely:—

“Senior Deputy Accountants General/Deputy Accountants General/Officers of equivalent rank

in the office of the Comptroller and Auditor General of India”.

[File No. C-11021/2/90-E.G. I]

D. THYAGESWARAN, Under Secy.

NOTE :

1. The principal notification S.O. 2815 dated 13-9-1988 was published in the Gazette of India dated 24-9-1988 at pages 3474 to 3477 in Part-II Section 3(ii).

2. A corrigendum was published in the Gazette of India dated 12-11-1988 at page 4120 vide S.O. 3349 dated 1-11-1988.

3. Subsequently amended by Notification S.O. 266(E) dated 22-2-1990 published in the Extra-ordinary Gazette of India, Part-II, Section 3(ii) dated 29-3-1990.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1991

का.आ. 668.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया कलकत्ता पर 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध गिरवीदार के रूप में मैसर्स बंगाल टूल्स एण्ड इंजीनियरिंग कं. (प्रा.) लिमिटेड, की 30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी धारिता से है।

[संख्या 15/2/91-बी.ओ.-III(i)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 18th February, 1991

S.O. 668.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsection (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period upto the 31 December, 1992 in so far as they relate to its holding of the shares in excess of 30% of the paid up share capital of M/s. Bengal Tools and Engineering Co. (P) Limited, Calcutta, as pledged.

[No. 15/2/91-B.O. III(ii)]

का.आ. 669.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उप धारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कलकत्ता पर 11 मार्च, 1993 तक की और अवधि तक, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में मैसर्स एक्से इलेक्ट्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की 30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी धारिता है।

[संख्या 15/2/91-बी.ओ.-III(ii)]

S.O. 669.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta for a further period upto 11th March, 1993 in respect of its holding of shares in excess of 30% of the paid up share capital of M/s. Acme Electro Industries Private Limited, as pledgee.

[No. 15/2/91-B.O. III (ii)]

का.आ. 670.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता पर 4 नवम्बर, 1992 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक उनका सम्बन्ध गिरवीदार के रूप में सैसर्स निब्रो लिमिटेड की 30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी धारिता से है।

[संख्या 15/2/91-बी ओ-III (iii)]

के.के. मंगल, अवसर सचिव

S.O. 670.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta upto 4th November, 1992 in so far as they relate to its holding of the shares in excess of 30% of the paid up share capital of M/s. Nibro Limited, as pledgee.

[No. 15/2/91-B. O. III (iii)]

K. K. MANGAL, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग)

बम्बई, 13 फरवरी, 1991

का.आ. 671.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (सी) के अन्तर्गण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करें, अर्थात् :—

“दि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अम्बाला शहर, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है” शब्दों के स्थान पर, “दि हरियाणा स्टेट क-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, अम्बाला, चंडीगढ़” शब्द रखे जाएंगे।

[आश्वासन सं. आर./एफ. 696/जे-22/90 91]

कु. आई.टी. वाज, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

Bombay, the 13th February, 1991

S.O. 671.—In pursuance of Clause (C) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alteration shall be made in the Second Schedule to the said Act, namely :—

For the words “THE HARYANA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD., AMBALA CITY with HEAD-QUARTERS at CHANDIGARH” the words “THE HARYANA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD., AMBALA, at CHANDIGARH” shall be substituted.

[RPCD No. RF. 696/J. 22-90/91]

MS. I. T. VAZ, Executive Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1991

का.आ. 672.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाबंध उपाबंध में विनिर्दिष्ट निर्यातों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

उपाबंध में विनिर्दिष्ट 8 नियमों में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नलिखित रूप में निरीक्षण फीस सदत्त की जाएगी :—

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए न्यूनतम 50 रुपये प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से;

(ख) परेषणवार निरीक्षण के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए न्यूनतम 50 रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

(ii) ऐसे विनिर्माताओं/निर्यातकारियों के लिए, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास लघु विनिर्माण एककों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, न्यूनतम 50 रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, उपाबंध (क) और (ख) के लिए दरें क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत होंगी।

उपाबंध

(1)	(2)	(3)	(4)
1. चमकदार मिट्टी की टाइलों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	359	16-2-1980	

1	2	3	4
2. अकार्बनिक वर्णकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2674	1-9-1966	
3. सुरक्षा कांच का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968	2837	21-9-1969	
4. प्रसाधन साबुन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980।	1016	19-4-1980	
5. साईकिल टायरों तथा साईकिल टयुबों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987।	143	17-1-1987	
6. पी.वी.सी. चमड़े के कपड़े का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1981।	49	3-1-1984	
7. सेफ्टी माचिस का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	1221 (ए)	28-3-1984	
8. संश्लिष्ट अपमार्जक का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980।	1024	19-4-1980	

टिप्पण :—“निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए देय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रूप में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहाँ ऐसी रकम में पैसे के रूप में रूप का भाग है वहाँ यदि ऐसा भाग 50 पैसे या उससे अधिक है, वहाँ उसे एक रूप तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा।”

[फाइल सं. 6(26)/86-ई आई एंड ई पी

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th February, 1991

S.O. 672.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the rules specified in the Annexure annexed hereto, namely :—

In the 8 rules specified in the Annexure, for rule 7, the following shall be substituted, namely :—

“7. Inspection Fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) (a) for exports under in-process quality control scheme at the rate of 0.2% of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment;

(b) for exports under consignment wise inspection at the rate of 0.4% of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment.

(ii) subject to minimum of Rs. 50/- per consignment, the rates shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent for sub-clause (a) and (b) respectively for manufacturers-exporters who are registered as small scale manufacturing units with the concerned Governments of States/Union Territories.

ANNEXURE

S.No.	Short Title of the Rule	S.O. No.	Date of publication in the Official Gazette.
1	2	3	4
1.	The Export of Glazed Earthen ware Tiles (Quality Control and Inspection) Rules, 1980	359	16-2-1980
2.	The Export of Inorganic Pigments (Inspection) Rules, 1966	2674	01-09-1966
3.	The Export of Safety Glass (Inspection) Rules, 1969	2837	21-09-1969
4.	The Export of Toilet Soaps (Quality Control and Inspection) Rules, 1980	1016	19-01-1980
5.	The Export of Cycle Tyres and Cycle Tubes (Quality Control and Inspection) Rules, 1987	143	17-01-1987
6.	The Export of Safety Matches (Quality Control and Inspection) Rules, 1984.	1221(A)	28-03-1984
7.	The Export of P.V.C. Leather Cloth (Inspection) Rules, 1981	49	03-01-1981
8.	The Export of Synthetic Detergent (Quality Control and Inspection) Rules, 1980.	1024	19-4-1980

“Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.”

[F. No. 6(26)/86-EI & EP]

का.आ. 673.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाबद्ध उपाबंध में विनिर्दिष्ट नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

i. उपाबंध में विनिर्दिष्ट 26 नियमों में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नलिखित रूप में निरीक्षण फीस संदत्त की जाएगी :—

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए

न्यूनतम 50 रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से—

(ख) परेषणवार निरीक्षण के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए न्यूनतम 50 रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

(ii) ऐसे विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिए, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास लघु विनिर्माण एककों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, न्यूनतम 50 रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, उपखंड (क) और (ख) के लिए दरें क्रमशः 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत होंगी।

उपाबंध

क्र. सं.	नियम का संक्षिप्त नाम	का. आ. सं.	राजपत्र में प्रकाशन की तारीख
1	2	3	4

1.	चीनी-मिट्टी के स्वच्छता उपकरणों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977।	1553	28-5-1977
2.	पार्सिलिन विद्युत रोधक तथा बुश निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979	3757	17-11-1979
3.	अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966।	1271	25-3-1966
4.	कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966।	481	9-2-1966
5.	नाशीकीटमार तथा उनके निरूपणों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970।	3311	7-10-1970
6.	लाउन्ड्री साबुन निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	1772	7-6-1966
7.	रबड़ वैल्टिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	848	13-3-1967
8.	रबड़ की बैल्टों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	80	5-1-1967
9.	रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2154	19-7-1966

1	2	3	4
10.	रबड़ की गर्म पानी की बोतलों का निर्यात (निरीक्षण), नियम, 1966	2459	16-8-1966
11.	रबड़ की बर्फ की थैलियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966।	2216	22-7-1966
12.	विद्युतीय प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973	158	13-1-1973
13.	रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987	309	7-2-1987
14.	क्रोम वर्णक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974।	2429	21-9-1974
15.	मुद्रण स्याही निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	1933	3-8-1974
16.	उष्मसह ईटों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2266	14-6-1966
17.	सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973।	2968	6-10-1973
18.	अल्ट्रापैग्रेन नील निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981	92	10-1-1981
19.	सीमेंट तथा कंकरीट की फर्श की टाइलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1983	3000	30-7-1983
20.	क्राकरी के बर्तनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989	1685	8-7-1989
21.	लिनोनियम का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989	856	22-4-1989
22.	विन्यल फिल्मों तथा चददरो का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989	1133	13-5-1989
23.	रबड़ नम्पनाल निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989।	1683	8-7-1989

1	2	3	4	1	2	3	4
24. वैक्यूम फ्लास्क का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985	4259	14-9-1985		2. The Export of Porcelain Insulator ; & Bushing (Quality Control and Inspection) Rules, 1979	3757	17-11-1979	
25. अवरक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969	268	16-1-1969		3. The Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966	1271	25-3-1966	
26. संरचित अवरक का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983	2953	23-7-1983		4. The Export of Organic Chemicals (Inspection) Rules, 1966	481	09-02-1966	

टिप्पण :

“निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए देय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रूप में पूर्णकृत की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में पैसों के रूप में रूप का भाग है वहां यदि ऐसा भाग 50 पैसे या उससे अधिक है, वहां उसे एक रूप तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा।”

[फाइल सं. 6 (26)-86-ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 673.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the rules specified in the Annexure annexed hereto, namely :—

1. In the 26 rules specified in the Annexure, for rule 6, the following shall be substituted, namely :—

“6 Inspection fee :—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) (a) for exports under in-process quality control scheme at the rate of 0.2% of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment ;

(b) for exports under consignment wise inspection at the rate of 0.4% of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment.

(i) subject to a minimum of Rs. 50/- per consignment, the rates shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent for sub-clause (a), and (b) respectively for manufacturers-exporters who are registered as small scale manufacturing units with the concerned Governments of State/Union Territories.

ANNEXURE

S. No.	Short title of the rule	S.O. No.	Date of publication in the official Gazette
--------	-------------------------	----------	---

1	2	3	4
1.	The Export of Ceramic Sanitary Appliance (Quality Control and Inspection) Rules, 1977	1553	28-05-1977

2.	The Export of Porcelain Insulator ; & Bushing (Quality Control and Inspection) Rules, 1979	3757	17-11-1979
3.	The Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966	1271	25-3-1966
4.	The Export of Organic Chemicals (Inspection) Rules, 1966	481	09-02-1966
5.	The Export of Pesticides and their formulations (Inspection) Rules, 1970	3311	07-10-1970
6.	The Export of Laundry Soap (Inspection) Rules, 1966	1772	07-06-1966
7.	The Export of Rubber Beltings (Inspection) Rules 1967	848	13-3-1967
8.	The Export of Rubber Belts (Inspection) Rules, 1967	80	05-01-1967
9.	The Export of Rubber Gloves (Inspection) Rules, 1966	2154	19-07-1966
10.	The Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection), Rules, 1966	2459	16-08-1966
11.	The Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Rules, 1966	2216	22-07-1966
12.	The Export of Rubber Gloves for Electrical Purpose (Inspection) Rules, 1973.	158	13-01-1973
13.	The Export of Paints & Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987.	309	07-02-1987
14.	The Export of Chrome Pigments (Quality Control and Inspection) Rules, 1974	2429	21-09-1974
15.	The Export of Printing Inks (Quality Control and Inspection), Rules, 1974	1933	03-08-1974
16.	The Export of Refractory Bricks (Inspection) Rules, 1966	2266	14-06-1966
17.	The Export of Sulphuric Acid (Inspection) Rules, 1973	2968	6-10-1973
18.	The Export of Ultramarine Blue (Quality Control and Inspection) Rules, 1981.	92	10-01-1981
19.	The Export of Cement Concrete Flooring Tiles (Inspection) Rules, 1983	3000	30-07-1983
20.	The Export of Crockeryware (Quality Control and Inspection) Rules, 1989	1685	08-07-1989
21.	The Export of Linoleum (Quality Control and Inspection) Rules, 1989	856	22-04-1989
22.	The Export of Vinyl Films and Sheetting (Quality Control and Inspection) Rules, 1989	1133	13-05-1989

1	2	3	4
23.	The Export of Vacuum Flask (Quality Control and Inspection) Rules, 1985	4259	14-09-1985
24.	The Export of Mica (Inspection) Rules, 1969	263	16-01-1969
25.	The Export of Fabricated Mica (Quality Control and Inspection) Rules, 1983	2953	23-07-1983
26.	The Export of Rubber Hoses (Quality Control and Inspection) Rules, 1989	1683	08-07-1989

"Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 6(26)/86-EL&EP]

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.आ. 674.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जे. बी. वोटा सर्वोयर्स प्राइवेट लिमिटेड, रघु बिल्डिंग (पहली मंजिल) 10 मैंगलौर-57 5006 को इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण खनिज तथा अयस्क के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के उपनियम (4) के अन्तर्गत उक्त निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मनोनित किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

1. मैंगनीज डायक्साइड कच्चा मैंगनीज
2. कच्चा लोहा।
3. क्रोम अयस्क, क्रोम चूर्ण रहित।

[फाइल सं. 5/15/(88)-ई आई एण्ड ई पी]

New Delhi, the 19th February, 1991

S.O. 674.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognised for a period of three years from the date

of publication of this notification M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., Reghu Building (1st floor) Mangalore-575006 as an agency for the inspection of Mineral & Ores specified in the schedule annexed hereto prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the export Minerals & Ores (Inspection) Rules, 1965.

SCHEDULE

1. Manganese Ore, excluding manganese dioxide.
2. Iron Ore.
3. Chrome Ore, including chrome concentrates.

[F. No. 5(15)/88 FI&EP]

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का. आ. 675.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेस लि., एफ-2/2 गिल्लंडर हाउस 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700001 को स्टील ट्रंक के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण स्टील ट्रंक के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 के नियम 4 के उपनियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मनोनित किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल संख्या 5/7/90-ई.आई.एण्ड ई.पी.पार्ट I]

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 675.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., F-2/2 Gillander House, 8 Netaji Subhash Road, Calcutta-700001, as an agency for the inspection of Cast Iron Manhole Cover & Frames prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub rule (4) of rule 4 of the Export of Cast Iron Manhole Cover & Frames (Inspection) Rules, 1971.

[F. No. 5/7/90-EI & EP Part I]

का. आ. 676.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लि., एफ-2/2, गीलेन्डर हाऊस 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 700001 को हले हुए लोहे के मेन होल के टक्कनों तथा फ्रेमों के निर्यात पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अधिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अधिकरण हले लोहे के मेन होल के टक्कनों तथा फ्रेमों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 के नियम 4 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिपद्द द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल सं. 5/7/90—ई आई एण्ड ई पी Part-I]

S.O. 676.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., F-2/2 Gillander House 8, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001, as an agency for the inspection of Steel Trunks prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Steel Trunks (Inspection) Rules, 1967.

[F. No. 5/7/90-EI&EP Part-I]

का. आ. 677.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नालोजी एण्ड इकोनोमिक सर्विस लि. एफ-2/2, गीलेन्डर हाऊस 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 को हले हुए लोहे के मल नाल फिटिंग्स का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अधिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अधिकरण हले लोहे के मल नालों तथा फिटिंग्स का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 के नियम 4 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिपद्द द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल सं. 5/7/90—ई.आई.एण्ड ई पी Part-I]

S.O. 677.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., F-2/2 Gillander House 8, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001, as an agency for the inspection of Cast Soil Pipes & Fittings prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Cast Iron Soil Pipes & Fittings (Inspection) Rules, 1971.

[F. No. 5/7/90-EI&EP-Part-I]

का. आ. 678.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लि. एफ 2/2, गीलेन्डर हाऊस, 8 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 को विस्तारित मेटल स्टील की चद्दरों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अधिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अधिकरण विस्तारित मेटल स्टील की चद्दर का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 के नियम 4 के उप नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अधिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति को जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिपद्द द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल संख्या 5/7/90—ई आई एण्ड ई पी (भाग I)]

S.O. 678.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical and Economic Services Ltd., F-2/2, Gillander House, 8, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001, as an agency for the inspection of Expanded Metal Steel Sheets prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Expanded Metal Steel Sheets (Inspection) Rules, 1967.

[F. No. 5/7/90-EI&EP-Part-I]

का. आ. 679.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लि., एफ. 2/2, गीलेन्डर हाऊस, 8 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 7000001 को इससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट लघु अभियांत्रिक उत्पाद के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों

के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण लघु अभियांत्रिक उत्पाद के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के नियम 4 के उप नियम (5) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिपद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

1. घरेलू सामान

1. पीतल के बर्तन
2. बलो लैम्प बर्नर सहित
3. ताबों के बर्तन
4. नरम इस्पात की बाल्टियां
5. तेल के दबाव वाले स्टोव, बर्नर सहित
6. तेल के दबाव वाले लानटर्न
7. कैंची
8. छाता
9. बगीचा/सर्वेक्षण/बीच/पिकनिक/छाता प्रसार के ताले

2. इमारती लोहे का सामान

1. दरवाज के ताले, अलमारी के ताले, बक्से, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियों के ताले, तथा ग्रीफ केम के ताले
2. बाड़ लगाने के लिए जस्तेदार, स्टील, कांटेदार तार
3. तसले
4. कब्जे
5. नरम स्टील तार के कील
6. माटिम ताले (वार्टिकल टाइप)
7. पेडलाक
8. ताले सहित इस्तेमाल होने वाले सरकवां दरवाजे के बोल्टस
9. चटखनियां
10. तार की जाली

3. छुरी कांटे

1. कांटे
2. चाकू
3. चम्मच

[फा.सं. 5/7/90-ई आई एण्ड ई पी-भाग 1]

S.O. 679.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., F-2/2 Gillander House, 8 Netaji Subhash Road, Calcutta-700001, as an agency for the inspection of Light Engineering Products specified in the Schedule annexed hereto prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (5) of rule 4 of the Export of Light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976.

SCHEDULE

I. HOUSE HOLD ARTICLES

1. Brass Utensils
2. Blow Lamp including burner.
3. Copper Utensils
4. Mild steel buckets.
5. Oil Pressure Stove, including burner.
6. Oil Pressure lantern.
7. Scissors.
8. Umbrellas
9. Garden/Survey/Beach/Picnic/Publicity Umbrella.

II. BUILDING HARDWARE :

1. Drawer locks, cuboard locks, box locks, suitcase locks, Portfolio locks and brief case locks.
2. Galvanised steel barbed wire for fencing
3. Chemicals.
4. Hinges.
5. Mild steel wire nails.
6. Mortise locks (vertical type)
7. Padlocks
8. Sliding door belts for use with Padlocks.
9. Tower bolts
10. Wire gauge.

III. CUTLERY:

1. Forks
2. Knives
3. Spoons

[F. No. 5/7/90-EI&EP-Part-I]

का. आ. 680.—केंद्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेमर्स रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस लि., सी-1 कम्युनिटी सेंटर, आई आई टी गेट के सामने एम. डी. एग्गिया, नई दिल्ली-110016 को देने हुए, लोहे के मल नाल तथा फिटिंग्स का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन

की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण ढले हुए लोहे के मल नालों तथा फिटिंग का निर्यात निरीक्षण) नियम, 1971 के नियम 4 के उप नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल सं. 5/7/90-ई आई एंड ई पी]

S.O. 680.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., C-1, Community Centre, Opposite I.I.T. Gate, S.D. Area, New Delhi-110016 as an agency for the inspection of Steel Trunks prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Steel Trunks (Inspection) Rules, 1967.

[F. No. 5/7/90-EI&EP]

का. आ. 681.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल, एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेस लि., सी-1 कम्युनिटी सेंटर, आई. आई. टी. गेट के सामने एस. डी. एरिया, नई दिल्ली-110016 को ढले हुए लोहे के मैन होल के टैक्कनों तथा फ्रेमों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण ढले हुए लोहे के मैन होल के टैक्कनों तथा फ्रेमों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971 के नियम 4 के उपनियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाणपत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करके के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फा. सं. 5 7/90-ई आई एंड ई पी]

S.O. 681.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical and Economic Services Ltd., C-1, Community Centre, Opposite I.I.T. Gate, S.D. Area, New Delhi-110016 as an agency for the inspection of Expanded Metal Steel Sheets prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub rule (4) of rule 4 of the Export of Expanded Metal Sheets (Inspection) Rules, 1967.

[F. No. 5/7/90-EI&EP]

का. आ. 682.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेस लि., सी-1 कम्युनिटी सेंटर, आई. आई. टी. गेट के सामने एस. डी. एरिया, नई दिल्ली-110016 को स्टील ट्रंक के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण स्टील ट्रंक के निर्यात (निरीक्षण) नियम 1967 के नियम 4 के उप नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल सं. 5 / 7 / 90-ई आई एंड ई पी]

S.O. 682.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., C-1, Community Centre, Opposite I.I.T. Gate, S.D. Area, New Delhi-110016 as an agency for the inspection of Cast Iron Manhole Covers & Frames prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub rule (4) of rule 4 of the Export of Cast Iron Manhole Covers & Frames (Inspection) Rules, 1971.

[F. No. 5/7/90-EI&EP]

का. आ. 683.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेस लि., सी-1 कम्युनिटी सेंटर, आई. आई. टी. गेट के सामने एस. डी. एरिया, नई दिल्ली-110016 को विस्तारित मेटल स्टील की चद्दरों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण विस्तारित मेटल स्टील की चद्दर का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1967 के नियम 4 के उप नियम (4) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

[फाइल सं. 5 / 7 / 90-ई आई एंड ई पी]

S.O. 683.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Services Ltd., C-1, Community Centre, Opposite

L.T. Gate, S.D. Area, New Delhi-110016 as an agency for the inspection of Cast Iron Manhole Covers & Frames prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub rule (4) of rule 4 of the Export of Cast Iron Soil Pipes Fitting (Inspection) Rules, 1971.

[F. No. 5/7/90-EI&EP]

का. आ. 684—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेस लि., सी-1 कम्यूनिटी सेंटर, आई. आई. टी. गेट के सामने एस. डी. एरिया, नई दिल्ली - 110016. को इससे उपाबध अनुसूची में विनिर्दिष्ट लघु अभियांत्रिक उत्पाद के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण लघु अभियांत्रिक उत्पाद के नियम (निरीक्षण) नियम, 1976 के नियम 4 के उप नियम (5) के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई प्रवृत्ति की जाच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिपद द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

I. घरेलू सामान

1. पीतल के पर्वन
2. बलो लेम्प बर्नर सहित
3. ताबों के बर्तन
4. नरम इस्पात की बाल्टियां
5. तेल के दबाव वाले स्टोव, बर्नर सहित
6. तेल के दबाव वाले लालटेन
7. कैंची
8. छाता
9. बगीचा सर्वेक्षण / बीच / पिकनिक / प्रचार छाता

II. हमारती लोहे का सामान

1. दराज के ताले, अलमारी के ताले, बक्से के ताले, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियों के ताले, तथा ब्रीफ केस के ताले,
2. बाड़ लगाने के लिए अस्तेदार स्टील, कांटेदार तार
3. तसले
4. कब्जे
5. नरम स्टील तार के कील
6. मार्टिस ताले, (वार्टिकल टाईप)
7. पैंडलाक

8. ताले सहित इस्तेमाल होने वाले सरकलों दरवाजे के बोल्ट्स

9. चटखनियां

10. तार की जाली

III. छुरी काटे

1. काटे

2. चाकू

3. चम्मच

[फा. सं. 5/7/90-ई आई एण्ड ई पी]

ए. के. चौधुरी, निदेशक

S.O. 684.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years from the date of publication of this notification M/s. Rail India Technical & Economic Service Ltd., C-1, Community Centre, Centre, Opposite L.T. Gate, S.D. Area, New Delhi-110016 as an agency for the inspection of Light Engineering Products specified in the Schedule Annexured here to prior to export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub rule (5) of rule 4 of the Export of Light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976.

SCHEDULE

I. HOUSE HOLD ARTICLES :

1. Brass Utensils
2. Blow Lamp including burnor
3. Copper Utensils
4. Mild steel buckets
5. Oil pressure stove, including burner
6. Oil pressure lantern
7. Scissors
8. Umbrellas
9. Garden/Survey/Beach/Picnic/Publicity Umbrella.

II. BUILDING HARDWARE :

1. Drawer locks, cupboard locks, box locks, suitcase locks, Portfolio locks and brief case locks.
2. Galvanised steel barbed wire for fencing
3. Ghamellas
4. Hinges
5. Mild steel wire nails
6. Mortise locks (vertical type)
7. Padlocks
8. Sliding door belts for use with Padlocks
9. Tower bolts.
10. Wire gauge.

III. CUTLERY:

1. Forks
2. Knives
3. Spoons

[F. No. 5/7/90-EI&EP]

A. K. CHAUDHURI, Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1991

का. आ. 685:—मैसर्स एम ए एम सी लिमिटेड, दुर्गापुर-पश्चिम बंगाल 7113210 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत संघटको अतिरिक्त पर्जों के आयात के लिए 20,83,892 का सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या पी/1/3080278 दिनांक 20-11-90 मंजूर किया गया था।

2. फर्म ने ऊपर उल्लिखित सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है जो कि उनसे गुम हो गया खो गया है। यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करण बिना और उपयोग कि बिना ही खो गया है।

3. अपनी दलील के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, कलकत्ता के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत रूप में शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार में संतुष्ट हूँ तथा यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 के उप-खण्ड 9 (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एम ए एम सी लिमिटेड को जारी किए गए उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/3080278 दिनांक 20-11-90 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

4. इस फर्म को सीमाशुल्क से माल की निकासी करने की दृष्टि से उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को जारी की जा रही है।

[फाईल सं. सुप्लिमेन्ट्री एन एस- 2/58 डी जी टी डी / ए एम 91 / एस एल एस]

(Office of the Chief Controller of Import and Exports)

New Delhi, the 18th February, 1991

S.O. 685.—M/s. MAMC Ltd. Durgapur, West Bengal 713210, were granted Custom clearance Permit No. P/J/3080278 dt. 20-11-90 for Rs. 20,83,892 for import of components/spares under G.C.A.

2. The firm has applied for issue of duplicate G.C.P. of the above mentioned C.C.P. which has been lost/misplaced by them. It has further been stated that C.C.P. has been lost without having been registered with any Customs Authority and without utilised at all.

3. In support of their contention, the licence has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public of Calcutta. I am, accordingly satisfied and in exercise of the power conferred on me under Sub-Clause 9(d) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-65 as amended that the said original C.C.P. No. P/J/3080278 dated 20-11-1990 issued to M/s. MAMC Ltd. is hereby cancelled.

4. In order to enable this firm to clear the goods from Customs duplicate C.C.P. of the said licence is being issued to the party.

[F. No. Suppl/NS-2/58/DGTD/AM.91/SLS]

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

का. आ. 686:—मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज-पेपर्स (बम्बई) प्रा. लि., एक्सप्रेस टावर, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति-बन्धित स्पेयर्स के आयात के लिए 8,99,000 रुपए (आठ लाख नित्यानवे हजार रुपये मात्र) का आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2276422 दिनांक 6 मार्च, 1989 दिया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल विनियम नियंत्रण प्रति कहीं गुम हो गई है या कहीं अन्यत्र रख दी गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की विनियम नियंत्रण प्रति स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई के पास पंजीकृत कराई हुई थी और इसलिए उपर्युक्त लाइसेंस का आंशिक रूप में उपयोग किया गया था।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक बम्बई के समक्ष विधिवत रूप में शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार में संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस की मूल विनियम नियंत्रण मुद्रा प्रति सं. पी डी /2276422 दिनांक 6-3-89 फर्म से गुम हो गई है। कहीं अन्यत्र रख दी गई है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (ग ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज-पेपर्स (बम्बई) प्रा. लि., बम्बई को जारी की गई उक्त मूल विनियम नियंत्रण प्रति सं. पी डी 2276422 दिनांक 6-3-89 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

4. मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सप्ली. एन एस-13 1355 / जी टी डी / ए एम- 89/डी एस एल एस /994]

अनिता पठेजा, (उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1991

S.O. 686.—M/s. Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt. Ltd., Express Tower, Nariman Point, Bombay-400021 were granted an import licence No. P/D/2276422 dated 6th March, 1989 for Rs. 8,99,000/- (Rupees eight lakh and ninety nine thousand only) for import of restricted spares under G.C.A.

2. The firm has applied for issue of Duplicate Copy of Exchange Control Copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the

licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange Control Copy of the licence was registered with State Bank of India, Bombay and as such the value of above mentioned licence has been utilised partly.

3 In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bombay. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of import licence No. P/D/226422 date 6-3-89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the

Import (Control) Order, 1955 date 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Copy No. P/D/2276422 dt 6-3-89 issued to M/s Indian Express Newspaper (Bombay) Pvt Ltd, Bombay is hereby cancelled

4 A duplicate Exchange Control Copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. Suppl/NS-13/1355/DGID/AM-89/SLS/994]

ANITHA PATHEJA, Dy Chief Controller of Imports & Exports

पेट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय

नई दिल्ली 8 फरवरी, 1991

का. आ. 687.—जब केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्केजिनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच. बी. जे. पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत मोरि I से जि. सि. एम. नगरम तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के जि. प्रोजेक्ट भूमेकरणा, कार्यालय, राजमद्रि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निदिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिव्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

आर. ओ. ए. पाइप लाइन मोरि I से जि. सि. एम. नगरम

स्टैंड : आन्ध्र प्रदेश

मंडल : मामिडि कुदुरु

जिला : पुरब गोदावरी

गांव	एम नं.	हेक्टेर्स	एस	सेन्टिधर्स	एकर्स	सेन्ट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोदवाडा	123—ए	0	03	0	0	07
	122—4-ए	0	02	0	0	05
	122—4-बी	0	05	5	0	13
	109—1	0	01	0	0	02
	109—2	0	00	5	0	01
	109—3	0	00	5	0	01
	108—2	0	01	0	0	02
	107—ए	0	03	0	0	07
	106—4-ए } 3—ए	0	11	5	0	29
	104—ए	0	32	0	0	79
	135—1-ए } 2—ए 2—बी } 138—ए	0	21	0	0	52

1	2	3	4	5	6	7
	136—3ए	0	16	0	0	40
	4ए					
	136—1ए } 141—4ए }	0	14	5	0	36
	137—1ए } 2ए }	0	14	5	0	36
	141—4 बी	0	04	5	0	11
कुल मिलाकर		1	30	5	3	21

[सं. ओ -11027/2/91-ओ./ऐन. जी. डी.-III]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 8th February, 1991

S.O. 687.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from MORI-I to G.C.S. NAGARAM in A.P. State Pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mine-

ral pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, K.G. Project, Rajahmundry, (533103).

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. pipe line from MORI-I to G.C.S. NAGARAM

State : Andhra Pradesh.

Mandal : Mamidikuduru

District : East Godavari

Name of the Village	R.S.No.	Hectars	Ares	Centiares	Acres	Cents.
GEDDADA	123—A	0	03	0	0	07
	122—4A	0	02	0	0	05
	122—4B		05	5	0	13
	109—1	0	01	0	0	02
	109—2	0	00	5	0	01
	109—3	0	00	5	0	01
	108—2	0	01	0	0	02
	107—A	0	03	0	0	07
	106—4A } 3A }	0	11	5	0	29
	104—A	0	32	0	0	79
	135—1A } 2A }	0	21	0	0	52
	2B					
	138—A					
	136—3A } 4A }	0	16	0	0	40

1	2	3	4	5	6	7
	136—1A]	—	—	—	—	—
	141—4A]	0	14	5	0	36
	137—1A]	—	—	—	—	—
	2A]	0	14	5	0	36
	141—4B	0	04	5	0	11
Grand Total		1	30	5	3	21

[No. O-11027/2/91-ONG.D.III]

का. आ. 688.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ. ओन. जी. सी. गैस टर्मिनल सं. गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसर्विंग स्टेशन अदजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड सुरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें नए उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना इरादा एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हाजीर प्रोजेक्ट, 60, सुभाष नगर सोसाइटी घोडादौड़ रोड, सुरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाईप लाइन ओ एन जी सी गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लि. अदजन तक

राज्य : गुजरात

जिला : सुरत

तालुका : चौरसी

गांव	वार्ड नं.	क्षेत्रफल
भाटा	तापी नदी	5 33 60
	603	0 03 52
	602	0 20 80
	597	0 14 00
	सरकारी मार्ग	0 03 60
	598	0 07 60
	599	0 14 00
	592	0 24 60
	589	0 30 40
	591	0 02 00
	588	0 00 77
	587	0 00 40
	586	0 00 60
	605	0 54 40
	43	0 16 20

S.O. 688.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60, Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Gas terminal to Gujarat Gas Company Limited Receiving Station at Adajan

State : Gujarat		District : Surat.		Taluka : Chorasi	
Village	Block No.	H.	Are.	Parti Are.	
BHATHA	Tapi River	5	33	60	
	603	0	03	52	
	602	0	20	80	
	597	0	14	00	
	Govt. Road	0	03	60	
	598	0	07	60	
	599	0	14	00	
	592	0	24	60	
	589	0	30	40	
	591	0	02	00	
	588	0	00	77	
	587	0	00	40	
	586	0	00	60	
	605	0	54	40	
	43	0	16	20	

[No.O-11027/1/91-ONG.D.III]

एस. ओ. 689.—जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच. बी. जे पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पैरवलि में कोब्रु तक तेल और सहज वायु आयोग द्वारा बिछाया जाना है और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकारी ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद्वारा उसे पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के जी. प्रोजेक्ट, भूसेकरणा, कार्यालय, राजमुद्रि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

बोर्डपूस

कार, ओ. ए. पाइप लाइन परवली से कोव्वूर तक ।

स्टेट : आंध्र प्रदेश; जिला : पश्चिम गोदावरी; मंडल : निदावोलु

गाँव	आवश्यक. नं.	हेक्तास	एस*	सेन्टिएस	एकड़	सेन्ट्स
1	2		4	5	6	7
विज्जेश्वरम	11/2	0	35	0	0	86
	10/1	0	15	0	0	37
	10/2	0	10	5	0	26
	10/3	0	03	5	0	09
	7/1	0	14	0	0	34
	7/2	0	04	5	0	11
	7/3	0	06	0	0	15
	7/4	0	03	0	0	08
	4/1	0	05	5	0	14
	4/2	0	29	5	0	72
	1	0	09	0	0	22
कुल मिलाकर		1	35	5	3	34

[सं. ओ-11027/3/91- ओ एन जी-डी.-III]

S.O. 689.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from PERAVALI to KOVVURU in A.P. State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act,

1962 the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, K.G. Project, Rajahmundry, (533103).

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. Pipe line from PERVALI to "KOVVURU"

State : Andhra Pradesh

District West Godavari.

Mandal : Nidadavolu

Village	R.S.No.	Hectars	Ares	Centiares	Acres	Cents
1	2	3	4	5	6	7
VIJESWARAM	11/2	0	35	0	0	86
	10/1	0	15	0	0	37
	10/2	0	10	5	0	26
	10/3	0	03	5	0	09
	7/1	0	14	0	0	34
	7/2	0	04	5	0	11
	7/3	0	06	0	0	15
	7/4	0	03	0	0	08
	4/1	0	05	5	0	14
	4/2	0	29	5	0	72
	1	0	09	0	0	22
Total		1	35	5	3	34

[No. O-11027/3/91-ONG.D.III]

का.आ. 690.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच. बी. जे. पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरवलि से कोव्वुरु तक तेल और सहज वायु आयोन द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है।

बनते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के. जि. प्रोजेक्ट, भूसेकरणा, कार्यालय, राजमूंद्री, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से प्रपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

अनुसूची

भार. ओ.यू. पाइप लाइन पेरवलि से कोव्वुरु

राज्य : आन्ध्र प्रदेश

जिला पश्चिम : गोवावरि; मंडल निरुदवोलु

गांव	भार एस नं.	हेक्टेर्स	एर्स	सेन्टियर्स	एकर्स	सेग्ट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोपवरम	164	0	20	0	0	50
	165/1	0	05	0	0	12
	165/2	0	02	0	0	05
	165/3	0	10	0	0	25
	166/1	0	12	0	0	30
	166/2	0	02	5	0	06
	166/3	0	20	0	0	50
	166/4	0	01	0	0	02
	166/5	0	01	0	0	03
	166/6	0	02	0	0	05
	370/1	0	07	5	5	18
	170/2	0	05	5	0	14
	170/3	0	21	5	0	53
	169/1	0	05	5	0	13
	167/1	0	16	5	0	41
	167/2	0	03	0	0	07
	100	0	23	0	0	57
	95	0	38	5	0	95
	94	0	03	0	0	07
	49 112	0	28	0	0	69
	50	0	31	0	0	76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	93 1	0	11	0	0	27
	93 2	0	07	5	0	19
	93 3	0	06	0	0	15
	92	0	23	0	0	57
	91	0	03	0	0	07
	90,114	0	28	5	0	71
	90/3	0	09	0	0	22
	85	0	13	0	0	32
	86	0	21	5	0	53
	88	0	01	5	0	04
कुल मिलाकर		3	82	5	9	45

[सं. ओ.-11027/4/91-ओ एन जी डी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 690.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from PERAVALI to KOVVURU in A.P. State Pipe line should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the land)

Act, 1962 the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, K.G. Project, Rajahmundry (533103).

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. Pipe line from Peravali to KOVVURU

State : Andhra Pradesh; District : West Godavari; Mandal : Nidadavolu

Village	R.S.No.	Hectars	Ares	Centiares	Acres	Cents
1	2	3	4	5	6	7
GOPAVARAM	164	0	20	0	0	50
	165/1	0	05	0	0	12
	165/2	0	02	0	0	05
	165/3	0	10	0	0	25
	166/1	0	12	0	0	30
	166/2	0	02	5	0	06
	166/3	0	20	0	0	50
	166/4	0	01	0	0	02
	166/5	0	01	0	0	03
	166/6	0	02	0	0	05
	170/1	0	07	5	0	18
	170/2	0	05	5	0	14
	170/3	0	21	5	0	53
	169	0	05	5	0	13
	167/1	0	16	5	0	41
	167/2	0	03	0	0	07

1	2	3	4	5	6	7
	100	0	23	0	0	57
	95	0	38	5	0	95
	94	0	03	0	0	07
	49/112	0	28	0	0	69
	50	0	31	0	0	76
	93/1	0	11	0	0	27
	93/2	0	07	5	0	19
	93/3	0	06	0	0	15
	92	0	23	0	0	57
	91	0	03	0	0	07
	90/114	0	28	5	0	71
	90/3	0	09	0	0	22
	85	0	13	0	0	32
	86	0	21	5	0	53
	88	0	01	5	0	04
Grand Total		3	82	5	9	45

[No. O-11027/4/91-ONG D.III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1991

का. आ. 691. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का. आ. 2004 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के लिए आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, राजमुंद्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे. नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा	तीम्मापुरम	85 2	0.107	
			84	0.178	

(4)	(5)	
83/1	0.036	
83/2	0.093	
82/2	0.107	
114	0.143	
84	0.157	
118	0.004	
119	0.142	
120	0.178	
121/A/6	0.171	
190	0.249	
291	0.250	
450	0.180	
339	0.200	
452	0.049	
453	0.250	
454	0.250	
455	0.219	
214	0.049	
290	0.250	
कुल	3,433	हेक्टर्स

[सं. प्रो-14016 4690-जी पी]

New Delhi, the 11th February, 1991

S.O. 691.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals department of Natural Gas S.O. 2004 dated 13-7-90 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (J) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Tatipaka—Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
East Godavari	Kakinada	Thimmapuram	85/22	0.107	
			84	0.178	
			83/1	0.036	
			38/2	0.093	

1	2	3	4	5	6
			82/2	0.107	
			114	0.143	
			84	0.157	
			118	0.004	
			119	0.142	
			120	0.178	
			121/A/6	0.171	
			122	0.171	
			190	0.249	
			291	0.250	
			450	0.180	
			359	0.200	
			452	0.049	
			453	0.250	
			454	0.250	
			455	0.219	
			214	0.049	
			290	0.250	
			Total	3.433 Hect.	

[No. O-14016/46/90-GP]

का.प्र. 692.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का.प्र. 2005 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्दी में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा	पंहुलू	382	0.099	
			358	0.099	
			359	0.121	
			376	0.449	

116	0.319
383	0.150
401	0.250
402	0.449
400	0.059
399	0.099
397	0.299
393	0.250
318	0.370
429	0.450

कुल	3.463	हेक्टे
-----	-------	--------

कुल	3.463	हेक्टे.
-----	-------	---------

[सं.श्री.-14016/47/90-जी.पी.]

S.O. 692.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals Department of Natural Gas S.O. 2005 dated 13-7-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godavari	Kakinada	Punduru	382	0.099	
			358	0.099	
			359	0.121	
			376	0.449	
			416	0.319	
			383	0.150	
			401	0.250	
			402	0.449	
			400	0.059	
			399	0.099	
			397	0.299	
			393	0.250	
			318	0.370	
			429	0.450	
			Total	3.463 Hect.	

[No. O-14016/47/90-GP]

का.ग्रा. 693—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का.ग्रा. 2006 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आणय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा	तम्मवरम	1	0.588	
			2	0.039	
			7	0.499	
			67	0.082	
			69	0.269	
			कुल	1.447	हेक्टे

[सं. ओ-14016/48/90-जी पी]

S.O. 693.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals department of Natural Gas S.O. 2006 dated 13-7-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act) 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Tatipaka—Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godavari	Kakinada	Thammavaram	1	0.588	
			2	0.039	

7	0.499
67	0.082
69	0.269

Total 1.447 Hect.

[No. O-14016/48/90-GP]

का.आ. 694.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कैमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का.आ. 2007 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची हटाने के विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा	नेमम	122	0.299	
			124	0.249	
			126	0.150	
			127	0.200	
			230	0.080	
			235	0.369	
			224	0.109	
			222	0.120	
			242	0.569	
			291	0.200	
			293	0.349	
			298	0.249	
			297	0.050	
			कुल	2.993	हेक्कटे

[सं.प्रो.-14016/49/90-जी पी]

S.O. 694.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals department of Natural Gas S.O. 2007 dated 13-7-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act) 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Tatipaka—Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./Acres)	Remarks
East Godavari	Kakinada	Nemam	122	0.299	
			124	0.249	
			126	0.150	
			127	0.200	
			230	0.080	
			235	0.0369	
			224	0.109	
			222	0.120	
			242	0.569	
			291	0.200	
			293	0.349	
			298	0.249	
			297	0.050	
			Total	2.993 Hect.	

[No. O-14016/49/90-GP]

का.ग्रा. 695.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का.ग्रा. 2008 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी अफ इंडिया लिमिटेड, राजमुन्द्री में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	सामिलकोट	गंचिला	25	0.021	
			24	0.071	
			61	0.321	
			62	0.121	
			23	0.114	
			23/1	0.040	
			22	0.221	
			13	0.036	
			16	0.046	
			15	0.053	
			17	0.245	
			19	0.036	
			18	0.285	
			02	0.057	
			कुल	1.987	हेक्टे

[सं. ओ. 14016/50/90 जी. पी.]

S.O. 695.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals department of Natural Gas S.O. 2008 dated 13-7-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act) 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE
TATIPAKA—KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godavari	Samalkot	Gonchala	25	0.021	
			24	0.071	
			61	0.321	
			62	0.121	
			23	0.114	
			23/1	0.040	
			22	0.221	
			13	0.036	
			16	0.046	
			15	0.053	

17	0.245
19	0.036
18	0.285
02	0.057

Total 1.987 Hect.

[No. O-14016/50/90-GP]

कां.आ. 696—अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962) 1962 का 50 का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना कां. आ. 2009 तारीख 13-7-1990 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में भूमियों में उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय गैस अक्विटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड राजमुन्दी में सभी बाधाओं में मुक्त रूप से घोषणा के प्रकथन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे० एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	मार्मालकोट	अच्छपेठा	133	0.279	
			134	0.264	
			135	0.157	
			162	0.178	
			71	0.264	
			57	0.028	
			58	0.335	
			59	0.036	
			कुल	1.541	हेक्टे.

[स.ओ.-14016/51/90-जी पी]

S.O. 696—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, Department of Natural Gas S.O. 2009 dated 13-7-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act) 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And, whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

TATIPAKA—KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/Acres)	Remarks
East Godavari	Samal Kot	Atochampeta	133	0.279	
			134	0.264	
			135	0.157	
			162	0.178	
			71	0.264	
			57	0.028	
			58	0.335	
			59	0.036	
			Total	1.541 Hect.	

[No. O-14016/51/90-GP]

का. आ. 697—यतः नेट्रोलीयम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और कौमिकल्स मंत्रालय, प्राकृतिक गैस विभाग की अधिसूचना का. आ. 739 (ई) तारीख 24-9-90 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अपना आणव्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड राजमन्द्री में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट/एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी	तातिपाका	वाक्तापूडि	249	0.299	
			239	0.049	
			236	1.049	
			250	0.519	
			272	0.599	
			271	0.699	

	4	5
	270	0.659
	269	0.499
	268	0.699
	267	0.239
	कुल	5.310 हेक्टे.

[मं. ओ- 14016/52/90-जी पी]

S.O. 697.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals, Department of Natural Gas S.O. 739(E) dated 24-9-90 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act) 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And, whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

TATIPAKA—KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godavari	Kakinada	Vakalpudi	249	0.299	
			239	0.049	
			236	1.049	
			250	0.519	
			272	0.599	
			271	0.699	
			270	0.659	
			269	0.499	
			268	0.699	
			267	0.239	
			Total	5.310 Hect.	

[No. O-14016/52/90-GP]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 698 ———निम्नलिखित अनुसूची में रकाना 1 में 6 में लिखे हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की अधिसूचना न. का. आ. 2004 तारीख 13-07-1990 भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपबन्ध (ii) तारीख 28-7-90 पृष्ठ 3419 तारीख द्वारा अधिसूचना की प्रत्यूची में दृष्ट है। इसके निम्नलिखित अनुसूची रकाना 7 में 12 में लिखे हुए शब्दों और संख्या को पठना।

प्रसारित किया गया वर्णन

अ. न.	गांव का नाम	मंडल	जिला	सं. नं.	क्षेत्र हे आर
1	2	3	4	5	6
1.	निम्मापूरम	काकिनाड	ईस्ट गोदावरी	85/2	0.107
				84	0.157
				83/1	0.036
				83/2	0.093
				83/2	0.107
				-इ-	-इ-
				114	0.143
				-इ-	-इ-
				121/ए/6	0.171
				122	0.171
				190	0.249
				214	0.049
				290	0.250
				291	0.250
				349	0.049
				मेन रोड)	
				450	0.180
				359	0.200
				452	0.049
				453	0.250
				454	0.250
				455	0.219

अ.नं.	गांव का नाम	मंडल	जिला	सं.नं.	क्षेत्र हे. धार.
7	8	9	10	11	12
1	तिम्मापुरम	काकिनाड	ईस्ट गोवावरी	234	0.390
				243	0.180
				245	0.050
				244	0.350
				231	0.090
				229	0.095
				228	0.100
				227	0.030
				264	0.105
				265	0.080
				266	0.255
				267	0.145
				271	0.120
				279	0.205
				207	0.435
				206	0.170
				309	0.055
				301	0.275
				300	0.150
				286	0.270
				287	0.285

[सं. ओ. 14016/52/90-जी पी]

पी. गोपालकृष्णन, अधर सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 698 :—Read words and figures shown in columns 1 to 6 to the schedule given below appearing in the schedule annexed to the Government of India Notification No. S.O. 2004 Dated 13-07-1990 published in the Gazette of India Part II Section III Sub-section (ii) dated 28-7-1990 on page 3419 as 'word & figures' shown in columns 7 to 12 to the schedule given below:

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the village	Mandal	District	Survey No.	Area
					Hec. Ars.
1	2	3	4	5	6
1.	Timmapuram	Kakinada	East Godavari	85/2	0.107
				84	0.157
				83/1	0.036
				83/2	0.093
				82/2	0.107
				-do-	-do-
				114	0.143
				-do-	-do-
				121/A/6	0.171
				122	0.171
				190	0.24
				214	0.049
				290	0.250
				291	0.250
				347	0.049
				(Main Road)	
				450	0.180
				359	0.200
				452	0.049
				453	0.250
				454	0.250
				455	0.219

SCHEDULE

Sr. Name of the Village No.	Mandal	District	Survey No.	Area	
				Hec. Ars.	
7	8	9	10	11	12
1.	Timmapuram	Kakinada	East Godavari	234	0.0390
				243	0.180
				245	0.050
				244	0.350
				231	0.090
				229	0.095
				228	0.100
				227	0.030
				264	0.105
				265	0.080
				266	0.255
				267	0.145
				271	0.120
				279	0.205
				207	0.435
				206	0.170
				309	0.055
				301	0.275
				300	0.150
				286	0.270
				287	0.285

[No. O-14016/52/90-G.P.]

Sd/-

P. GOPALAKRISHNAN, Under Secy.

(पेट्रोलियम और नसर्गिक वायु विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1991

का. आ. 699.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. (3202 से 3226) तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशिय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

— और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नरिमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहीत होगा।

परिशिष्ट

राज्य महाराष्ट्र, जिला - रायगढ़, तहसील - अलिबाग

गांव सर्वे नम्बर		हिस्सा नम्बर	गट नम्बर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर.	सेन्टीआर.
1	2	3	4	5	6	7
बोरीस	13	1 पार्ट	—	0	01	20
	13	2 पार्ट	—	0	02	60
	13	3 पार्ट	—	0	06	33
	12	1 पार्ट	—	0	00	94
	12	3 पार्ट	—	0	01	90
	11	1 पार्ट	—	0	12	23
	11	2 पार्ट	—	0	13	26
	10	4 पार्ट	—	0	07	28
	10	3 पार्ट	—	0	00	52
	81	1ए/1 पार्ट	—	0	32	36
	80	1 पार्ट	—	0	03	73
	80	2 पार्ट	—	0	11	31
	77	2 पार्ट	—	0	08	88
	77	3 ए पार्ट	—	0	06	60
	77	4 पार्ट	—	0	07	98
	85	2 बी/2 पार्ट	—			
	85	2 बी/1 पार्ट	—	0	11	11
	101	2 ए	—	0	02	03
	101	3 ए पार्ट	—	0	07	07
	101	1 ए 1 पार्ट	—	0	16	70

New Delhi, the 25th February, 1991

S.O. 699.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3202 to 3226 dated 9-11-90 under sub-section 1 of section 3, the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas Pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd.*, 91, *Sabhar Bhavan*, *Nariman Point*, *Bombay-400021* free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra

District : Raigad

Taluka : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				Hector	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Boris	13	1 Part	—	0	01	20
	13	2 Part	—	0	02	60
	13	3-A Part	—	0	06	33
	12	1 Part	—	0	00	94
	12	3 Part	—	0	01	90
	11	1 Part	—	0	12	23
	11	2 Part	—	0	13	26
	10	4 Part	—	0	07	28
	10	3 Part	—	0	00	52
	81	1 A/1 Part	—	0	32	36
	80	1 Part	—	0	02	73
	80	2 Part	—	0	11	31
	77	2 Part	—	0	08	88
	77	3 A Part	—	0	06	60
	85	2B/2	} Part	0	11	11
	85	2B/1				
	101	2 A Part	—	0	02	03
	101	3 A Part	—	0	07	07
	101	1A 1 /1	Part	0	16	70
	77	4 Part				

[No. O-14016/45/85-G.P.]

का. आ. 700.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. (3225) तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि, उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने निहीत होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नारिमन प्वाइंट, मुंबई-400021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहीत होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		जिल्हा : रायगड,		तहसिल : अलिबाग		
गांव	मबे नम्बर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर	सेंटीआर
गुजीम	46	1 पार्ट	—	0	10	95
	45	1 + 2ए पार्ट	—	0	05	99
	46	3 पार्ट	—	0	04	43
	1	8ए पार्ट	—	0	06	17
	1	8बी पार्ट	—	0	04	10
	1	8सी पोर्ट	—	0	02	68
	1	10पार्ट	—	0	01	35
	34ए	11पार्ट	—	0	09	34
	34ए	12एपार्ट	—	0	25	49
	35	2पार्ट	—	0	09	72
	45	8ए } पार्ट	—	0	00	82
	45	8बी }				

[सं. ओ.-14016/45/85 जी.पी.]

S.O. 700.—Whereas by Notification of the Government of India is the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3225 dated 9-11-90 under sub-section 1 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of the Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Grasim Ind. Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : : Maharashtra

District : Raigad

Taluka: Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Block/Gat No.	Area		
				Hectare	Are	Centiare
Gunjis	46	1 Part	—	0	10	95
	45	1 + 2 A Part	—	0	05	99
	- 45	3 Part	—	0	04	43

1	2	3	4	5	6	7
	1	8 A Part	—	0	06	17
	1	8 B Part	—	0	04	10
	1	8 C Part	—	0	02	68
	1	10 Part	—	0	01	35
	34A	11 Part	—	0	09	34
	34A	12 A Part	—	0	25	49
	35	2 Part	—	0	09	72
	45	8 A } 8 B }	—	0	0	82

[No. O-14016/45/85-G.P.]

का. आ. 701—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन [भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन] अधिनियम 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. (3223) तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः संलग्न प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दिया है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की बजाय ग्रामीण इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नर्मिन पाइंट मुंबई 400021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिल्हा : रायगड, तहसिल : अलिबाग

गांव	सर्गे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र	हेक्टर	आर	सेंटी आर
वायशेत	10	6 पार्ट	—	00	17	34	
	10	4 ए 1/1 पार्ट	—	00	01	67	
	10	7 ए पार्ट	—	00	51	45	
	10	7ब पार्ट	—	00	51	45	
	11	1 पार्ट	—	00	14	00	
	10	8 पार्ट	—	—	05	90	

[सं० ओ-14016/45/85-जी०पी०]

S.O. 701.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3223 dated 9-11-90 under sub-section 1 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared his intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of the Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd.*, 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra

District : Raigad

Taluka : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Vaishet	10	6 Part	—	0	17	34
	10	4-A-1-1/1	—	0	01	67
		Part				
	10	7 A	} Part	0	51	45
	10	7 B				
	11	1 Part	—	0	14	00
	10	8 Part	—	0	05	90

[No. O-14016/45/85-G.P.]

का. आ. 702 .—यतःपेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 3222 तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पहाड़ लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि, इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि, उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की बजाय ग्रामीण इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नरिमन पॉइंट मुंबई-400021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

परिशिष्ट पारसनी

राज्य : महाराष्ट्र जिला रायगड, तहसील: अलिबाग

गांव	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				ह	आर.	सेंटीआर
भाल	5	1 पार्ट	---	00	16	35
	2	1ए. पार्ट	---	---	04	25
	2	1 बी/1पार्ट	---	---	19	63
	1	1पार्ट	---	---	05	10
	1	2 बी/1पार्ट	---	00	07	58
	1	2 ए. /2 पार्ट	---	00	04	44
	83	1 ए. पार्ट	---	00	09	97
	83	1बी पार्ट	---	00	17	33
	82	1पार्ट	---	00	12	42
	82	1पार्ट	---	00	16	01
	81	4पार्ट	---	00	18	49
	79	1पार्ट	---	00	08	35
	79	2पार्ट	---	00	05	52
	79	2पार्ट	---	00	11	27
	83	पार्ट 5	---	---	10	66
	4	1 पार्ट	---	00	01	12

[सं. ओ 14016/45/85-जी पी]

S.O. 702.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3222 dated 9-11-90 under sub-section 1 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of the Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Nauman Point, Bombay 400021* free from encumbrance

SCHEDULE

State : Maharashtra

District : Raigad

Taluka : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				Hector	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Bhal	5	1 Part	---	0	16	35
	2	1-A Part	---	0	04	25
	2	1 B/1 Part	---	0	19	63
	1	1 Part	---	0	05	10

1	2	3	4	5	6
	1 2B/1 Part	—	0	07	58
	1 2A/2 Part	—	0	04	44
	83 1 B Part	—	0	17	33
	83 1 A Part	—	0	09	97
	82 1 Part	—	0	12	42
	82 2 Part	—	0	16	01
	81 4 Part	—	0	18	49
	79 1 Part	—	0	08	35
	79 2Part	—	0	05	52
	79 3 Part	—	0	11	27
	83 5 Part	—	0	10	66
	4 1 Part	—	0	01	12

[No. O—14016/45/85-G.P.]

का.आ. 703.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3221 तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दिया है।

और आगे यत्: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने विहित होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नरिमन प्वाइंट, मुंबई-400021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहीत होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : रायगढ़

तहसील : अलिबाग

गांव	सर्वे नम्बर	हिस्सा नम्बर	गट नम्बर	क्षेत्र		
				हेक्टर	ग्रा. सेंटीग्रा	
थल	49	9 भाग	—	—	02	83
	50	2 भाग	—	—	00	35
	50	3 भाग	—	0	02	12
	50	4 भाग	—	0	00	15

[सं.ओ-14016/45/85-जी पी.]

S.O. 703.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3221 dated 9-11-90 under sub-section (1) of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd.*, 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrances.

SCHEDULE

State : Maharashtra.

District : Raigad.

Taluka : Alibag.

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat/Block No.	Area		
				Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Thal	49	9 Part	—	0	02	83
	50	2 Part	—	0	0	35
	50	3 Part	—	0	02	12
	50	4 Part	—	0	0	15

[No. O.14016/45/85-G.P.]

का.प्रा. 704.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा. (3220) तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नरिमन पॉइंट, मुंबई-400 021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र			जिला : रायगढ़	तहसील : अलिबाग		
गांव	सर्वे नं.	हिस्सा नम्बर	गट नम्बर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर.	सेंटीआर
1	2	3	4	5	6	7
मानतर्फे मिराड	93 ए	4 भाग	—	0	01	58
	92	2 भाग	—	0	13	25

1	2	3	4	5	6	7
	92	1 भाग	—	0	00	94
	94	1 भाग	—	0	17	07
	97	12 भाग	—	0	04	75
	97	13 भाग	—	0	00	50
	94	2 भाग	—	0	01	30
	84	1 + 2 + 3 भाग	—	0	07	60
	84	4 भाग	—	—	15	04
	80	8 भाग	—	—	08	34
	80	9 भाग	—	—	11	74
	83	11 ए, 2 भाग	—	—	09	62
	83	13 ए भाग	—	0	13	80
	93 ए	2 भाग	—	—	00	38

[सं अ-14016/45/85-जी पी.]

S.O. 704.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3220 dated 9-11-90 under sub-section (1) of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas Pipeline.

And further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd.*, 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra.

District : Raigad

Taluka : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Block/ Gat No.	Area		
				Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Man Tarf Zirad	93A	4 Part	—	0	01	58
	92	2 Part	—	0	13	25
	92	1 Part	—	0	00	94
	94	1 Part	—	0	17	07
	97	12 Part	—	0	04	75
	97	13 Part	—	0	00	50
	94	2 Part	—	0	01	30
	84	1 + 2 + 3 Part	—	0	07	60
	84	4 Part	—	0	15	04
	80	8 Part	—	0	08	34
	80	9 Part	—	0	11	74
	83	11 A 2 Part	—	0	09	62
	83	13 A Part	—	0	13	80
	93A	2 Part	—	0	00	38

[No. O-14016/45/85-GP]

का.प्रा. 705.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा. 3216 तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दिया है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है की उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नारिमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : रायगढ़

तहसील : अलिबाग

गांव	सर्वे नं.	हिस्सा नम्बर	गट बूक	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर	सेंटीआर
चेंदरे	39	1 भाग	—	—	03	36
	38	1-ए भाग	—	—	06	23
	38	1-बी भाग	—	—	07	98
	38	2-ए भाग	—	—	02	27
	38	2-बी भाग	—	—	08	22
	37	2(1) भाग	—	—	06	85
	37	3 भाग	—	—	09	99
	41	1-ए भाग	—	—	17	90
	44	1-ए भाग	—	—	36	08
	51	1-ए भाग	—	—	13	48
	51	1-बी भाग	—	—	08	38
	52	2-बी भाग	—	—	14	9
	52	2-सी भाग	—	—	09	42
	52	6 भाग	—	—	08	97
	40	1-सी भाग	—	—	01	69
	36	1 भाग	—	—	01	95

[सं. ओ.-14016/45/85-जी पी]

S.O. 705.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3216 dated 9-11-90 under sub-section 1 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified

in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of the Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the *Grasim Ind. Ltd.*, 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra

District : Raigad

Tahasil : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Arca		
				Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Chendhare	39	1 Part	—	—	03	36
	38	1A Part	—	—	06	23
	38	1-B Part	—	—	07	98
	38	2-A Part	—	—	02	27
	38	2-B Part	—	—	08	22
	37	2-1 Part	—	—	06	85
	37	3 Part	—	—	09	99
	41	1-A Part	—	—	17	90
	44	1-A Part	—	—	36	08
	51	1-A Part	—	—	13	48
	51	1-B Part	—	—	08	38
	52	2-B Part	—	—	14	09
	52	2-C Part	—	—	09	42
	52	6 Part	—	—	08	97
	40	1-C Part	—	—	01	69
	36	1 Part	—	—	01	95

[No. O-14016/45/85G.P.]

का.आ० 706.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3212 तारीख 9-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दिया है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने निहित होने की बजाय ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 91 साखर भवन, नारिमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र जिला : रायगढ़ तहसील : अग्निबाग

गांव	सर्वे नं.	हिस्सा नं.	गट नम्बर	क्षेत्र		
				हेक्टर	घार	सेंटीघार
बेलकडे			369 भाग	0	07	20
			368 भाग	0	12	17
			367/1 भाग	0	13	02
			361 भाग	0	04	99
			340 भाग	0	06	92
			341 भाग	0	05	10
			336 भाग	0	07	88
			333 भाग	0	06	47
			332 भाग	0	13	74
			331 भाग	0	06	21
			300 भाग	0	00	47
			323 भाग	0	02	06
			326 भाग	0	07	98
			325 भाग	0	02	23
			306 भाग	0	02	03
			380	0	01	08
			259 भाग	0	02	98
			255 भाग	0	17	09
			252 भाग	0	01	50
			253 भाग	0	18	05
			254 भाग	0	05	53
			223 भाग	0	03	95
			244	0	02	57
			224 भाग	0	03	02
			225 भाग	0	06	01
			212 भाग	0	09	97
			226 भाग	0	01	84
			246 भाग	0	00	20

[मं. औ-14016 45/85-जी पी]

राजीव सहषि, उप सचिव

S.O. 706.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3212 dated 9-11-90 under sub-section 1 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying Gas Pipelines.

And, whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the Right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of user in the said lands specified in the schedule appended to the Notification hereby acquired for laying the Gas pipeline.

And, further, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of the Section 6, the Central Government directs that the Right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Grasim Ind. Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021 free from encumbrance.

SCHEDULE

State : Maharashtra

District : Raigad

Taluka : Alibag

Village	Survey No.	Hissa No.	Block No.	Area		
				Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6	7
Belkade	—	—	369 Part	0	07	20
	—	—	368 Part	0	12	17
	—	—	367/1 Part	0	13	02
	—	—	361 Part	0	04	99
	—	—	340 Part	0	06	92
	—	—	341 Part	0	05	10
	—	—	336 Part	0	07	88
	—	—	333 Part	0	06	47
	—	—	332 Part	0	13	74
	—	—	331 Part	0	06	21
	—	—	300 Part	0	00	47
	—	—	323 Part	0	02	06
	—	—	326 Part	0	07	98
	—	—	325 Part	0	02	23
	—	—	306 Part	0	02	03
	—	—	380	0	01	08
	—	—	259 Part	0	02	98
	—	—	255 Part	0	17	09
	—	—	252 Part	0	01	50
	—	—	253 Part	0	18	05
	—	—	254 Part	0	05	53
	—	—	223 Part	0	03	95
	—	—	244 Part	0	02	57
	—	—	224 Part	0	03	02
	—	—	225 Part	0	06	01
	—	—	212 Part	0	09	97
	—	—	226 Part	0	10	84
	—	—	246 Part	0	00	20

[No. O-14016/45/85-G.P.]

RAJIV MEHRSHI, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1991

का.आ. 707 भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या का.आ. 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1968 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारिता के अपवाद के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फिल्म सहाकार बोर्ड बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त, संलग्न अनुसूची के बालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को, जिसको जिनका विवरण अपर्यक्त अनुसूची के बालम 6 में दिया गया है, उसके विचार करने के अन्तर्गत, संलग्न अनुसूची के बालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को, जिसका/जिनका विवरण उपर्यक्त अनुसूची के बालम 6 में दिया गया है, उसके/उनके सभी भाषा रूपांतरों के साथ जो 1-1-90 से 10-9-1990 की अवधि से संबंधित है स्विकार करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	फिल्म का शीर्षक	फिल्म की लम्बाई (मीटर में)	आवेदक का नाम	निर्माताओं का नाम	संक्षिप्त रूप देखा कि क्या फिल्म वैज्ञानिक फिल्म है या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है या समाचारों और सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्म है या वृत्तचित्र है
1	2	3	4	5	6
1.	न्यूज मैगजीन नं. 166, (एथलेटिक्स-बर्ड क्लास)	296.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-जी, देशमुख मार्ग, बम्बई-400026		सामान्य रिलीज और 'समाचार एवं सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत'
2.	क्रैजाइल माउण्टेनस	596.00	-तदर्थ-		सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र के रूप में वर्गीकृत।
3.	महाराष्ट्र न्यूज रील नं. 444	236.00	श्री बी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (फि.) सूचना एवं जन संपर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई-34	सूचना एवं जन संपर्क महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार बम्बई-32	महाराष्ट्र क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिलीज
4.	लगेच पेंसे	177.00	-तदर्थ-	-तदर्थ-	महाराष्ट्र क्षेत्र में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज
5.	बातचीतगिनी 145	276.83	ग्राम प्रदेश राज्य फिल्म विकास मिशन लि., 11.5.423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		ग्राम प्रदेश क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिलीज
6.	उत्तर प्रदेश समाचार 128	294.11	श्रीरेन्द्र पाण्डे, निर्माता न्यूजरील, सूचना और जन संपर्क निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		"समाचार और सामयिक घट- नाओं" के रूप में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रिलीज
7.	न्यूज मैगजीन नं. 162	299.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-डा. जी देशमुख मार्ग, बम्बई-26		सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत।
8.	निरोध	60.96	-तदर्थ-		-तदर्थ-
9.	सेब दि हिमालयाज	533.95	-तदर्थ-		-तदर्थ-
10.	आधुनिक लेनी	362.70	सूचना और जनसंपर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेक्टर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-34	सूचना और जन संपर्क महा- निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई-32	वृत्तचित्र के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज
11.	बिल्ली मूव्ज एडेड	486.46	फिरोज चिन्तिय "कर्मवीर" प्लेट नं. 16, तोसरा तल, छार. टी. श्री. लेन, अधेरी (पश्चिमी) बम्बई-400058		वृत्तचित्र के रूप में सामान्य रिलीज
12.	महाराष्ट्र न्यूजरील सं 446	234.00	श्री बी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (फिल्म) सूचना एवं जन संपर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई-34		"समाचार और सामयिक घटनाओं" के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज

1	2	3	4	5	6
13.	महति चित्र 491	213.38	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सचिवालय, गंधी नगर- 382010		"समाचार और सामयिक घटनाओं" के रूप में गुजरात क्षेत्र में रिलीज
14.	न्यूज मैगजीन नं. 168 (नामिबिया विन्स फ़ीचर)	402.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई- 26		सामान्य रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
15.	बातौरंगिनी 151	302.74	ग्राम्य प्रवेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004		समाचार एवं सामयिक घटनाओं के रूप में ग्राम्य प्रवेश क्षेत्र में रिलीज
16.	बातौरंगिनी नं. 152	284.45	-तदर्थ-		-तदर्थ-
17.	महापुरुष डा. अम्बेडकर	480.00	श्री. पी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक सूचना महाराष्ट्र सरकार, 68-तारदेव रोड, बम्बई- 34		"वृत्तचित्र" के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज
18.	पुरस्कृत पुनर्वसन	327.49	-तदर्थ-		-तदर्थ-
19.	आसानी ही आसानी	40.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई- 26		सामान्य रिलीज और "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत
20.	समसंवारी की बात	40.00	-तदर्थ-		काट-छांट के बाद "वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज
21.	न्यूज मैगजीन नं. 167	454.00	-तदर्थ-		"समाचार और सामयिक घटनाओं" के रूप में सामान्य रिलीज
22.	बातौरंगिनी 150	284.45	ए. पी. एस. एफ. डी. सी. लि 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004		"समाचार और सामयिक घटनाओं" के रूप में ग्राम्य प्रवेश क्षेत्र में रिलीज
23.	छानुची कथा	395.6	श्री. पी. पी. भोंडे, सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र बम्बई- 34		वाक्य में काट-छांट कर "वृत्तचित्र" के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज
24.	पिकवू पिबके मोती	314.55	श्री. पी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक सूचना, महाराष्ट्र सरकार, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34		"वृत्तचित्र" के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज
25.	बातौरंगिनी नं. 149	320.12	ग्राम्य प्रवेश राज्य फिल्म विकास निगम, 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।		"समाचार और सामयिक घटनाओं" के रूप में ग्राम्य प्रवेश क्षेत्र में रिलीज
26.	न्यूज मैगजीन नं. 166 (साक्षरता : एनाक्रुलम उदाहरण)		फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई- 26		"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज
27.	कलकत्ता बक्स ए सिटी आफ पैसेज	578.20	मैसर्स अंजन राय प्रोडक्शन्स, 18/39, कार्लाय गार्गे पैसेज इस्ट, कलकत्ता - 700019		"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज
28.	उत्तर प्रदेश समाचार नं. 120	295.64	श्री. धीरेन्द्र पाण्डे, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उ. प्र. क्षेत्र में रिलीज के लिए और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत

1	2	3	4	5	6
29. पुकार	50.30	श्री एस. आर. साज, प्रोपाईटर, ग्राम्मा-ए-मेकर्स एंसोसिएशन, बम्बई			सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत
30. ग्लूज मैगजीन नं. 165 1990 भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह	296.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26			"समाचार और सामयिक विषयों" के रूप में सामान्य रिलीज
31. भारती तरंगिनी नं. 147	288.28	ए. पी. एस. एफ. डी. सी. लि. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004			"समाचार और सामयिक घट- नाओं" के रूप में प्रांश प्रदेश में रिलीज
32. भारती तरंगिनी नं. 148	266.77	-तदैव-			-तदैव-
33. गुवा महाराष्ट्र	319.29	सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, 68-तारदेव रोड, बम्बई			महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज और "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत
34. नवजीवन	306.63	-तदैव-			-तदैव-
35. ग्लूज मैगजीन नं. 164	290.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			"समाचार एवं सामयिक घट- नाओं" के रूप में सामान्य रिलीज
36. डाकुमैट्री ब्रिक्स लाइफ क्लोजर टू यू	53.95	-तदैव-			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज
37. दि थर्ड घाई	230.00	-तदैव-			-तदैव-
38. यस, वी मेक वेम सार्ट	336.05	-तदैव-			-तदैव-
39. स्पोर्टिंग वि इवेंट्स	16.21	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			सामान्य रिलीज "वृत्तचित्र"
40. महाराष्ट्र ग्लूज रील	265.00	श्री वी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (फिल्म), सूचना और जन सम्पर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारदेव रोड, बम्बई - 34			महाराष्ट्र में रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गी- कृत
41. गर्वो गुजरात भाग - 2	589.03	संयुक्त निदेशक, सूचना, गुजरात सरकार, धनराज महल, भूतल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई - 39			गुजरात क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज (घाबंदक द्वारा फिल्म के शीर्षक में भाग - 2 जोड़ जाने के बाद)
42. पूर्ण कुम्भ 1989	534.92	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, सूचना एवं जन सम्पर्क निदे- शालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।			उत्तर प्रदेश क्षेत्र में "वृत्त-चित्र" के रूप में।
43. भारती तरंगिनी 146	262.84	प्रांश प्रदेश राज्य फिल्म विकास नियम लि., 1156-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 4			प्रांश प्रदेश में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिलीज।
44. ग्लूज मैगजीन नं. 163 (पंजाब इन संचे आफ पीस)	437.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26			"समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में सामान्य रिलीज
45. दिल्ली पुलिस—चेंजिंग फेस	299.00	-तदैव-			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज

1	2	3	4	5	6
46. महत्तिचित्र सं. 493	222.50	सहायक निदेशक सूचना गुजरात सरकार, रायनोड रिमर्स लेब लि., 77-डा. ए. बी. रोड, वर्ली, बम्बई - 18			गुजरात क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित और समाचार एवं सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
47. महत्तिचित्र नं. 494	167.64	-तदर्थ-			गुजरात क्षेत्र में रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
48. किसान विकास पत्र	430.79	ग्रांध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004			ग्रांध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
49. म्यूज मेगजीन नं. 171	585.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26			सामान्य रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
50. म्यूज मेगजीन नं. 170	507.00	-तदर्थ-			-तदर्थ-
51. भारता तरंगिणी	311.28	ग्रांध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004			ग्रांध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज और सामान्य एवं सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
52. भारता तरंगिणी 155	257.32	-तदर्थ-			-तदर्थ-
53. भारता तरंगिणी 156	235.67	-तदर्थ-			-तदर्थ-
54. महत्तिचित्र 495	243.84	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्मस) गुजरात सरकार, रायनोड रिमर्स लेब लि., 77-डा. ए. बी. रोड, वर्ली, बम्बई - 18			गुजरात क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
55. म्यूज मेगजीन नं. 173- ए. जी. 15 साउथ को-ऑपरेशन	404.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26			"समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में सामान्य रिलीज
56. चक्र	73.00	-तदर्थ-			"वृत्तचित्र" के रूप में ग्रांध्र- प्रदेश क्षेत्र में रिलीज।
57. अत्यन्त	72.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26			"वृत्तचित्र" के रूप में केरल क्षेत्र में रिलीज
58. चक्र	76.00	-तदर्थ-			उड़ीसा क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
59. चक्र	81.00	-तदर्थ-			असम क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
60. चक्र	73.00	-तदर्थ-			पश्चिम बंगाल में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
61. चक्र	76.00	-तदर्थ-			तमिलनाडु में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
62. चक्र	70.00	-तदर्थ-			कर्नाटक में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
63. विश्व मां	87.00	-तदर्थ-			उड़ीसा क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
64. बुद्धिमती मां	97.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26			"वृत्तचित्र" के रूप में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में रिलीज।
65. म्यूज मेगजीन 175	388.00	-तदर्थ-			अखिल भारतीय रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।

1	2	3	4	5	6
66.	शायेरिया	301.00	-तदीव-		सामान्य रिलीज और "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत।
67.	वार्ता तरंगिनी 161	297.86	ए. पी. एस. एफ. डी. सी लि, 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिलीज।
68.	महाराष्ट्र न्यूज मैगजीन 448	275.21	पी. एस. पालेकर, सहायक निदेशक फिल्म, सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केंद्र, बम्बई।		महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज और 'समाचार एवं सामयिक घटनाओं' के रूप में वर्गीकृत।
69.	न्यूज मैगजीन 174 (बुकिंग फारवर्ड भाग-2)	348.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26		"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज।
70.	चक्र	68.00	-तदीव-		महाराष्ट्र क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
71.	जय	73.00	-तदीव-		"वृत्तचित्र" के रूप में गुजरात में रिलीज।
72.	बंगाल ग्लिमसेस थ्रफ ए ग्लोरियस ह्योज	600.00	ज्योतिर्मय राय, 15, मोती लाल नेहरू रोड, कलकत्ता - 700029		"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज।
73.	व्रत तरंगिनी 160	364.02	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिलीज।
74.	न्यूज मैगजीन 173 (समता और न्याय के लिए)	332.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26		"समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में सामान्य रिलीज।
75.	दस्त शगवे हो	70.00	-तदीव-		"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज।
76.	समझदार भां	109.00	-तदीव-		-तदीव-
77.	विवेकमना भनाई	94.18	-तदीव-		तमिलनाडु क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
78.	तेले बीना तल्ली	92.66	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26		आंध्र प्रदेश में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
79.	जाने साये	103.02	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई - 26		कर्नाटक क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
80.	विवेकमुल्ला अम्मा	88.70	-तदीव-		केरल में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
81.	जानी मातु	98.45	-तदीव-		असम क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
82.	अन्ध विश्वास	84.00	-तदीव-		गुजरात क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
83.	मुदा नामबिकाई	72.00	-तदीव-		तमिलनाडु में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
84.	अन्ध विश्वास	78.38	-तदीव-		आंध्र प्रदेश में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
85.	मुदा नामबेके	90.83	-तदीव-		कर्नाटक में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
86.	अंध विश्वास	74.07	-तदीव-		केरल जिले में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।

1	2	3	4	5	6
87.	अन्ध विश्वास	76.20	—तदैव—		असम क्षेत्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
88.	अन्ध विश्वास	69.00	—तदैव—		पश्चिम बंगाल क्षेत्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
89.	अन्ध विश्वास	76.00	—तदैव—		उड़ीसा क्षेत्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
90.	ओ. आर. एस. का मिश्रण	88.00	—तदैव—		“वृत्तचित्र” के रूप में सामान्य रिलीज।
91.	आ. अ. ए. दा घोल	87.99	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		पंजाब हरियाणा, दिल्ली में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
92.	दस्त लगने के कारण	67.00	—तदैव—		“वृत्तचित्र” के रूप में सामान्य रिलीज।
93.	दस्त लगते ही	72.00	—तदैव—		पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज।
94.	ओ. आर. एस. का घोल	83.00	—तदैव—		उ. प्र. म. प्र., बिहार में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज।
95.	समझदार आई	101.00	—तदैव—		महाराष्ट्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
96.	अंध विश्वास	74.37	—तदैव—		“वृत्तचित्र” के रूप में सामान्य रिलीज।
97.	समझदार पति	36.00	—तदैव—		—तथैव—
98.	दस्त लगने के कारण	62.00	—तदैव—		पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज।
99.	दरतों की वजह	67.00	—तदैव—		उ. प्र., म. प्र., बिहार जम्मू और कश्मीर में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज।
100.	बनश्री हिच धनश्री	395.00	पी. एस. पालेकर, सहायक निदेशक फिल्म, सूचना महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेंटर, बम्बई-34		महाराष्ट्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
101.	वार्तातरंगिनी 159	290.24	ए. बी. एस. एफ. डी. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		“समाचार एवं सामयिक घटनाओं” के रूप में आंध्र प्रदेश में रिलीज।
102.	तुफान बद्धित ऊलानू आडुकोडी	408.54	ए. बी. एस. एफ. डी. 11-5-423/6, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		“समाचार एवं सामयिक घटनाओं” के रूप में आंध्र प्रदेश में रिलीज।
103.	गल्युकोमा : ए रेस टु ब्लाईंडनेस	366.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		“वृत्तचित्र” के रूप में सामान्य रिलीज।
104.	जल संजीवनी	76.00	—तदैव—		महाराष्ट्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
105.	जल संजीवनी	72.54	—तदैव—		गुजरात में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
106.	ओ. आर. एस. कलाब	80.47	—तदैव—		“वृत्तचित्र” के रूप में तमिल-नाडु में रिलीज।

1	2	3	4	5	6
107. ओ. आर. एस. मिश्रम	82.96	—तथैव—			“वृत्तचित्र” के रूप में आंध्र प्रदेश में रिलीज।
108. ओ. आर. एस. मिश्रणा	84.12	—तथैव—			कर्नाटक में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
109. ओ. आर. एस. मिश्रीदम	70.71	—तथैव—			केरल में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
110. संजीवनी पनी	72.54	—तथैव—			असम में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
111. संजीवनी बारी	70.40	—तथैव—			बंगाल में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
112. जल संजीवनी	70.71	—तथैव—			उड़ीसा में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
113. एक समझदार मां	84.00	—तथैव—			“वृत्तचित्र” के रूप में सामान्य रिलीज।
114. एक होशियार मां	91.00	—तथैव—			उ.प्र., म.प्र., बिहार और जम्मू व कश्मीर में रिलीज।
115. एक सयानी मां	75.00	—तथैव—			पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
116. विविध प्रतिभाओं का संगम	578.16	योगेश कान्त भागोरिया, 40, बनारसी दास एस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली-54			राजस्थान क्षेत्र में रिलीज और “वृत्तचित्र” के रूप में बर्गीकृत।
117. महाराष्ट्र न्यूज रोल 447	268.00	पी. एस. पालेकर, सहायक निदेशक (एफ), सूचना और जन संपर्क महानिदेशालय, फिल्म सेंटर, 68—तारदेव रोड, बम्बई-34			“समाचार एवं सामयिक घटनाओं” के रूप में महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज।
118. चमची जेतिल शखर अने चिमटी जेतुलू मीथू	89.31	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			“वृत्तचित्र” के रूप में गुजरात क्षेत्र में रिलीज।
119. चमचा भर शखर एण्ड चिमूट भर मीठ	89.00	—तथैव—			महाराष्ट्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
120. बेदिये नेसलुवाडे इलेयाडे	87.18	—तथैव—			तमिलनाडु में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
121. नीला वेरोचनाला नून्ची उप-समानम इन्थो सुलाभम	87.79	—तथैव—			आंध्र प्रदेश क्षेत्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
122. अतिवेदी इन्दवे सुलभ रक्षणो	95.04	—तथैव—			आंध्र प्रदेश क्षेत्र में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
123. वेरेलाक्कम नेयेन्द्रिकन एन्तरे इल्लुप्पम	66.45	—तथैव—			“वृत्तचित्र” के रूप में केरल में रिलीज।
124. अतिसार तेके मुक्ति	89.61	—तथैव—			पश्चिम बंगाल में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।
125. अतिसारुमुक्ति (उड़िया)	75.29	—तथैव—			उड़ीसा में “वृत्तचित्र” के रूप में रिलीज।

1	2	3	4	5	6
126. नमक चानी का मिश्रण	77.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज।
127. नमक चानी का घोल	95.00	--तथैव--			उ.प्र., म.प्र., बिहार और जम्मू व कश्मीर में वृत्तचित्र के रूप में रिलीज।
128. नमक चानी का घोल	75.00	--तथैव--			पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
129. भेद रोगों पर मृत्ति	78.38	--तथैव--			असम में "वृत्तचित्र" के रूप में रिलीज।
130. विशेष महाराष्ट्र समाचार चित्र क्रमांक-4 (अपना उत्सव)	292.00	पी. एस. पालेकर, सहायक निदेशक (एफ.), महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68-तारवेण रोड, बम्बई-34			महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज और "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत (समाचार एवं सामयिक घटनाएँ नहीं)।
131. ड्रम	111.25	अजय सिंह, बुद्धिमा, द्वारा यासनिक फिल्मस, 10-ए, तिनवाला बिल्डिंग, त्रिभुवन रोड, बम्बई-400004			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिलीज।
132. सन टैफ़ ग्राफ असम	597.41	एम. एम. बरुआ, डू-रे-मे फिल्मस, 121, कलेक्टर कालोनी, फ्लैट नं० 1-सी, चेम्बूर, बम्बई-74			सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत।
133. न्यूज मैगज़ीन (नृकिय फार्बर्ड भाग-3)	420.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत (समाचार एवं सामयिक घटनाएँ नहीं)।
134. फार यूबर हेल्थ	367.00	--तथैव--			सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत।
135. गोमा	69.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			सामान्य रिलीज और "वृत्त- चित्र" के रूप में वर्गीकृत।
136. न्यूज मैगज़ीन नं० 177 (यू. एस. एस. आर.-इंडिया फ्रंटशिप एण्ड ट्रस्ट)	477.00	--तथैव--			सामान्य रिलीज और "समाचार" एवं सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
137. बार्ना त्रिगिनी 162	271.34	ए. पी. एस. एफ. डी. सी., हैदराबाद-11-5-423/16, मकड़ी का पुल, हैदराबाद 500004			आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
138. बिहार दर्शन	387.76	श्री एस. झा, फिल्म निर्माण अधिकारी, मुम्बना एवं अणु संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना।			बिहार क्षेत्र में रिलीज और "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत।

1	2	3	4	5	6
139. वार्ता नरंगिनी 163	298.17	ए. पी. एम. एफ. डी. सी., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल हैदराबाद।			मध्य प्रदेश क्षेत्र में रिक्विज और "समाचार एवं साम- यिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
140. विकास की ओर	518.14	निदेशक सूचना और जनसम्पर्क, बिहार सरकार, पटना।			बिहार क्षेत्र में "वृत्तचित्र" के रूप में रिक्विज।
141. महाराष्ट्र स्यूजरील नं. 449	233.00	पी. एम. पालेकर, सहायक निदेशक (एफ.), सूचना और जनसम्पर्क महा- निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, 68-साखेव रोड, बम्बई-34			महाराष्ट्र क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिक्विज।
142. प्रयत्न	145.42	तेलुगु चित्र, 6-1-308/ए/18, श्रीराजवाड, हैदराबाद-500001			मध्य प्रदेश क्षेत्र में "वृत्त- चित्र" के रूप में रिक्विज।
143. महानि चित्र नं. 496	354.70	सहायक निदेशक सूचना (एफ) गुजरात सरकार, रायलोट रिमर्च लैंड, 77-डा. ए. बी. रोड, बम्बई-18			गुजरात क्षेत्र में "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में रिक्विज।
144. स्यूज मैगजीन नं. 178	417.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26			"समाचार एवं सामयिक घट- नाओं" के रूप में सामान्य रिक्विज।
145. स्यूज मैगजीन नं. 178-ए	540.00	--तद्वैव--			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिक्विज।
146. स्यूज मैगजीन 179 (ब्राडकास्टिंग विडिओ टैप रॉल)	501.00	--तद्वैव--			"समाचार एवं सामयिक घट- नाओं" के रूप में सामान्य रिक्विज।
147. भारतीय गणेश शंकर बिद्यार्थी	319.00	--तद्वैव--			"वृत्तचित्र" के रूप में सामान्य रिक्विज।
148. स्यूज मैगजीन नं. 179-ए (विडिओ टैप रॉल)	373.00	--तद्वैव--			"समाचार एवं सामयिक घट- नाओं" के रूप में सामान्य रिक्विज।
149. वार्ता नरंगिनी 164	279.88	ए. पी. एम. एफ. डी. सी., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500001			"समाचार एवं सामयिक घट- नाओं" के रूप में रिक्विज।
150. वार्ता नरंगिनी 165	283.23	--तद्वैव--			--तद्वैव--

[फा. सं. 315/1/90-एफ. (पी.)]

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
ORDER

New Delhi, the 30th January, 1991

S.O. 707—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the first Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay here approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule pertaining to the period 1-1-90 to 30-9-1990.

SCHEDULE

SJ. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for educational purpose or a film dealing with news & current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	News Magazine No. 161 (Athletics-World Class)	296.00	Films Division Govt. of India, 24-G. Deshmukh Marg- Bombay-400 026.		General Release and classified as "News and Current Events"
2.	Fragile Mountains	596.00	-do-		General release and classified as "Documentary".
3.	Maharashtra Newsreel No. 444	236.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dire. Films Dir. Gen. of Inf. & Publ. Rel., Govt. of Maharashtra Bombay-34.	Dir. Gen of Inf. & Pub. Rels., Govt. of Maha- rashtra, Bombay-32.	Release in Maharashtra circuit as "News and Current Events".
4.	Lagech Paisa	177.00	-do-	-do-	Release in Mah. circuit as Documentary.
5.	Varta Tarangini 145	276.83	Andhra Pradesh State Film Devlp. Corpn. Ltd., 11-5-423,1, Lakdikapool Hyderabad-500 004.		Release in Andhra Pradesh circuit as "News and Current Events".
6.	Uttar Pradesh Samachar 128	294.11	Dhirendra Pande, Producers Newsreel, Dir. of Inf. & Public Relations, Govt. of U.P. Lucknow.		Release in Uttar Pradesh circuit as "News and Current Events."
7.	News Magazine No. 162 Films for Children.	299.00	Films Division, Govt. of India 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-26.		General Release and classified as "Documentary".
8.	Nirodh	60.96	-do-		-do-
9.	Save the Himalayas	533.95	-do-		-do-
10.	Aadhunik Leni	362.70	Dir. Genl. of Inf. & Pub. Rels., Govt. of Maharashtra Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-34.	Dir. Gen. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay-32.	Release in Maharashtra circuit as "Documentary".
11.	Delhi Moves Ahead	486.46	Firoze Chinoy 'Karamveer' Flat No. 16, 3rd floor, RTO Lane, Andheri (West) Bombay-400058.		General Release as "Documentary".
12.	Maharashtra News Reel No. 446	234.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. Films. Dir. General of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Bombay-34		Release in Maharashtra circuit as "News and Current Events".
13.	Mahiti Chitra 491	213.36	Dir. of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar-382010		Release in Gujarat circuit as "News and Current Events".
14.	News Magazine No. 168 (Namibia Wins freedom)	402.00	Films Division, Govt. of India-24 Peddar Road, Bombay-26		General Release and classified as "News and Current Events".

1	2	3	4	5	6
15.	Varta Tarangini 151	302.74	Andhra Pradesh State Film Develp., Corpn., Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-Ka-pool- Hyderabad-500 004.		Release in A.P. circuit as "News and Current Events".
16.	Varta Tarangini 152	284.45	-do-		-do-
17.	Mahapurush Dr. Ambedkar	480.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. of Inf. Govt. of Maharashtra, 68-Tardeo Road- Bombay-34.		Release in Maharashtra circuit as "Documentary"
18.	Purgastanche Punarwasan	327.49	-do-		-do-
19.	Asani Hi Asani	46.00	Films Division, Govt. of India 24, Peddar Road- Bombay-26.		General release & classified as "Documentary".
20.	Samajhdari Ki Baut	40.00	-do-		General release as "Documentary" subject to deletion.
21.	News Magazine No. 167	454.00	-do-		General release as "News and Current Events".
22.	Varta Tarangini 150	284.45	A.P.S.F.D.C. Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-Ka-Pool Hyderabad-500004.		Release in A.P. circuit as "News and Current Events".
23.	Dhanuchi Katha	395.6	V.P. Bhonde, Dir. Gen. of Inf. Govt. of Maharashtra, Bombay-34.		Release in Maharashtra circuit as "Documentary" Subject to one deletion of a sentence.
24.	Pikvoo Pivale Moti	314.55	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. of Information Govt. of Maharashtra, 68-Tardeo Road, Bombay-34.		Release in Maharashtra circuit as "Documentary"
25.	Varta Tarangini 149	320.12	Andhra Pradesh State Film Develp. Corpn. 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool Hyderabad-500 004.		Release in A.P. circuit as "News and current Events".
26.	News Magazine No. 166 (Literacy: Ernakulam Example)		Films Division Government of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		General release as "Documentary"
27.	Calcutta—Once a City of Palaces	578.20	M/s. Anjan Roy Productions, 18/39, Kallygunge, Palace East, Calcutta-700 019.		General release as "Documentary"
28.	Uttar Pradesh Samachar No. 129	295.64	Shri Dharendra Pande, Govt. of Uttar Pradesh. Lucknow.		Release in U.P. circuit and classified as "News and Current Events".
29.	Pukar	50.30	Shri S.R. Saaz, Proprietor, Amma-A Makers Association, Bombay.		General release and classified as "Documentary".
30.	News Magazine No. 165, 1990- International Film Festival of India.	296.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		General release as "News and Current Events".
31.	Varta Tarangini No. 147	286.28	A.P.S.F.D.C. Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool Hyderabad-500 004.		Release in A.P. circuit as "News and Current Events".
32.	Varta Tarangini No. 148	266.77	-do-		-do-
33.	Yuva Maharashtra	319.29	Director General of Inf. Govt. of Maharashtra, 68-Tardeo Road, Bombay.		Release in Maharashtra circuit and classified as "Documentary".

1	2	3	4	5	6
34. Navjeevan	306.63	-do-	-do-	-do-	-do-
35. News Magazine No. 164	290.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road Bombay-26.			General Release as "News and Current Events".
36. Documentary Brings Life closer to you	53.95	-do-			General release as "Documentary".
37. The Third Eye	230.00	-do-			-do-
38. Yes, we make them short	336.05	-do-			-do-
39. Sporting the Events	26.21	Films Division, Govt. of India 24-Peddar Road, Bombay-26.			General Release "Documentary".
40. Maharashtra News Reel 445	265.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. (Films), Dir. Genl. of Inf. & Pub. Rel. Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			Release in Maharashtra circuit and classified as News and "Current Events".
41. Garvi Gujarat Pt. II	589.03	It. Dir. of Information, Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Ground floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-39.			Release in Gujarat circuit as "Documen- tary" (subject to appli- cant adding Pt. 2 to the film as title).
42. Purna Kumbha 1989	534.92	Shri Dharendra Pande, Dir. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.			U.P. Circuit as "Documentary".
43. Varta Tarangini 146	262.84	Andhra Pradesh State Film Devlp., Corpn. Ltd., 11-6-423/1, Lakdi-ka-pool Hyderabad-4.			Release in A.P. circuit as "News and current Events".
44. News Magazine No. 163 (Punjab in Search of Peace)	437.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.			General Release as "News and Current Events".
45. Delhi-Police-Changing face	299.00	-do-			General Release as "Documentary".
46. Mahitichitra No. 493	222.50	Asstt. Dir. of Inf., Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab. Ltd., 77-Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-18.			Approved for release in Gujarat circuit and classified as "News and Current Events".
47. Mahitichitra No. 494	167.64	-do-			Release in Gujarat circuit and classified as "News and Current Events".
48. Kisan Vikas Patra	430.79	Andhra Pradesh State Film Devlp. Corpn. Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool Hyderabad-500 004.			Release in A.P. circuit and classified as "N & CE".
49. News Magazine No. 171	505.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.			General Release and classified as "N & CE"
50. News Magazine No. 170	507.00	-do-			-do-
51. Varta Tarangini 154	311.28	Andhra Pradesh State Film Devlp., Corpn., Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool Hyderabad-500 004.			Release in A.P. circuit as "News and Current Events".
52. Varta Tarangini 155	257.32	-do-	-do-	-do-	-do-
53. Varta Tarangini 156	235.67	-do-	-do-	-do-	-do-
54. Mahitichitra 495	243.84	Asstt. Dir. of Inf. (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab. Ltd., 77-Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-18.			Release in Gujarat Circuit as "N & CE"

1	2	3	4	5	6
55.	News Magazine No. 173-A. G-15. South Cooperation	404.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		General Release as "N & CE"
56.	Chakram	73.00	-do-		Rel. in A.P. Circuit as "Documentary"
57.	Valayam	72.00	-do-		Rel. in Kerala circuit as "Documentary"
58.	Chakra	76.00	-do-		Rel. in Oriya Circuit as "Documentary"
59.	Chakra	81.00	-do-		Rel. in Assam circuit as "Documentary"
60.	Chakra	73.00	-do-		Rel. in W. Bengal as "Documentary"
61.	Chakram	76.00	-do-		Rel. in Tamil Nadu as "Documentary"
62.	Chakra	70.00	-do-		Rel. in Karnataka as "Documentary"
63.	Vignya Mau	87.00	-do-		Rel. in Oriya circuit as "Documentary"
64.	Buddhimati Mau	97.00	-do-		Rel. in W. Bengal circuit as "Documentary"
65.	News Magazine 175	389.00	-do-		Rel. in All India circuit and classified as "N & CE"
66.	Dattihoca	301.00	-do-		General Release and classified as "Docu- mentary"
67.	Varta Tarangini 161	297.86	A.P.S.I.D.C. Ltd., 11-5-423/1, Lakdi-ka-Pool Hyderabad-500 004.		Rel. in A.P. circuit as "N & CE"
68.	Maharashtra News Magazine 448	275.21	P.S. Palekar, Asst. Dir. of Film, Dir. Gen. of Inf., Govt. of Maharashtra, Film Centre, Bombay.		Rel. in Maharashtra Circuit and classified as "N & CE".
69.	News Magazine 174 (looking forward part II)	348.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		General Release as "Documentary"
70.	Chakra	68.00	-do-		Rel. in Maharashtra circuit as "Documen- tary".
71.	Chakra	73.00	-do-		Rel. in Gujarat as "Documentary"
72.	Bengal, Glumpes of a glorious Epoch	600.00	Jyotirmoy Roy, 15, Motilal Nehru Road, Calcutta-700 029.		General release as "Documentary"
73.	Varta Tarangini 160	364.02	Andhra Pradesh State Film Develop. Corpn., 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004.		Rel. in A.P. circuit as "N&CE"

1	2	3	4	5	6
74.	News Magazine 173 (For equality and Justice)	332.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		General Release as "N & CF"
75.	Dast Lagte Hi	70.00	-do-		Gen. Release as "Doc".
76.	Samajhdar Maa	109.00	-do-		-do-
77.	Vivekamana Annai	94.18	-do-		Re. in Tamil Nadu circuit as "Doc".
78.	Tele Vai Na Thalli	92.66	-do-		Re. in A.P. as "Doc".
79.	Jaane Thaaye	103.02	-do-		Rel. in Karnataka circuit as "Documen- tary"
80.	Vivekamulla Amma	88.70	-do-		Rel. in Kerala as "Doc".
81.	Gyani Matri	98.45	-do-		Rel. in Assam circuit as "Documentary"
82.	Andhra Vishwas	84.00	-do-		Rel. in Gujarat circuit as "Documentary"
83.	Muda Nambikkai	72.00	-do-		Release in Tamil Nadu as "Documentary"
84.	Andha Vishwasani	78.88	-do-		Rel. in A.P. as "Doc".
85.	Muuda Nambeke	90.83	-do-		Rel. in Karnataka as "Doc."
86.	Andhavishwasam	74.07	-do-		Rel. in Kerala District as "Doc."
87.	Andha Vishwas	76.20	-do-		Rel. in Assam circuit as "Documentary"
88.	Andhabishwas	69.00	-do-		Rel. in W. Bengal as "Doc".
89.	Andhabiswas	76.00	-do-		Rel. in Orissa circuit as "Documentary"
90.	O.R.S. Ka Mishran	88.00	-do-		Gen. Rel. as "doc".
91.	ORS Da Ghol	87.99	-do-		Rel. in Punjab, Haryana, Delhi as "Documentary"
92.	Dast Lagne Ke Karan	67.00	-do-		Gen. Rel. as "Docu- mentary"
93.	Dast Lagde Hi	72.00	-do-		Re. in Punjab, Haryana, Delhi as "Documen- tary"
94.	ORS Ka ghol	83.00	-do-		Rel. in U.P., M.P., Bihar as "Documen- tary"
95.	Samajhdar Aai	101.00	-do-		Rel. in Maharashtra as "Documentary"
96.	Andh Vishwas	74.37	-do-		Gen. Rel. as "Doc".
97.	Samajhdar Pati	36.00	-do-		-do-
98.	Dast Lagan De Karan	62.00	-do-		Rel. in Punjab, Haryana, Delhi "Documentary"
99.	Dastan Ki Wajah	67.00	-do-		Rel. in UP, MP, Bihar, J & K as "Documentary"
100.	Vanashree Hich Danashree	395.00	P.S. Palekar, Asstt. Dir. of Film, Dir. Gen. of Inf., Govt. of Maharashtra Film Centre, Bombay-34.		Release in Maharashtra as "Documentary"

1	2	3	4	5	6
101.	Varta Tarangini 159	290.24	AP.S.F.D. 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004		Rel. in A.P. circuit as "N & CF"
102.	Thuffan Badithulanu Aadukondi	408.54	-do-		-do-
103.	Galucoma : A Race to Blindness	366.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Gen. Rel. as "Documentary"
104.	Jalsanjivani	76.00	-do-		Genl. in Maharashtra as "Doc"
105.	Jalsanjivani	72.54	-do-		Rel. in Gujarat as "Doc"
106.	O.R.S. Kalavai	80.47	-do-		Rel. in Tamil Nadu as "Documentary"
107.	O.R.S. Mishramam	82.06	-do-		Rel. in A.P. as 'Doc'
108.	O.R.S. Mishrana	84.12	-do-		Rel. in Karnataka as "Doc"
109.	O.R.S. Mishridham	70.71	-do-		Rel. in Kerala as "Doc"
110.	Sanjivani Pani	72.54	-do-		Rel. in Assam as "Doc"
111.	Sanjivani Bari	70.40	-do-		Rel. in Bengal as "Documentary"
112.	Jal Sanjivani	70.71	-do-		Rel. in Orissa as "Doc"
113.	Ek Samajhdar Maa	84.00	-do-		Gen. Rel. as "Doc"
114.	Ek Hoshiyar Maa	91.00	-do-		Rel. in UP, MP, Bihar, J & K
115.	Ek Sayani Maa	75.00	-do-		Rel. in Punjab, Delhi Haryana as "Doc"
116.	Vividh Pratibhaon Ka Sangam	578.16	Yogeshkant Bhageria, 40, Banarsi Dass Estate, Timarpur, Delhi-54.		Rel. in Rajasthan circuit and classified as "Doc"
117.	Maharashtra News Reel 447	268.00	P.S. Palekar, Asstt. Dir. (F) Dir. Gen. of Inf. & Pub. Rel. Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34		Rel. in Maharashtra circuit as "N & CF"
118.	Chamchi Jetil Sakhar ane chimti jetlu mithu	89.31	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Release in Gujarat circuit as "Documentary".
119.	Chamcha bhar sakhar & Chimut bhar meeth	89.00	-do-		Rel. in Maharashtra as "Documentary"
120.	Bediyai Neruthuvade Eleyade	87.18	-do-		Rel. in Tamil Nadu as "Documentary"
121.	Neella Verochanaala Nunchi Upasamanam Entho Sulabham	87.79	-do-		Rel. in A.P. circuit as "Documentary"
122.	Athibedi Endhe Sulabha Rakshane	95.04	-do-		Rel. in Karnataka as Documentary
123.	Vairellakkam Neyendrikan Ethare Elluppam	66.45	-do-		Release in Kerala as Documentary
124.	Atisar Theke Mukti	89.61	-do-		Rel. in West Bengal as Documentary.
125.	Atisarrumukti (Oriya)	75.29	-do-		Rel. in Orissa as "Documentary".
126.	Namak Chini Ka Mishran	77.00	-do-		Gen. Rel. as "Doc"
127.	Namak Chini Ka Ghol	95.00	-do-		Rel. in UP, MP, Bihar, J & K as Documentary.

128. Namak Chini da ghol	75.00	-do-	Rel. in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh as "Documentary"
129. Bhed Rogor Para Mukti	78.38	-do-	Rel. in Assam as Documentary.
130. Vishesh Maharashtra Samachar Chitra Kramank-4 (Apna Utsav)	292.00	P.S. Palekar, Asstt. Dir. (F) Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.	Rel. in Maharashtra circuit and classified as "Documentary" (and not N&CE)
131. Drugs	111.25	Ajay Singh Chudasama, C/o Yashnik Films, 10-A, Tinwala Bldg., Tribhuvan Road, Bombay-400 004.	Gen. Rel as "Doc".
132. Man Tai, of Assam	597.41	N.M. Barua, DO-RE-ME Films, 121, Collector Colony, Flat No. 1-C, Chembur, Bombay-74	Gen. Rel. and Classified as "Documentary"
133. News Magazine No. 176 (Looking forward Pt. III)	420.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Gen. Rel. and classified as Documentary (and not N&CE)
134. For Your Health	367.00	-do-	Gen. Rel. and classified as "Documentary"
135. Gauna	69.00	-do-	-do-
136. News Magazine No. 177 (USSR-India Friendship and Trust)	477.00	-do-	Gen. Rel. and classified as "News and Current Events"
137. Varta Tarangini 162	271.34	A.P.S.F.D.C. Hyderabad, 11-5-423/1, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004.	Re. in A.P. circuit and classified as "N & CE"
138. Bihar Darshan	387.76	Shri M. Jha, Film Producer Officer, and Inf. & Pub. Rel., Deptt. Govt. of Bihar, Patna	Rel. in Bihar circuit and classified as "Documentary"
139. Varta Tarangini 163	298.17	A.P.S.F.D.C. 11-5-423/1, Lakdi-ka-Pool Hyderabad.	Rel. in A.P. circuit as & "N & CE"
140. Bikash Ki Ore	518.14	Dir. of Inf. & Pub. Rel. Govt. of Bihar, Patna	Rel. in Bihar Circuit as "Documentary"
141. Maharashtra Newsreel No. 449	233.00	P.S. Palekar, Asstt. Dir. (F) Dir. Gen. of Inf. & Pub. Rel., Govt. of Maharashtra 68-Tardeo Road, Bombay-34.	Rel. in Maharashtra circuit as "N & CE"
142. Prashna	445.92	Telugu Chitra, 6-1-508/A/18, Khairatoad, Hyderabad-500 004.	Rel. in A.P. circuit as "Doc"
143. Mahiti Chitra No. 496	234.70	Asstt. Dir. of Inf. (F) Govt. of Gujarat, Ramnord Res. Lab, 77-Dr. A.B. Road, Bombay-18.	Rel. in Gujarat circuit as "N & CE"

1	2	3	4	5	6
144. News Magazine No. 178	417.00	Film Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Gen. Rel. as "N & CE"	
145. News Magazine No. 178-A	540.00	-do-		Gen. Rel. as "Documentary"	
146. News Magazine 179 (Broad- casting : Winds of Change)	501.00	-do-		Gen. Rel. as "N & CE"	
147. Shaheed Ganesha Shankar Vidyarthi	329.00	-do-		Gen. Rel. as "Doc."	
148. News Magazine No. 179-A (The Eternal Journey)	373.00	-do-		Gen. Rel. as "N & CE"	
149. Varta Tarangini 164	279.88	A.P.S.F.D.C. 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-500 004.		Rel. in A P. circuit as "N & CE"	
150. Varta Tarangini 165	283.23	-do-		-do-	

[F. No. 315/1/90-F(P)]

आदेश

का. भा. 708 -- भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या का. भा. 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1988 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त, संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को, जिसका/जिनका विवरण उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया गया है, उसके/उनके सभी भाषा रूपांतरों के साथ स्वीकार करती है। (1-7-1989 से 31-12-1989 तक अनुमोदित फिल्में)।

अनुसूची

क्रम सं.	फिल्म का शीर्षक	फिल्म की संख्या (मीटर में)	आवेदनकर्ता का नाम	निर्माता का नाम	संक्षिप्त रूप देखा कि क्या फिल्म वैज्ञानिक फिल्म है या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है या समाचारों और समसामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्म है या वृत्तचित्र है।
1	2	3	4	5	6
1. न्यूज मैगजिन सं 152	526 00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026	मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग 24-पैडर रोड, बम्बई।	सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित तथा "समाचार तथा समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।	
2. मे हमारी धरती	21.76	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026			
3. बार्ता 140	289 67	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि, 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समाचार तथा समसाम- यिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।	
4. रेबोल्यूशन इंडियन एग्रिकल्चर	543 55	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित तथा "डाक्यूमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।	

1	2	3	4	5	6
5. महाराष्ट्र न्यूज सं. 436	436.00	श्री वी. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (फिल्म), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई-32	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय महाराष्ट्र सरकार फिल्म प्रभाग बम्बई ।	महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा “समाचार एवं समसामयिक घटनाओं” के रूप में वर्गीकृत ।	
6. न्यूज मैगजीन सं. 154	493.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित तथा “समाचार एवं समसामयिक घट- नाओं” के रूप में वर्गीकृत ।	
7. उज्ज्वल भविष्य की ओर (इलाहाबाद मंडल)	289.56	श्री धीरेन्द्र पांडे, निर्माता सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित “डायुमेटरी” के रूप वर्गीकृत	
8. न्यूज मैगजीन सं. 153	484.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित एवं “डायुमेटरी के रूप में वर्गीकृत” ।	
9. दि स्पीड पौटो	599.00	श्री वीरेन्द्र द्विवेदी, 104, सी गैल, ए. बी. नाथर रोड, गुठ, बम्बई-400049		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित एवं “डायुमेटरी” के रूप में वर्गीकृत” ।	
10. बार्ता तरंगिनी	214.63	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश सर्किट में सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित एवं “समाचार एवं सम- सामयिक घटनाओं” के रूप में वर्गीकृत ।	
11. सेंटर भव सुधारे	221.89	संयुक्त निदेशक (सूचना), गुजरात सरकार, धनराज्य महल, भू-तल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई-400039		गुजरात सर्किट में सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा “डायुमेटरी” के रूप में वर्गीकृत ।	
12. न्यूज मैगजीन नं. 153-ए	486.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित तथा “समाचार एवं समसामयिक घटनाओं” के रूप में वर्गीकृत ।	
13. देश की वाणी	598.00	--तथैव--		“क” तथा “ख” राज्यों सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित एवं “डायु- मेटरी” के रूप में वर्गीकृत ।	
14. दि रिन्यूबल आफ होप	594.36	डा. पी. के. राजहंस, विश्वजीत अपार्टमेंट्स, 35, नेहरू रोड, सांताक्रुज (ई.), बम्बई-400055		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित एवं “डायुमेटरी” के रूप में वर्गीकृत ।	
15. एनर्जी सिनेरियो	596.18	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		--तथैव--	
16. कब तक	549	--तथैव--		--तथैव--	

1	2	3	4	5	6
17. महाराष्ट्र समाचार सं. 437	190.00	श्री वं. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (एफ.) सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, "फिल्म केन्द्र, 68-ताडदेव रोड, बम्बई-34	निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क महाराष्ट्र सरकार, बम्बई-32	महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।	
18. महाराष्ट्र समाचार सं. 438	265.00	-- तदैव--	-- तदैव--	महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित एवं डाक्यु- मेंटरी के रूप में वर्गीकृत।	
19. विद्यालये वृत्ति	405.18	आंध्र प्रदेश राज्य विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश सकिट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।	
20. न्यूज मैगजीन सं. 155	479.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, ¹ 24-पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित एवं "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।	
21. न्यूज मैगजीन सं. 156	585.00	-- तदैव--		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु- मोदित एवं डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।	
22. महाराष्ट्र न्यूज सं. 439.	222.00	श्री वं. पी. भोंडे, सहायक निदेशक (फिल्म), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म केन्द्र, 68 ताडदेव रोड, बम्बई-34	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार बम्बई-43.	महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समा- चार एवं समसामयिक घट- नाओं के रूप में वर्गीकृत।	
23. वार्ता तरंगिनी 142	284.75	आंध्र प्रदेश राज्य 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004.	फिल्म विकास निगम लि.,	आंध्र प्रदेश सकिट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित एवं समाचार एवं समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत.	
24. न्यूज मैगजीन नं. 157	520.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 डॉ. जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-26.		सामान्य प्रदर्शन तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।	
25. शर्बी गुजरात	570.41	संयुक्त निदेशक (सूचना), गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर-380010.		केवल गुजरात सकिट में प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।	
26. जगद्गुरु श्री चंद्राचार्य	594.97	रवि मेहरा, 36 हरी मार्किट, खार (पश्चिम), बम्बई-52.		सामान्य रूप से प्रदर्शित एवं डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत	
27. अवर सोल्जर्स फार पीस	456.28	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-226.		डाक्युमेंटरी के रूप में सभी संस्करणों में सामान्य रूप से प्रदर्शित।	
28. वार्ता तरंगिनी नं. 143	356.40	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद- 500004.		समाचार एवं समसामयिक घट- नाएं तथा आंध्र प्रदेश सकिट में प्रदर्शित।	
29. लाईट हाऊस एंड नैविगेशन ऐड्स	493.00	श्री मार्क बैपटिस्ट, (हुअनार फिल्मस), नानाभाई नेशनल सर पी.एम. रोड, फोर्ट, बम्बई-400001.		सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।	

1	2	3	4	5	6
30. म्यूज मैगजीन नं. 158	364.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.			सामान्य रूप से प्रदर्शित "डाक्युमेंटरी"।
31. जन जंगल जल जमीन	222.49	फिल्म निर्माण अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क, बिहार सरकार पटना।	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, बिहार सरकार पटना।		बिहार सॉफ्ट में डाक्युमेंटरी के रूप में प्रदर्शित।
32. मेले और त्योहार	231.94	—तथैव—	—तथैव—		—तथैव—
33. सोहराब मोदी	594.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
34. अभिवरोधी पादामले भरेल्लू	331.40	प्रांथ प्रदेश राज्य विकास निगम, लि., 11-4-423/1, लकड़ी का पुल, हैवराबाद- 500004.			केवल प्रांथ देश में डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
35. महाराष्ट्र म्यूज रील 441.	300.00	श्री बी.पी. भोडे, सहायक निदेशक (फिल्मस), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म केन्द्र, 68, ताड्डेव रोड, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सॉफ्ट में डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
36. विशेष महाराष्ट्र समाचार विज्ञ, क्रमांक 3 (महाराष्ट्र विधानसभा, सुवर्ण महोत्सवी वर्ष)।	504.00	श्री बी.पी. भोडे, सहायक निदेशक (फिल्मस), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार फिल्म केन्द्र, 68 ताड्डेव रोड, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सॉफ्ट में डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
37. महाराष्ट्र म्यूज रील 442.	288.00	—तथैव—	—तथैव—		—तथैव—
38. मालती	607.99	राष्ट्रीय शिक्षा एवं सूचना फिल्म, लि. 67, मेकर्स पैम्बर्स 111, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021.			सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित एवं डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
39. गुजरात नौ विकास गाथा	600.00	संयुक्त निदेशक (सूचना), गुजरात सरकार, धनराज महल, भूतल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई-400039.			गुजरात सॉफ्ट में डाक्युमेंटरी के रूप प्रदर्शन में लिए अनु- मोदित।
40. राजा राधा	589.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, डा.जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.			सभी संस्करणों में डाक्युमेंटरी के रूप में सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित।
41. म्यूज मैगजीन नं. 158-ए, (मराठ्याची बोल कौतुके)	563.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, डा.जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.			महाराष्ट्र सॉफ्ट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समा- चार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
42. उत्तरोत्तर	228.60	सहायक निदेशक (सूचना), गुजरात सरकार, राममोई रिसर्च लैब लि., 77 डा. एनी बेसेंट रोड, बर्ली, बम्बई 400018.			गुजरात सॉफ्ट में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
43. आदिवासी विकासनी के दीये	259.8	—तथैव—			—तथैव—
44. सकल जनांचा अवाक	325.00	श्री बी. भोडे, सहायक निदेशक, (एफ), सूचना एवं जनसंपर्क, निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केन्द्र, 68, ताड्डेव रोड, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सॉफ्ट में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "डाक्यु- मेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।

1	2	3	4	5	6
45. साकार सपने	484.02	धीरेन्द्र पांडे, निर्माता न्यूजरील, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर देश सरकार लखनऊ।			उत्तर प्रदेश सकिट में प्रदर्शित के लिए अनुमोदित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
46. न्यूज मैगजीन नं. 159. (इंडिया ए निशिंग डेमोन्स्ट्री)	541.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, डा. जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा समाचारों एवं समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
47. प्रवर प्रोल्ड मास्टर्स क्रिकेट	329.18	-तदैव-			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
48. बि एल्फाबेट	582.00	श्रीमती सुमति शिवराज, मै. सुवर्णावानी-001, एच. अष्टिकेश, अपना घर, अंधेरी (प०) बम्बई-58.	श्रीमती सालीन जोसेफ, 001 एच. अष्टिकेश, अपना घर, अंधेरी (प०), बम्बई-58.		केरल सकिट में प्रदर्शित तथा शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत।
49. नवीं क्षितिज नं. 4 प्राशा		श्री बी.पी. भोडे, सहायक निदेशक (फिल्म), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केंद्र, 68 ताड़देव रोड, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
50. घर सजाले	235.00	-तदैव-			केवल महाराष्ट्र में प्रदर्शित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
51. सार्ई ट्री	179.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, डा. जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-400026.			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
52. पांडुरा सोनायची की माया	237.00	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केंद्र, 68, ताड़देव रोड, बम्बई-34			महाराष्ट्र में प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
53. हाथ अपना है मगर	344.73	-तदैव-			-तदैव-
54. मिश्रित चित्र	152.40	सहायक सूचना निदेशक (फिल्म), गुजरात सरकार, 77, डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-18			गुजरात सकिट में प्रदर्शित समाचार एवं समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
55. रेनबो	62.00	श्री बी.ए. नाडकर्णी, प्लॉट नं. 13, रोड नं. 1, पेंडसे नगर, डोम्बीविली (पूर्व), जिला धाणे।			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
56. मबर लेई	80.00	श्री बी.ए. नाडकर्णी, प्लॉट नं. 33, रोड नं. 1, पेंडसे नगर, डोम्बीविली (पूर्व), जिला धाणे।			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
57. बी. बेरिश हिज मेमोरी	248.10	श्री रमेश डी पटेल, 1/2, उन्नत नगर, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई-62.			-तदैव-
58. उत्तरोत्तर	228.60	सहायक सूचना निदेशक (फिल्म), गुजरात सरकार रामोई रिसर्च लेब 77 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-18.			गुजरात सकिट में प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
59. भाविवासी बिकासिनी के बीर्यं।	259.00	-तदैव-			-तदैव-
60. न्यूज मैगजीन नं. 158-ए, (मराठांची बोल कोतुके)	563.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, डा. जी. देशमुख मार्ग, बम्बई-26.			महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शित तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
61. सकल जनांच। अवास	325.00	श्री बी.पी. भोडे, सहायक निदेशक (फिल्म), महाराष्ट्र सरकार फिल्म केंद्र, 68, ताड़देव रोड, बम्बई-34.			-तदैव-

1	2	3	4	5	6
62. साकार सपने	484.02	श्री धीरेन्द्र पांडे, प्रोड्यूसर न्यूजरील, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।			उत्तर प्रदेश सकिट में प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
63. महिती चित्र 489	265.18	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनोई रिसर्च लैब।			गुजरात सकिट में प्रदर्शित तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
64. महाराष्ट्र न्यूजरील	279.00	श्री वी.पी. भोंडे, महाराष्ट्र सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, फिल्म केन्द्र, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शित तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
65. महाराष्ट्र न्यूजरील 443	279.00	-तदैव-			-तदैव-
66. वार्ता तरंगिनी	270.42	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम, 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।			आंध्र प्रदेश सकिट में प्रदर्शित तथा "समाचार एवं सम- सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
67. ओकन ड्रीम	122.22	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26.			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
68. ए कमिटमेंट पीस	492.00	-तदैव-			-तदैव-
69. न्यूज मैगजीन नं. 160, (न्यू गवर्नमेंट न्यू बिगसिह)	318.00	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "समाचार एवं समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत।
70. हिरवी गरडी	300.40	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केन्द्र, 68, ताड़वे रोड, बम्बई-34.			महाराष्ट्र सकिट में प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।
71. जवाहरलाल नेहरू	487.68	धीरेन्द्र पांडे, जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।			डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
72. उज्जवल भविष्य की ओर	291.00	धीरेन्द्र पांडे, जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।			उत्तर प्रदेश सकिट में प्रदर्शित तथा डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।
73. ए न्वाइट रेवोल्यूशन।	262.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26,			सामान्य रूप से प्रदर्शित तथा "डाक्युमेंटरी" के रूप में वर्गीकृत।

[फा.सं. 315[1/89-एफ (पी)]

विजय कुमार, डेस्क अधिकारी

ORDER

S.O. 708.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the first Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule pertaining to the period 1-7-1989 to 31-12-1989.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the Applicant	Name of the producer	Brief synopsis whether a scientific film or for educational purpose or a film dealing with news & current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	News Magazine No. 152	526.00	The Chief Producer films Division, 24-Peddar Road Bombay-400026	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	Approved for general release and classified as "News and Current events"

1	2	3	4	6	6
2. Ye Hamari Dharti	216.76	The Chief Producer, Film Division, Bombay-400026			Approved for general release and classified as "News and Current Events"
3. Varta Tarangini 140	289.67	Andhra Pradesh State, Film Development Copn. Ltd. 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad 500004.			Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News and Current Events".
4. Revolution Indian Agriculture	545.55	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.			Approved for general release and classified as "Documentary".
5. Maharashtra News No. 436.	436.00	Shri V.P. Bhonede, Asstt. Dir. (Films) Dir. Gen. of Inf. & P.R., Govt. of Maharashtra. Bombay-32.	Dir. Gen. Inf. & P.R., Govt. of Maharashtra. Bombay.		Approved for general release in Maharashtra circuit and classified as News and current Events.
6. News Magazine No. 154.	493.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.			Approved for general release and classified "News and current event"
7. Ujjawal Bhavishya Ki Ore (Allahabad Mandal)	289.56	Shri Dharendra Pande, Producer, Dir. Gen. of Inf. & Public Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.			Approved by release in Uttar Pradesh Circuits and classified as "Documentary".
8. News Magazine No. 153.	484.00	The Chief Producer, Film Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.			Approved for general and classified as "Documentary"
9. The Seed Potato	599.00	Shri Virendra Dwivedi 104 Sea Shell A.B. Nair Road, Juhu, Bombay-400049.			-do-
10. Varta Tarangini 141	214.63	Andhra Pradesh State Film Divl. Corpn. Ltd., 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad 500004.			Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as News and Current Events".
11. Bhanter Bhav Sudhare	221.89	Jt. Dir. of Information Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal Gr. Fl. Chhatrapati Shivaji, Maharaj Marg, Bombay-400039			Approved for release in Gujarat circuit and Classified as "Documentary".
12. News Magazine No. 153-A	486.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.			Approved for general release and classified as "News and Current Events".
13. Desh Ki Vani	98.900	-do-			Approved for release in 'A' & 'B' States and classified as "Documentary".
14. The Renewal of Hope	594.36	Dr. P.K. Rajhuns Vishwajit Santa Apts., 35 Nehru Road, Santa Cruz (E), Bombay-400055			Approved for general release and classified as "Documentary"
15. Energy Scenario	596.18	The Chief Producer, Film Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.			-do-
16. Kab tak	549.00	-do-			-do-
17. Maharashtra News No. 437	190.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir (F) Dir Gen. of Inf. & Pub. Relations Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68 Tardeo Road, Bombay-34	Dir. Gen. of Inf. & Public Relations Govt. of Maharashtra, Bombay-32		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News and current events".
18. Maharashtra News No. 438	265.00	-do-	-do-		Approved for release in Maharashtra Circuit and classified as ocumentary

1	2	3	4	5	6
19. Vidyatho vruthi	405.18	Andhra Pradesh State Devl. Corpn. Ltd., 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad-500004.			Approved or release in A.P. circuit and classified as "Documentary."
20. News Magazine No. 156	479.00	The Chief Producer, Films Division 24, Peddar Road, Bombay, 26.			Approved for general release and classified as "News and Current Events".
21. News Magazine No. 156	585.00	-do-			Approved for general releases and classified as "Documentary"
22. Maharashtra News No. 439.	222.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. Films. Dir. Gen. of Inf. & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68 Tardeo Road, Bombay, 34.	Dir. Gen. of Inf. Govt. of Maharashtra Bombay, 32.		Approved or release in Maharashtra circuit and classified as News and Current events"
23. Varta Tarangi 142	284.75	Andhra Pradesh State Film Development Corpn. Ltd. 11/5/423-1 Lakdikapool Hyderabad-500004.			Approved for release in A.P. circuit and classified as News and Current Events"
24. News Magazine No. 157	520.00	Films Division Govt. of India 24, Dr. G. Deshmukh Mg., Bombay, 26.			General Release "News and Current Events."
25. Garvi Gujarat	570.41	Jt. Director of Inf. Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhinar-382010			Release in Gujarat circuit only. classified as Documentary.
26. Jagadguru Srichandracharya	594.97	Ravi Mehra 36, Hari Market Khar (w.) Bombay, 52.			General release and classified as documentary.
27. Our Soldiers or Peace	456.28	Films Division 24, Peddar Road, Bombay-26.			General Release Documentary in all versions.
28. Varta Taragini 143	356.40	Andhra Pradesh State Film Development Corpn. 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-500004.			News and Current Events and release in Andhra Pradesh circuit.
29. Light houses and Navigation Aids	493.00	Shri Marc Baptisia, (Hunnar Films, Nanabhoy Mansion, Sir. P.M. Road, Fort. Bombay-400001.			General release classified as "documentary"
30. News Magazine No. 158	364.00	Films Division 24, Peddar Road Bombay, 26.			General release "documentary".
31. Jan Jungle Jal Jamine	222.49	Film Prod. Officer, Information & Public Relations, Govt. of Bihar Patna.	Dir. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Bihar, Patna.		Bihar circuit as Documentary.
32. Mele aur Teohar	231.94	-do-	-do-		-do-
33. Sohrab Modi	594.00	Film Division 24, Peddar Road, Bombay-26.			General release category "documentary"
34. Abhivrodhipadamlo Arellu	331.40	A.P. State Develop. Corpn. Ltd. 11-5-423/1, Lakdikapool Hyderabad-500004.			Andhra Pradesh circuit only "Documentary"
35. Maharashtra News Reel 441	330.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. (Films). Dir. Gen. of Inf. & Pub. Relations Govt. of Maharashtra Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-34.			Maharashtra circuit classified as Documentary
36. Vishesh Maharashtra Samachar Chitra Kramank "3 (Maharashtra Vidhan Sabha Suvarna, Mahotsavi Varsha)	504.00	-do-	-do-		-do-
37. Maharashtra News Reel 442.	288.00	-do-			
38. Malati	607.99	National Educational & Information Films Ltd., 67, Maker Chambers III, Nariman Point. Bombay-400021.			Approved for General Release classified as "Documentary"

1	2	3	4	5	6
39. Gujarat Ni Vikas Gatha	600.00	Joint Director of Inf. Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Ground floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-400039			Approved for release in Gujarat circuit as "Documentary."
40. Raja-Radha	589.00	Films Division, Govt. of India, 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.			Approved for General release, as "Documentary" on all its versions.
41. News Magazine No. 158, A (Marhathachi Bol Kautuke)	563.00	-do-			Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "New and current events."
42. Uttartotar	228.60	Asstt. Dir. of Inf. Govt. of Gujarat Ramnord Research Lab. Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.			Approved for release in Gujarat circuit classified as 'Documentary'.
43. Adivasi-Vikasni Ke Diey	259.08	-do-			-do-
44. Sakal Janancha Adharu	325.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. (P), Dir. Genl. of Inf. and Public Relations Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			Approved for release in Maharashtra circuit & classified as 'Documentary'.
45. Sakar Sapne	484.02	Dhirendra Pande, Producer Newsreel, Directorate of Information & Public Relations Govt. of U.P. Lucknow.			Approved for release in U.P. circuit, and classified as 'Documentary'.
46. News Magazine No. 159 (India : A Living Democracy)	541.00	Films Division, Govt. of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.			General Release and classified as "News and Current Events".
47. Our Old Masters—Cricket	329.18	-do-			General Release and classified as "Documentary".
48. The Alhabat	582.00	Mrs. Sumati Shivraj, M/s. Suvarnawani 001, H. Rishikesh, Apna Ghar, Andheri (W) Bombay-58.	Mrs. Saleen Joseph, 001, H. Rishikesh, Apna Ghar, Andheri (W) Bombay-58.		Release in Kerala circuit and classified as 'Educational'.
49. Navi Kshitija Navya Aasha		Shri V.P. Bhonde, Asstt. Director (Films) Dir. Gen. of Inf. and Public Relations, Government of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			Release in Maharashtra circuit and classified as 'Documentary'.
50. Ghar Sajale	235.00	-do-			Release in Maharashtra only and classified as 'Documentary'.
51. My Tree	179.00	Films Division, Govt. of India, Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-400026.			General release classified as 'Documentary'.
52. Haath Apna Hai Magar	344.73	-do-			-do-
53. Pandhrya Sonyachi Kimaya	237.00	Dir. Genl. of Inf. & Pub. Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			Release in Maharashtra circuit as "Documentary".
54. Mahiti Chitra 490	152.40	Asstt. Dir. of Inf. (Films) Govt. of Gujarat, 77-Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.			Release in Gujarat circuit as "News and Current Events".
55. Rainbow	62.00	Shri V.A. Nadkerni, Plot No. 13, Road No. 1, Pendse Nagar, Dombivli (E) Dist. Thane.			General release and classified as "Documentary".
56. Motherland	80.00	-do-			-do-
57. We Cherish his Memory	148.10	Shri Ramesh D. Patel 1/2, Unnat Nagar Goregaon (W), Bombay-62.			-do-
58. Uttartotar	228.60	Asstt. Dir. of Inf. (F) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab., 77-Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18			Release in Gujarat circuit and classified as "Documentary".
59. Adivasi-Vikasni Ke Diey	250.08	-do-			-do-

1	2	3	4	5	6
60. News Magazine No. 158-A (Marhathachi Bol Kautuke)	563.00	Films Division, Govt. of India, 24-Dr. G. Deshmukh Marg, Bombay-26.			Rel ase in Maharashtra circuit and classified as "News and current Events".
61. Sakal Janancha Adharu	325.00	Shri V.P. Bhonde, Asstt. Dir. (Films) Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			-do-
62. Sakar Sapne	484.02	Shri Dharendra Pande, Producer Newsreel, Dir. Inf. & Pub. Rel. Govt. of U.P. Lucknow.			Release in U.P. circuit and classified as "Documentary"
63. Mahiti Chitra 489	265.18	Asstt. Dir. of Inf. Govt. of Gujarat Ramnord Res. Lab. 77, Dr. A.B. Road Worli Bombay-18.			Release in Gujarat circuit and classified as "New and Current Events".
64. Maharashtra News Reel 440	279.00	Shri V.P. Bhonde, Govt. of Maharashtra, Dir. Gen. of Inf. & Pub. Rel. Film Centre, Bombay-34.			Release in Maharashtra circuit as "News & Current Event".
65. Maharashtra News Reel 443	279.00		-do-		-do-
66. Varta Tarangini 144	270.42	Andhra Pradesh State Film Divn. Corpn. 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad.			Release in A.P. circuit as "News and Current Events".
67. Broken Dream	122.22	Films Division, 24-G. Deshmukh Marg, Bombay-26.			General Release as "Documentary."
68. A Commitment to Peace	492.00		-do-		-do-
69. News Magazine No. 160 (New Governments new beginnings)	318.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26			General Release as "News and Current Events".
70. Hirvi Gardi	300.40	Dir. Gen. of Inf. & Pub. Rel. Govt. of Maharashtra. Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.			Release in Maharashtra circuit and classified as "Documentary".
71. Jawaharlal Nehru	487.68	Dhirendra Pande, Dir. of Public Rel., Govt. of Uttar Pradesh Lucknow.			General Release as "Documentary".
72. Ujwal Bhavishya Ki Ore.	291.00		-do-		Release in Uttar Pradesh circuit and classified as documentary.
73. A Quiet Revolution	262.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.			General release and classified as "Documentary"

[F.No. 315/1/89-F(P)]

VIJAY KUMAR, Desk Officer.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का.आ. 70) :—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 3 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल और अगला आदेश जारी होने तक उक्त बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है:—

1. श्री शक्ति सामंत
2. श्री मनमोहन पेट्टी
3. श्री राकेश मिश्रा
4. श्रीमती प्रणयनी मुशी

5. सुश्री दीप्ति तवल
6. श्री बासु भट्टाचार्य
7. श्रीमती सरोजनी मुतैया
8. श्री ए. बी. बालमुब्रमण्यम
9. श्री जेमिनी गणेशन
10. श्री बी. आर. वेंकटाचेलूम
11. श्रीमती नन्दिना कृष्णा
12. श्री अजय डे
13. श्री पी. सेनगुप्ता
14. श्री हर्ष कुमार नेवनिया
15. श्रीमती जीवाराज अल्वा
16. श्रीमती एन. कालीश्वरन
17. श्री पी.के. पदमण

18. श्री टी. सुब्बारासी रेड्डी
19. श्री जे. भास्कर राव
20. श्री अमरेन्द्र सारण
21. श्री राज विसरिया
22. श्रीमती सारा मोहम्मद
23. श्रीमती कमला मानकेकर
24. श्री दिलजीतसिंह पन्नून
25. श्रीमती उर्वशी तलवार

2. उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऊपर बताए अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पुनर्गठन के साथ ही वर्तमान सदस्य (क्रम सं. 1, 2, 8, 9, 12, 18 तथा 23 को छोड़कर)* तत्काल बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे।

- * 1. श्री शक्ति सामंत
2. श्री मनमोहन शेट्टी
8. श्री ए. वी. बालसुब्रमण्यम
9. श्री जेमिनी गणेशन
12. श्री अजय डे
18. श्री टी. सुब्बारासी रेड्डी
23. श्रीमती कमला मानकेकर

[फाइल संख्या-809/1/91-एफ. (सी.)]

एस. लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 19th February, 1991

S.O. 709.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 3 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and in supersession of earlier Notifications on the subject, the Central Government is pleased to reconstitute the Central Board of Film Certification and appoint the following persons as members of the said Board with immediate effect until further orders :—

1. Shri Shakti Samanta
2. Shri Manmohan Shetty
3. Shri Rakesh Sinha
4. Smt. Pranayani Munshi
5. Ms. Dipti Naval
6. Shri Basu Bhattacharya
7. Smt. Sarojini Muthiah
8. Shri A. V. Balasubramaniam
9. Shri Gemini Ganesan
10. Shri V. R. Venkatachalam
11. Smt. Nandita Krishna
12. Shri Ajoy De
13. Shri P. Sengupta
14. Shri Harsh Kumar Neotia
15. Smt. Jeevaraj Alva
16. Smt. N. Kalceswaran
17. Shri P. K. Padman
18. Shri T. Subbarami Reddy
19. Shri J. Bhaskara Rao
20. Shri Amarendra Saran
21. Shri Raj Bisaria
22. Smt. Sara Mohammed
23. Smt. Kamala Mankekar
24. Shri Diljit Singh Pannun
25. Smt. Urvashi Talwar.

2. In exercise of the aforesaid powers, the Central Government also directs that with the reconstitution of the

Central Board of Film Certification as mentioned above, the existing members (except S. Nos. 1, 2, 8, 9, 12, 18 and 23) shall cease to be members of the Board with immediate effect.

- * 1. Shri Shakti Samanta
2. Shri Manmohan Shetty
- 8 Shri A. V. Balasubramaniam
9. Shri Gemini Ganesan
12. Shri Ajoy De
18. Shri T. Subbarami Reddy
23. Smt. Kamala Mankekar

[File No. 809/1/91-F(C)]

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार आयोग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1991

का.आ. 710.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुमर्ण में, संचार मंत्रालय, दूरसंचार आयोग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है :—

1. दूरसंचार जिला अभियंता, अलमोड़ा।
2. प्रभारी दूरभाष केन्द्र, रानी खेत (अलमोड़ा)।

[सं. ई. 11027/2/88-रा.भा.]

ओ.पी. वर्मा, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Telecom. Commission)

New Delhi, the 6th February, 1991

S.O. 710.—In pursuance of Rule 10(4) of the Official Language (for the use of official purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of Ministry of Communications, Telecommunications Commission where of more than 80% staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. Telecom. District Engineer—Almora.
2. Telephone Exchange Ranikhet (Almora).

[No. F-11027/2/88-OL]

O. P. VERMA, Director (OL)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

का.आ. 711:—सरकारी स्थापना (अप्राधिकृत अधि-भोगियों की बेइखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा रेल मंत्रालय के 8 अक्टूबर, 1985 के एस.ओ. 5068 में भारत सरकार की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में कालम (1) के अन्तर्गत क्रम सं. (VII), (VIII), (IX) तथा (X) के सामने

की गई इन्दराजों में "और वालतेर, दक्षिण पूर्व रेलवे", शब्दों के लिए जहाँ भी ये आए हों, "वालतेर तथा सम्बलपुर मंडल, दक्षिण-पूर्व रेलवे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फाइल सं. 82/डब्ल्यू. 2/14/4]

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं
इन्की ओर से,
मसीहुज्जमा, सचिव (रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 20th February, 1991

S.O. 711.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Railways No. S.O. 5068 dated 8th October, 1985, namely :—

In the Table to the said notification, in the entries against the Serial Nos. (vii), (viii), (ix) and (x) under column (1) for the words "and Waltair, South Eastern Railways" wherever they occur, the words "Waltair and Sambalpur Division, South Eastern Railway" shall be substituted.

[File No. 82/W-2/14/4]

For and on behalf of President of India
MASIHUZZAMAN, Secy. (Railway Board)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1991

का.आ. 712:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. पाण्डुरंग टिम्ब्लो इण्डस्ट्रीज, मार्गो के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-2-1991 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th February, 1991

S.O. 712.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Panduranga Timblo Industries, Margao and their workmen, which was received by the Central Government on 11-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/36 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Panduranga Timblo Industries, Margao,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. V. Cuncolienkar Labour Consultant.

For the Workmen—Shri Subhas Naik, Union Representative.

INDUSTRY : Iron Ore Mines

STATE : Goa

Bombay, the 1st February, 1991

AWARD

The Central Government by their Order No. L-29012/33/89-IR (Misc.) dated 25-8-1989 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

"Whether the action of the management of M/s. Panduranga Timblo Industries, Margao in terminating the services of Smt. Amruti Naik, Cook at Talaulum Mines w.e.f. October, 1988 is justified? If not, what relief is the said workmen entitled to?"

2. The Joint Secretary of the Goa Mining Labour Welfare Union filed the statement of claim (Ex. 2) challenging the said action of the management.

3. Thereafter while the reference was at the stage of filing written statement by the management, the partner of the management filed an application (Ex. 3) stating that the matter is already mutually settled between them and the workman, and that an amount of Rs. 12,635 has already been paid to the lady in question i.e. Smt. Amruti Naik by Cheque No. 0853919 dated 4-1-1991, and as such the matter may be disposed of. The representative of the Union also made an endorsement below that application that the matter is settled and as such it be disposed of. The management also produced zerox copy of the receipt (Ex. 4) passed by the said lady in favour of the management. The said lady clearly stated in that document that she has received the amount of Rs. 12,635 in full and final settlement of all legal dues in terms of the mutual settlement and that she has no further claim of whatsoever nature against the management, and that she intends to withdraw the present case pending before this Tribunal. Therefore, as the matter is amicably settled as above, the present reference stands disposed of.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-29012/33/89-IR (Misc.)]

का.आ. 713:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सिलवेस्टर एण्ड कम्पनी बम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-2-1991 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 713.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Sylvester and Co. Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 11-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/55 of 1987

PARTIES :

Employer in relation to the management of M/s. Sylvester and Co., Bombay

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Namjoshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. R. Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Maharashtra

Bombay, the 1st February, 1991

AWARD PART II

By Award Part I Issue No. 3 was tried as a preliminary issue and it has been held that this Central Government Industrial Tribunal No. 2 has jurisdiction to try the present reference made by the Central Government by their Order No. L-31012/7/87-D.IV (A) dated 15-10-1987. Rest of the issues are thus :—

- (1) Whether the termination of the services of the workman Shri R. G. Gaikwad by the management, without holding any domestic inquiry against him, is valid and legal ?
 - (2) Whether no proper opportunity was given to the said worker to defend himself, before his services were terminated by the management ?
 - (4) Whether the termination of the services of the said workman was not by way of punishment by the management ?
 - (5) Whether the action of the management of M/s. Sylvester and Co. Custom House Clearing and Forwarding Agents, operating in the major port of Bombay in relation to its Dock Department in terminating the services of Shri R. G. Gaikwad, Docks Clerk w.e.f. 1-7-1986, is justified ?
 - (6) If not, to what relief the said workman is entitled ?
 - (7) What Award ?
2. My findings on the said Issues are :—
- (1) Does not survive.
 - (2) Proper opportunity was given.
 - (4) Yes
 - (5) No
 - (6) As per Award below.
 - (7) As per Award below.

REASONS

3. The workman Shri R. G. Gaikwad filed his affidavit (Ex. 5) in support of his case, and he was cross-examined on behalf of the management. Claver Paul Fernandes, a partner of the management, i.e. M/s. Sylvester and Co., filed his affidavit (Ex. 73) in support of the case of the company. He was also cross-examined on behalf of the workman. By the letter dated 27-6-1986 (Ex. 12) the services of the workman were terminated by the said management. The last para of that letter stated that "because of your aforesaid persistent lapses, unauthorised, habitual absence, dereliction in duties, misappropriation of company's money, habitual and deliberate late attendance etc., the Company has lost confidence in you and has reluctantly been compelled to dispense your services with discharge simpliciter w.e.f. 1st July, 1986. You are advised to collect your dues from the Accountant of the Company, as early as possible". The said management witness referred to the different derelictions in duties in his affidavit and stated thus :—

The workman Shri R. G. Gaikwad was employed in their firm as a Dock Clerk from 1-10-1978. He committed major lapses/omissions, dereliction in duties, misappropriation of money etc., some of which are thus :—

He withheld 9 Way Bills pertaining to Voltas Ltd. for over a week instead of handing the mover to our office on the same day thereby making the company liable for payment of demurrage. He was asked to explain but he did not submit his explanation and was therefore warned by letter dated 27-12-1978. He frequently absented himself from duty without prior intimation or permission and frequently availed excess leave when not due. He was issued Memos, dated 13-6-79, 30-10-81, 24-4-1982 and 8-5-82. He cheated the company in collaboration with Mukadam by falsely showing engagement of extra labour. He was warned by letter dated 30-11-79 as his explanation dated 29-11-1979 was misleading and false. No extra labour was required in that behalf. He delayed the payment of wharfage and also delayed taking the delivery of the consignment. He was issued

a Memo, dated 18-3-80 calling for his explanation. His explanation dated 21-3-80 was misleading and false. He defrauded the company to the tune of Rs. 25 by claiming excess delivery charges than actually paid. Therefore he was issued with a Memo dated 20-11-80 calling for his explanation. But he did not submit his explanation. He misbehaved with the Foreman of Stevedores and gave misleading information to our office. Therefore he was issued a Memo dated 11-8-82 calling for his explanation. But he did not submit his explanation.

4. The said witness further stated in his affidavit that in spite of repeated advices, Memos and warnings given to Shri R. G. Gaikwad for his aforesaid lapses, omissions, habitual absence, misbehaviour, cheating and misappropriation of money, he continued to repeat the same and instead of improvement, he became adamant and indulged in the following lapses, omissions and commissions :—

He failed to register the containers at Manganese Ore Depot, in spite of specific instructions given to him and thereby incurred demurrage to the company. Therefore he was given a Memo dated 19-9-1984. He did not submit reply or explanation. He wrongly despatched the sample fibres to various transporters without keeping the office copies of the challans. Therefore he was issued a Memo dated 17-1-1985. Although he worked from 6.00 p.m. to 6.30 p.m. for loading the lorries in the Dock he made a fraudulent claim of overtime work from 6.00 p.m. to 10.00 p.m. and therefore he was issued a Memo dated 13-7-1985 and 13-8-1985 calling for his explanation. But he did not submit his explanation. He deliberately neglected tracing container No. TR1U 2800696 and therefore his explanation dated 3-4-86 for failing to trace the container was found quite unsatisfactory. Because of his deliberate negligence in tracing the container our company was held liable to steamer agents charges and Rs. 4,500 together with the container detention charges. This amount should have been recovered from Shri R. G. Gaikwad. But a lenient view was taken and he was spared with a warning dated 10-4-1986 as his explanation dated 3-4-86 was found most irresponsible and concocted. The said witness lastly stated in his affidavit that because of his aforesaid persistent lapses, unauthorised and habitual absence, dereliction in duties, misappropriation of company's money, habitual late attendance etc., the company management lost confidence in him and they were reluctantly compelled to dispense with his service as discharge simpliciter from 1-7-1986."

5. As such, according to the management, the termination of service of the said workman was only discharge simpliciter without any punishment. Even then I find that the said termination of the service of the workman falls within the definition of terms 'retrenchment'. Under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act 'retrenchment' means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. Therefore, the termination of service of the workman was retrenchment from service by the management, even though it is styled as discharge simpliciter by the management. In a recent case it has been held by the Supreme Court reported in Current Labour Reports (1990-Vol. II) (The Punjab Land Development and Reclamation Corporation Ltd. Vs. The Presiding Officer, Labour Court, Chandigarh and others), the retrenchment means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever except those expressly excluded in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. As the termination of the services of the workman was retrenchment from service, the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act should have been complied. In this case the provisions of Section 25-F have not been complied with. Under Section 25-F of the Act, no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until (a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of notice (b) the workman has been

paid at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months Admittedly, no retrenchment compensation was given by the management nor he has been paid one month's wages in lieu of notice. Further, admittedly he was in the service of the company for 8 years from 1978 to 1986. Therefore, the said termination of service of the workman by the management is not just, valid and legal. As such the workman in question will be entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity of service. In the present case only three days' notice was given by the management to the workman before his services were terminated with effect from 1-7-1986 by the letter dated 27-6-1986 (Ex. 15). According to the workman, his dismissal from service by the management was by way of punishment, and it was not a discharge simpliciter. Now, in case it is held that the said dismissal was by way of punishment, then it is an admitted fact that or no domestic enquiry was held against the workman for any of the charge and as such no charge was proved against him before his services were terminated by way of punishment. In that case also, the workman will be entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

6. The said management witness stated in his affidavit that after his discharge from the said company the workman was employed as Dock Clerk in the establishment of G. V. Pednekar, Custom House and Clearing Agents located at Devchaya, Jamsetji Dadaji Road, Bombay-400034. However, the workman stated in his affidavit that since his dismissal from service, he is unemployed all the while. Now, in case the workman was to be in service at at Bombay then he would have mentioned the place of his residence as Bombay, when his evidence was recorded in the Court. However, he stated his address as Parnai, Dist. Ahmednagar. Therefore, I find that since the date of his termination of service he is unemployed, and as such he is entitled to full back wages.

7. I find that the termination of service of the workman was not by way of punishment, but it was only discharge simpliciter which amounted to retrenchment in the present case. Further, he was given sufficient opportunity to defend himself when several Memos were issued to him. Therefore, Issues Nos. 1, 2, 4, 5 and 6 are found as mentioned above.

ISSUE No. 7

8. The following Award is, therefore, passed.

AWARD

- (i) The action of the management of M/s. Sylvester and Co., Custom House Clearing and Forwarding Agents, operating in the major port of Bombay in relation to its Dock Department in terminating the services of Shri R. G. Gaikwad, Dock Clerk w.e.f. 1-7-1986 is not justified.
- (ii) The said management is hereby directed to reinstate the said workman with full back wages and continuity of service immediately.
- (iii) The parties to bear their own costs of this reference.

Dated : 1-2-1991

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
[No. L-31012/7/87-D.IV (A)]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1991

का. आ. 714.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में हरियाणा मिनरल्स लि., (मार्बल माइन्स) नारनौल जि. महेंद्रगढ़ के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-2-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd February, 1991

S.O. 714.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Haryana Minerals Ltd. (Marble Mines) Narnaul (Mahindergarh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 7-2-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING;
OFFICER; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL; NEW DELHI

[I.D. No. 98/90]

In the matter of dispute between

Shri Raja Ram S/o Shri Prabhati Lal, Vill.
Mosampura, P. O. Sirohimoli, Distt.
Mohindergarh-123001.

Versus

The General Manager, M/s. Haryana Minerals
Ltd. (Marble Mines), Antri Biharipur,
Narnaul, Distt. Mohindergarh-123001.

APPEARANCES

None for the workman.

Shri Satish Kaushik Advocate for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L-29012/40/90-IR (Misc.) dated Nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of M/s. Haryana Minerals Ltd. in relation to their Antri Biharipur Mines in dismissing the services of Shri Raja Ram, Labourer w.e.f. 17-6-89 is just, fair and legal. If not, what relief the worker concerned is entitled to and from what date?"

2. The workman did not appear on 7-9-90, 12-11-90, 17-12-90, 21-12-90, 2-1-91 and 16-1-91. Though registered A.D. notice was sent to him for 16-1-91 but he did not appear. It appears that the workman is not interested in this case and I, therefore, pass No Dispute award in this case.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

January 16, 1991.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

[No. L-29012/40/90-IR (Misc.)

का. आ. 715.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन लखनऊ, उ. प्र के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 715.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Warehousing Corporation Lucknow (U.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 7-2-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 75/90

In the matter of dispute
BETWEEN

Shri Jagbir Singh, Ex-Sweeper, Gram Post Bhaipur, Jahangirabad, District Bulandshahr (U.P.)-203001.

Versus

Zonal Manager, Central Warehousing Corporation, 126/74, V. N. Road, Lalbagh, Lucknow-226001.

APPEARANCES

None for the Workman.

Shri N. Chaudhary for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012/1/90IR (Vividh) dated 7-1-90 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Central Warehousing Corporation, Lucknow in terminating the services of Shri Jagbir Singh, Sweeper, w.e.f. 7-11-86 (FN) is justified ? If not, what relief is the workman concerned entitled to ?”

2. The workman did not appear inspite of registered notices having sent to him 3-4 times. It appears that the workman is not interested in pursuing the case. I, therefore, pass a No Dispute award in this case. Parties to bear their own costs.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end. January 23, 1991.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer
[No. L-42012/1/90-IR(Vividh)]

का. आ 716 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एयर इंडिया, नई दिल्ली के प्रबंधन के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 716.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 7-2-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 93/88

In the matter of dispute
BETWEEN

Shri Hukam Chand, through A.R. & Co. General Secretary, Delhi Mazdoor Morcha, Gate State Bank, Tis Hazari Courts, Delhi.

Versus

M/s. Air India, Himalya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

APPEARANCES

None for the workman.

Mrs. Aditi Chaudhary for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. 11012/7/88-D.II(B)/D.III(B) dated 31-8-1988 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Air India, New Delhi in dismissing Sh. Hukam Chand, Loader from services w.e.f. 11-11-86 is justified. If not, to what relief the workman is entitled to ?”

2. The workman last appeared on 16-10-90 and did not attend the court on 26-11-90 nor on 18-12-90 nor on 23-1-91. Though registered A.D. notice was sent to him for 23-1-1991 but he did not appear. It appears that the workman is not interested in this case and I therefore, pass No Dispute award in this case.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end. January 23, 1991.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer
[No. L-11012/7/88-D.II(B)/D.III(B)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1991

का.आ. 717 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डी.आर.एम., पालघाट डिब्बीजन दक्षिण रेलवे,

पालघाट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म-कारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आलामुजाह्न के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 12-2-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th February, 1991

S.O. 717.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Alappuzha as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DRM, Palghat-Division, Southern Railway, Palghat and their workmen, which was received by the Central Government on 12-2-1991.

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ALAPPUZHA

(Dated this the 19th day of January, 1991)

I. D. No. 140/89

BETWEEN

The Divisional Railway Manager, Palghat Division,
Southern Railway, Palghat-678002, Kerala.

AND

The General Secretary, Dakshina Railway Casual Labour
Union, Edappalli North, Ettakulam, Cochin-682024,
Kerala.

REPRESENTATION :

M/s. M. Ramachandran and P. V. Abraham, Advocate
Cochin-682017—For Union.

AWARD

1. This industrial dispute is referred by the Government of India, Ministry of Labour by Order No. L-41011/59/80-IR(DU) dated 6-10-1989. The issues referred for adjudication read as follows :—

“Whether the action of the Divisional Railway Manager, Southern Railway, Palghat Division, Palghat, Kerala in terminating the services of female khalasies (list enclosed) working under the permanent Way Inspector, Southern Railway, Palghat, Kerala is justified? If not, to what relief the work women concerned are entitled?”

2. The services of fifteen workers out of sixteen were terminated on 21-6-1980. But in the case of one worker Meerakshy, the date of termination was on 20-11-1978. Admittedly, these workers were casually employed as Khalasies in the various projects works undertaken by the Palghat Division of Southern Railway. They were paid on daily basis. They were engaged on the basis of work sanctions obtained by the Officer from time to time. The details of period in which the workers concerned were working are given in the claim statement. I shall extract hereunder the name of each worker and period in which they were working :

1. Fathimabecvi	21-09-1973 to 20-06-1980
2. C. Panchali	21-11-1967 to 20-06-1980
3. P.K. Kalliyani	21-12-1986 to 20-06-1980
4. Thangamma	06-08-1969 to 20-06-1980
5. K. Kalliyani	21-11-1974 to 20-06-1980
6. Krishnaveni	21-11-1974 to 20-06-1980
7. Vijayamma 3	21-11-1974 to 20-06-1980
8. Sulojana	21-03-1974 to 20-06-1980
9. K. Ammini	26-09-1974 to 20-06-1980
10. Kamalam	21-02-1975 to 20-06-1980
11. Sathiyabhamai	21-02-1974 to 20-06-1980
12. P. Kesu	21-04-1975 to 20-06-1980
13. Lekshmikutty	21-11-1974 to 20-06-1980
14. R. Chellamma	26-09-1974 to 20-06-1980
15. Rugminiamma	26-09-1974 to 20-06-1980
16. Meenakshi	26-09-1974 to 20-11-1978

3. The union contends that without assigning any reason the services of the fifteen workers were terminated on 21-6-1980. Although they were entitled for 'temporary status' while they were working, they were not given any benefit of that kind. At last they had to approach the Labour Court for getting some of the monetary benefits. These female Khalasies while working along with other Male Khalasies, were doing all kinds of work. Since they were having more number of years of service they were entitled for regularisation in service or in the alternative they are entitled for terminal benefits in accordance with the provisions contained in the I. D. Act. Moreover, if their services were not terminated, they would have been screened for regularisation in service also.

4. In the counter statement filed by the Railways it is stated that all these workers concerned were engaged purely on casual basis. They were employed only for short durations. They were called for work depending upon the exigencies of the work. None of them had continuous service either for one year or for 240 days during the period of 12 calendar months preceding their date of termination for enabling them to receive any kind of terminal benefits. From the very beginning of their engagements, they were not having continuous service and their services were mostly irregular and there were intermittent breaks also. The engagement of these casual labourers was of casual in nature and the work assigned to these workers were not at all relating to renewal of railway tracks. Even among the male Khalasies or Men Mazdoors, there were different categories. The services of none of the workers concerned were required then because no work of casual nature was available. When these workers were employed on casual basis they were not paid the CPC scale. They would be entitled for temporary status and CPC scale of pay only if they would complete 180/120 days of continuous work without break. Since none of the workers did not have that much service, they were not entitled for any terminal benefits available to workers having temporary status. Regarding the contention of the union that while terminating the services of these workers the Railway had not complied with the provision contained in the I. D. Act, the contention of the Railways is that since none of them have service qualifications as contemplated in Section 25-B (2) of the I. D. Act there was no need for complying with the formalities contemplated in Section 25-F of the I. D. Act. According to them, for almost identical relief these workers had approached the High Court of Kerala earlier by filing O.P. No. 4178/80 and that writ petition was dismissed. However, in writ appeal while dismissing the writ petition the Division Bench of the High Court opined (in the judgment in WA No. 613/83) that the workers herein should seek remedy provided in the Industrial Dispute Act.

5. It is a fact that challenging the terminations and seeking declaration for their continuance in service, these workers had approached the High Court by filing writ petition. The Division Bench of the High Court has observed that the question whether each worker had completed 240 days or not is a matter concerning of facts and under Article 226 of the constitution such matters cannot be adjudicated. The High Court has also observed that the appropriate remedy for the workers is to invoke the provisions of the Industrial Dispute Act. In the light of that observation, the union moved the Labour Department of the Government of India and ultimately the matter was referred for adjudication to this Tribunal.

6. On the side of the union one of the workers concerned as also the Secretary of the union were examined. On the side of the management a Permanent Way Inspector attached to Palghat Division was also examined.

7. While perusing the reference order it can be seen that the only question to be decided is the validity of the termination effected in the case of the workers concerned in the dispute. The union's case is that these workers were having length of service varying from four years to 14 years. They are having continuous service as contemplated in Section 25-B of the I. D. Act. In view of that the terminations in their case were nothing but retrenchment and in that case their terminations should have been only in accordance with Section 25-G of the I. D. Act. Other contention raised in that in terms of Section 25-H of the I. D. Act, they are entitled for preferential right in the matter of employment also. It is also the case of the union that a casual labourer under railways will attain the temporary status on completion of 120 days of continuous service. To vindicate that position, union relies on Railway Manual (Chapter 25). According to them a casual labourer will attain temporary status if he/she has got 120 days of service during a period of six months.

8. Now let us examine the claims of the union. In the course of proceeding, the union filed a petition causing production of some of the documents which would show the service particulars of the workers concerned. They sought the production of original pay sheets, muster roll, service register (LTI Register), and service cards. The plea of the union on that behalf was resisted by the management through an affidavit stating that all the original pay sheets were destroyed on expiry of the period specified for the preservation of documents and that was in terms of Rule 2004 and 2005 of Indian Railway General Code. Regarding the service cards it is stated by the employer railways that those service cards should be only in the custody of the workers concerned. In relation to muster sheets it is stated that since preservation period is already over, those are not kept in the office. However they could produce muster sheets in relation to six of the casual labourers. They had produced the photo copies of the LTI register relating to these workers.

9. Ext. W-1 series are the photo copies of the service cards in respect of the workers concerned. The entries in Ext. W-1 series regarding the service particulars are tallying with the service particulars maintained by the Railways after verifying LTI register. Since the particulars contained in Ext. W-1 series are not varying with the service particulars furnished by the Railways the entries in W-1 series can be taken into account to make an assessment of the service details of each worker. It is a fact that none of them are having 240 days of continuous service during a period of 12 calendar months immediately preceding the date of termination. If we look at the service particulars it can be seen that during the initial period, these workers had worked almost all the days. After engaging them for about 200 days, there would be a gap extending to one month or two months. Because of that break, none of them would be eligible for making claim for 240 days of service. But while taking into account the total service rendered by each, it can be seen that they were having more than 240 days of service to their credit, but only thing is that those services were not at all continuous.

10. It is admitted in the counter statement filed by the Railways that these casual workers were employed on the basis of work sanctions given by the Railway administration. It appears that although the requirements of these workers were there to continue the work, sanction were

being given in such a manner that there would be some kind of break in the services of the workers concerned. Now the question is whether such a break can be included in the exclusion clause provided in Section 25-B of the I. D. Act. The union contends that such a break was not at all on account of any fault on the part of the workers. The delay in getting sanction was the real reason for it. If that position is accepted all these workers will have continuous service of more than 240 days so as to make them eligible to claim terminal benefits in accordance with the provisions contained in Section 25-F of the I. D. Act.

11. In the course of evidence it is revealed that so far as casual employment in Railways is concerned if a worker works continuously for 120 days, he would get temporary status. If the person having such temporary status is to be retrenched, he should be given 14 days' notice in terms of railways establishment manual chapter XXIII. If we go through Ext. W-1 series of service cards (photo copies) it can be seen that all these workers were having more than 120 days of service at the time of their termination, of course, with intermittent breaks. This position is not disputed by the Railways. WW-1 Fathimabeevi had rendered service to the Railways considerably for a long period i.e., from 1973 to 1980. She got casual employment for three days to thirty days during a period of one month.

12. In the counter statement filed by the management themselves it is admitted that casual employees are entitled for temporary status and CPC scale of pay if they complete 180/120 days of continuous service. But in the same breath in paragraph 7 of the counter statement they say that a person holding a post without a lien in the permanent post is not entitled to temporary status. Relying on a provision relating to temporary railway servant, it is contended by the Railways that even for getting temporary status to a casual labourer there must be a lien for him in a permanent post. This assumption is absolutely irrelevant for a situation now under discussion.

13. Section 25-F of the I. D. Act provides that a person who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched only by giving one month's notice in writing, giving reason for the retrenchment or in lieu of such notice one month's wages. It is also provided therein that while effecting such retrenchment compensation in terms of Section 25-F (b) should also be given. The service qualification viz., 'not less than one year' is explained in Section 25-B wherein it is stipulated that for the purpose of continuous service for one year a person need not work for one full year. It will be sufficient that he needs work only 240 days at any time during a period of 12 calendar months immediately preceding the date of retrenchment. Evidently, in this dispute, all the workers concerned had been under employment for more than one year, of course, with intermittent breaks in their service. Their length of service varies from four years to 14 years. Since the workers concerned were having service spread over for a period of more than one year at the time of their termination, it is not necessary that they should satisfy the other alternative condition that they should have worked for 240 days continuously during a period of 12 calendar months. If we analyse the true legislative intent, it can only mean that the insistence of 240 days is relevant for a situation where a worker could not work all the 12 calendar months immediately preceding the date of retrenchment. That is more evident if we look at the position that during the period of one year even if there is a break of three months continuously, the worker will be entitled for the benefits contemplated in Section 25-F of the I. D. Act, if he had at least 240 days of service to his credit at any time during a period spread over from eight to twelve months. If that be the position, the case of workers who had rendered service for several years stands at a different footing. No minimum continuous service of 240 days need not be insisted in their case because they had rendered more number of years of service. True, that is with intermittent breaks. Since all the workers concerned are having more than one year's of service, they are entitled for benefits as provided under Section 25-F of the I. D. Act. Thus, any kind of termination effected in their case not in compliance of Section 25-F of I. D. Act can only be declared as illegal and void.

14. Viewing the entire aspect through another compass, these employees are governed by Railway Establishment Manual also. A casual worker who has rendered 120 days of continuous service during a period of six months is entitled for 'temporary status'. The evidence adduced by the union is to the effect that a worker who satisfies the condition relating to 120 days of service within a period of six months could be retrenched only after giving 14 days of notice or in lieu of that wages for that period. The Railways may say that since the workers concerned in this dispute do not satisfy the service qualifications for getting even the temporary status, any reliance on the provision relating to retrenchment of persons having temporary status is of no relevance. If we go through the service cards Ext. W-1 series it can be seen that breakages in the service of these workers were effected in such a manner that their service shall not be continuous even for making claim for temporary status. After putting break to their services, they were called again to continue the same types of works. Explanation for it is given by the Railways saying that they could carry out the work only on the basis of sanction orders which would be contained from time to time from the Railway administration. Since the artificial break effected in the services of the workers herein is found to be not on account of any fault on their part, it can only be held that all of them satisfied the requirements even for conferring the temporary status. Evidently, while terminating their services, the Railway had not complied with the provisions contained in the Railway Establishment Manual also.

15. In view of the fact that the terminations were found to be illegal it is unnecessary to make any pronouncement on the questionability of the pleas made by the union relying on Section 25-G and H of the I. D. Act. In view of my declaration that the terminations effected in the case of these workers are illegal, they are entitled for reinstatement with back wages. For the purpose of calculation of their back wages, the total earning they had during the last 12 months immediately before the termination will be the wages for one year. For calculating the total wages, the fraction of any year less than half need not be taken into account. Till these works are validly terminated either in terms of I. D. Act or in terms of Railway Establishment Manual, they are deemed to continue in service.

Award is passed in the above terms.

(Dated this the 19th day of January, 1991).

K. KANAKACHANDRAN, Industrial Tribunal
[No. L-41011/59/89-IR (DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

APPENDIX

Witnesses examined on the side of the Union :
WW-1—Fathima Beevi.

WW-2—C. P. Menon.

Witness examined on the side of the Management :
MW-1—V. V. John.

Exhibits marked on the side of the Union :

W-1 (Series)—Photocopy of the Casual Labour Service cards.

Exhibits marked on the side of the Management :

M-1 (a)—Casual Labour Registers for the years from 1973 to 1980.

M-1 (b)—Casual Labour Registers for the year from 1974 to 1976.

M-1 (c)—Casual Labour Registers for the years from 1975 to 1978.

M-1 (d)—Casual Labour Registers for the years 1979 and 1986.

M-1 (e)—Casual Labour Registers for the years from 1976 to 1980.

का. आ. 718 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसूर भारत कोकिंग कोल लि. की कूया कोयलरी के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11/2/91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th February, 1991

S.O. 718.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kuiya Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 11-2-91.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 105 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 30th January, 1991

AWARD

By Order No. L-20012(100)/82-D.III(A)/I.R.(Coal.D) dated, the 26th April, 1990, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the workmen of Kuiya Colliery Bastacolla Area of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Jharia, Distt. Dhanbad that the workmen mentioned in the Annexure should be regularised and treated as departmental workmen is justified? If so, to what relief are the concerned workmen entitled?"

ANNEXURE

List of workmen

1. Panchanan Bouri.
2. Payarilal Yadav.
3. Sitarani.
4. Sokhilal Yadav.
5. Malinda Bouri.
6. Sobha Ram Yadav.
7. Mungaram Bouri.
8. Deojanan Yadav.
9. Anand Bouri.
10. Suresh Robidas.
11. Amulya Bouri.
12. Bisu Mahato.

13. Pana Bouri.
14. Somaru Yadav.
15. Sankar Bouri.
16. Sadan Yadav.
17. Ramlal B.P.
18. Alwa Manjhi.
19. Sonalal Manjhi.
20. Bhuchang Manjhi.
21. Ajan Manjhi.
22. Nanhu Manjhi.
23. Kisun Manjhi.
24. Lakhiya Manjhi.
25. Chandu Manjhi.
26. Sarada Manjhi.
27. Ratia Manjhi.
28. Lakhu Manjhi.
29. Jhumai Manjhi.
30. Alpi Manjhi.
31. Fulmoni Manjhi.
32. Kisundhari Bhua.
33. Hareram Khelewar.
34. Ramchandra Bhua.
35. Pitambar Khelewar.
36. Chandu Bhua.
37. Ubre Sawra.
38. Chalimoti Bai.
39. Madan Prasad.
40. Biswanath.
41. Sital Bhua.
42. Bateswar Manjhi.
43. Naresh Bhua.
44. Sanichr Manjhi.
45. Mohan Bhua.
46. Tirka Manjhi.
47. Bandhu Bhua.
48. Jaleswar Manjhi.
49. Lakhu Bhua.
50. Sarkar Manjhi.
51. Lal Manjhi.
52. Samlal Manjhi.
53. Ganu Manjhi.
54. Sarbeswar Bouri.
55. Sonaram Manjhi.
56. Sankar Bouri.
57. Gopal Manjhi.
58. Charku Bouri.
59. Ram Manjhi.
60. Pramod Kewat.
61. Jotilal Manjhi.
62. Sadhu Kewat.
63. Malti Manjhi.
64. Gokul.
65. Budhui Manjhi.
66. Jagdish Bhua.
67. Sundari Manjhi.
68. Phagu Sawra.
69. Mahabir Sargakar.
70. Bhadu Yadav.
71. Pardeshi Rajwar.
72. Monharan.
73. Prahlad Yadav.
74. Chandram Sawra.
75. Bhola Prasad.
76. Pardeshi.
77. Haricharan Paswan.
78. Nirmal Kr. Chakraborty.

2. The case of the sponsoring union, Bihar Colliery Kamgar Union, as disclosed in the written statement submitted by it on behalf of the concerned workmen, details apart, is as follows:

S/Shri Panchanan Bouri and other concerned workmen have been working as permanent Truck Loaders within the precinct and premises of the Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. since long with unblemished record of service. They have been performing the job of coal loader under the direct control and supervision of the management of Kuiya Colliery. All the implements necessary for execution of the job are being supplied by the management to the concerned workmen. Each of the concerned workmen has put in more than 240 days attendance in each calendar year as coal loader. The job of loaders is a prohibited category of job. M/s. B.C.C. Ltd. has got permanent employees who have been doing the same nature of job of loading of coal at the same place along with the concerned workmen. Despite these facts the management has been disbursing the wages of the concerned workmen through intermediary and that too below the rates of Wage Board Recommendation and N.C.W.A. I, II, III and IV. The union served a strike notice on 29-12-1981 demanding regularisation of the concerned workmen and payment of wages at par with other permanent loaders. The conciliation proceeding over the matter ended in a failure due to the adamant attitude of the management. The then Government was known for its anti-labour attitude and policy; it did not either refer the dispute for adjudication nor did it reject the dispute for adjudication and kept it pending since 1982. The union and the workmen concerned represented to the Ministry and the different authorities for earlier reference of the dispute for adjudication, but without any effect. Seeing no other alternative the union filed representation before Hon'ble High Court at Patna, Ranchi Bench, which was registered as C.W.J.C. No. 1330/83(R). The Hon'ble Court was pleased to direct the Government to pass proper order in accordance with law. Thereupon, the Central Government, appreciating the legal position, referred the dispute for adjudication. The demand of the workmen of Kuiya Colliery for regularisation of the concerned workmen for treating them as departmental workmen are legal and justified. The action of the management in not regularising the concerned workmen and not treating them as departmental employees are illegal, arbitrary, unjustified and against the principles of natural justice. The management has not been paying them wages as per Wage Board Recommendation and N.C.W.A. I, II, III and IV. The action of the management is vindictive, discriminatory and smacks of anti-labour policy. The management had not procured any registration for engaging the concerned workmen as contractor's workmen nor had the alleged contractor procured any licence for engaging the concerned workmen in the job of coal loading. Disbursement of wages through different intermediaries is nothing but a legal camouflage. In the circumstances, the union has demanded that the concerned workmen be regularised as departmental workmen with retrospective effect and be paid wages as per N.C.W.As. The union has further submitted that some inaccuracies have crept in the Annexure to the reference containing the names of some of the concerned workmen and it has submitted the correct names with a prayer for acceptance of the same.

3. Despite notices issued under registered post from the office of the Tribunal calling upon the management to appear and to make submission on the demand of the sponsoring union, the management did not appear either to admit or to contest the claim.

4. The sponsoring union has examined two witnesses, namely, WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty, WW-2 Gokul Rewani, two of the concerned workmen and laid in evidence certain items of documents including photo copy of the order of Hon'ble High Court and Attendance-cum-Wage Registers marked Exts. W-1 to W-2/2 in support of its demand.

5. The case of the sponsoring union is that the concerned workmen have been working as Truck Loaders of coal in Kuiya Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. and that they have been performing this job within the precinct and premises of the colliery since long. WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty is one of the concerned workmen. He has stated on oath before

me that since 1978-79 they have been working in Kuiya Colliery of M/s. BCC Ltd as Truck Loaders within the precinct and premises of Kuiya Colliery. He has further stated emphatically that they have been loading coal raised from Kuiya Colliery and dumped at Depot No 22 by the workmen of the management, with the help of dumper on trucks. WW-2 Gokul Rawani, another concerned workman has lent support to the statement of WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty by stating that they have been working as Truck Loaders of coal in Kuiya Colliery for the last ten years or more and that they have been working in depot of the Kuiya Colliery known as Depot Nos 21 and 22.

6 Both, WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty and WW-2 Gokul Rawani have stated that they have been doing the job of coal loaders which is a permanent nature of job and that all of them have put in attendance for 240 days or more in every calendar year. Both of them have also stated that the representative of the management has been exercising supervision and control over their job and that the management has been providing them with work implements. Both of them have asserted that along with them regular workmen of the management have been performing the job of truck loading and that while the regular workmen have been getting Group III wages as per NCWAs, they have been getting payment at the rate of Rs. 20 per head per day for loading 4-1/2 tonnes of coal per head per day.

7 The union submitted an application on 21-12-90 before the Tribunal for directing the management to produce the attendance register of the concerned workmen from 1983 till date. The petition was allowed and the management was directing to produce those documents before this Tribunal on or before 24-1-1991 through a competent person. The order of the Tribunal in this behalf was sent to the management under registered post, but no step was taken. Anyway, the union has produced some attendance-cum-wage registers of the management which have been marked Exts W-2, W-2/1 and W-2/2. These registers contain the names of the concerned workmen, their attendance and their wages for some period during the years 1981 (Ext W-2/2), 1982 (Ext W-2/1) and 1986 (Ext W-2). These registers also bear the signatures of Naresh Sharma, Loading Clerk of Kuiya Colliery, Satnarain, another Loading Clerk of the colliery and Dhiren Halder, Magazine Clerk of the colliery which have been marked Exts W-2/a series, W-2/a/1, W-2/1/a series and W-2/2/a series.

8 Upon consideration of these evidence on record, I come to the inescapable conclusion that the concerned workmen have been working in Kuiya Colliery of M/s. BCC Ltd. as Loaders of coal for the last ten years or more and that they have been working continuously and have put in attendance for 240 days or more in a calendar year and that they have been doing the job under the control and supervision of the management. The evidence on record also establishes the fact that while regular loaders of the colliery have been getting Group III wages as per NCWAs, the concerned workmen have been getting Rs 20 per head per day provided each of them can load 4-1/2 tonnes of coal per day. Admittedly, the main business of coal mines is to raise coal and to supply the same to the customers on consideration. In order to supply coal to customers, loading of coal on truck or railway wagons is required necessarily to be done. In the context of facts and evidence on record, I come to the conclusion that the job of loading of coal is permanent nature of job.

It has been alleged by the union that the management has been disbursing wages to the concerned workmen through intermediaries below the rates as recommended by the Wage Board Recommendations and NCWA I, II, III and IV. The two concerned workmen, who have deposed before me, have stated emphatically that while the regular workmen of the colliery have been getting wages as per NCWAs, they have been getting wages at the rate of Rs 20 for loading 4-1/2 tonnes coal per head per day.

Anyway regard being had to the evidence on record as aforesaid, I am constrained to hold that although the concerned workmen have been rendering services to the management of the colliery by loading of coal from the colliery on trucks, the management has adopted the subterfuge of paying them wages through intermediary. In the circumstances, the concerned workmen shall be considered to be

the workmen of principal employer i.e. management of the colliery and not of the intermediary.

9 Shri D. Mukherjee, authorised representative of the sponsoring union has submitted before me that the job of loading of coal has been declared to be a prohibited category of job by the appropriate Government by notification issued under the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970. Both the concerned workmen, S/Shri Gokul Rawani and Nirmal Kumar Chakraborty have also asserted that loading of coal by engaging workmen through intermediary is prohibited. Indeed, the position is really so. The Central Government issued a notification dated 1-2-1975 prohibiting employment of Contract Labour in five types of work, such as, (i) Raising or raising-cum-selling of coal; (ii) Coal loading and unloading, (iii) Over burden removal and earth cutting, (iv) Soft coke manufacturing and (v) Driving of stone drifts and miscellaneous stone cutting underground. It appears that this notification was challenged before the Hon'ble Patna High Court and Hon'ble Bihar Court held that the notification issued was valid (1981 Bihar Revenue and Labour Journal—January Part-I page 25).

10 The management could not produce any document for registration of establishment under the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 nor has the licence of the so-called intermediary for engaging workmen on the job of loading of coal been produced. The provisions contained in Sections 7, 9 and 12 of the said Act envisage that (i) the establishment of the principal employer must be registered and (ii) the contractor must have a valid licence and if these conditions are not satisfied then the workmen even if employed by the intermediary, shall be considered to be the employees of the principal employer i.e. the management (1990 Lab I.C. 1968 Gujarat High Court).

11 Upon consideration of evidence on record and legal position I am constrained to hold that the concerned workmen are really the workmen of Kuiya colliery of M/s. BCC Ltd and the management of the said colliery cannot shirk away its obligation to absorb them in regular employment and to pay them Group-III wages as per NCWA, IV.

12 Now, the issue that comes to the fore of my consideration is the back wages that the concerned workmen are entitled to get from their employment. The sponsoring union has claimed that the concerned workmen should be paid back wages with retrospective effect i.e. with effect from the date of their employment. The two concerned workmen, who have deposed before me, have also claimed back wages.

It is common knowledge that the coal industry has been passing through a critical phase. It will be hardly justified if the management is called upon to pay back wages to the concerned workmen from the date of their employment or from the date when they made demand for their regularisation and payment of proper wages on the management. Taking a balanced view of the matter, I am of the opinion that the management of Kuiya Colliery shall pay Group-III wages to the concerned workmen with effect from the date of order of the Hon'ble High Court i.e. from 10-2-1988 (Ext W 1) and should regularise the concerned workmen in service.

Since there are some inaccuracies in the names of the workmen involved in the Annexure to the reference, the union has corrected the names in its written statement. WW-1 Nirmal Kumar Chakraborty has also testified that some inaccuracies have crept in the names of the workmen involved in the Annexure to the reference and he recited of the correct names in his evidence. This being so a separate Annexure is prepared and marked as Annexure 'A' containing the correct names of the workmen involved. The management is directed to regularise these workmen in service as per Annexure 'A' and to pay them back wages as mentioned before.

13 Accordingly the following award is rendered—The demand of the workmen of Kuiya Colliery Bastacolla Area of M/s. BCC Ltd P.O. Iharia Distt Dhanbad that the workmen mentioned in Annexure 'A' should be regularised and treated as departmental workmen is justified. The management of Kuiya Colliery is directed to regularise these workmen in service and pay them Group-III wages as per

N.C.W.A. IV with effect from 10-2-1988 less wages already drawn by them.

In the circumstances of the case, I award no Cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/100/82-D-III(A)]ER-Coal-I]

ANNEXURE 'A'

1. Panchanan Bouri.
2. Sharam Mahato.
3. Malinda Bouri.
4. Anand Bouri.
5. Peyarilal Yadav.
6. Sokhilal Yadav.
7. Sobha Ram Yadav.
8. Deoanand Yadav.
9. Mogaram Bouri.
10. Suresh Rabidas.
11. Amulya Bouri.
12. Bisu Mahato.
13. Panu Bouri.
14. Somaru Yadav.
15. Sankar Bouri.
16. Sadan Yadav.
17. Ramlal K. P.
18. Alma Manjhi.
19. Sonalal Manjhi.
20. Bhuchi Manjhi.
21. Ajan Manjhi.
22. Prabhu Manjhi.
23. Kishun Manjhi.
24. Lakhiya Manjhi.
25. Chandu Manjhi.
26. Sarada Manjhi.
27. Ratia Manjhi.
28. Lukhi Manjhi.
29. Jhumri Manjhi.
30. Alpi Manjhi.
31. Pulmoni Manjhi.
32. Bishundhari Bhuiya.
33. Hararam Khejowar.
34. Ramchandra.
35. Pitambar Khelowar.
36. Chandu Manjhi.
37. Ubia Sawra.
38. Cheitmoti Lal.
39. Madan Prasad Rawani.
40. Biswanath Paramanik.
41. Sital Bhuiya.
42. Rameswar Manjhi.
43. Naresh Bhuiya.
44. Sanichar Manjhi.
45. Mohan Bhuiya.
46. Tirku Manjhi.
47. Bandhu Bhuiya.
48. Jaleswar Manjhi.
49. Lakhu Bhuiya.
50. Sarkar Manjhi.
51. Lal Manjhi.
52. Shyamlal Manjhi.
53. Ganu Manjhi.
54. Sarbeswar Bouri.
55. Sonaram Manjhi.
56. Sankar Bouri.
57. Gopal Manjhi.
58. Charku Bouri.
59. Ram Manjhi.

60. Pramod Kewat.
61. Jatilal Manjhi.
62. Sudhu Kewat.
63. Malti Manjhi.
64. Gokhul Rewani.
65. Budhni Manjhi.
66. Jagdish Bhuiya.
67. Sundari Manjhi.
68. Khubhu Sagar.
69. Mahabir Sarnakar.
70. Bahadur Yadav.
71. Pardeshi Rajwar.
72. Monoharan Chakraborty.
73. Prahlad Yadav.
74. Chandram Sawra.
75. Bhola Prasad Mahato.
76. Pardeshi Prasad.
77. Haricharan Paswan.
78. Nirmal Kumar Chakraborty.

का.आ. 719 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की कनकानी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 11-2-1991 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 719.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kankanee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on 11-2-1991.

ANNEXURE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 130 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kankanee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated, the 28th January, 1991

AWARD

By Order No. L-20012/35/89-I.R. (Coal-I), dated, the 6th October, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad for regular employment to Shri Bhavesh Jha, delisted miner loader with 99

days of attendance in 1974-75 in Kankanee Colliery to Area No. V of M/s. BCCL is justified? If yes, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the sponsoring union, Rashuiya Colliery Mazdoor Sangh, as disclosed in the written statement submitted on behalf of the concerned workmen, details apart, is as follows :

Shri Bhavesh Jha, the concerned workman, was employed by the management of Kankanee Colliery of Area No. V of M/s. BCCL as delisted miner/loader in 1973, he worked in that capacity for sometime in 1974 and had put in 99 days attendance on duty. Thereafter he was stopped from the said job by the management. After he was stopped from duty by the management the concerned workman as well as his union raised the issue before the management for allowing him duty but to no avail. The management of M/s. B.C.C. Ltd. introduced a scheme for employment of a workman who had put in 75 days of duty in one year during 1973 in the job of miner/loader in the Colliery. In accordance with the said scheme the concerned workman was entitled to get a job of miner/loader, he having put in 76 days attendance in 1973. The union raised the issue before the management and the matter was discussed between the union and the management on 28-12-1983 when it was decided that the case would be examined and expedited as per company's policy alongwith similar other cases. The matter was allowed to drift and again the union raised the matter before the management and again the issue was discussed between the management and the union representative on 17-5-1985 when it was decided that the union should take up the matter with higher authorities. A special meeting of the Central Consultative Committee of BCCL was held on 26-4-1986 which is a joint committee of the management of M/s. B.C.C. Ltd. and the major unions functioning in M/s B.C.C. Ltd. in which the BCCL management desired to increase the production target of coal by fresh employment of 5,407 miners/loaders from such persons who were covered by the scheme of the management. The concerned workman laid his claim before the management by letter dated 28-7-1986 written by the union but no reply was received nor the concerned workman was allowed duty as miner/loader. In the circumstances, the union made a representation before the A.L.C. (C), Dhanbad on behalf of the concerned workman. The conciliation proceeding ended in a failure and the present reference has been made by the appropriate Government for adjudication.

3. The case of the management of Kankanee Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., as appearing in the written statement-cum-rejoinder submitted, briefly stated, is as follows :

The present reference is not legally maintainable. There was no delisted miner/loader at any point of time. The miner/loaders were designated as permanent, probationer or badli workers. The wagon loaders were designated as permanent casual and delisted/unlisted casual workers. The assertion of the concerned workman that he was delisted miner/loader is obviously false. His assertion that he put in 99 days of attendance in the year 1974-75 as miner/loaders is also false. He submitted an application to the General Manager that he worked as delisted mazdoor in 1973-74 and he should be given the job of miner/loader as per circular of the management. No person was ever appointed as delisted mazdoor. There used to be one group of wagon loaders, who were described as delisted/unlisted casual wagon loaders during the period from 1973 to 1976. In 1976 the practice of engaging unlisted/delisted casual wagon loaders was stopped. The concerned workman failed to produce any paper in support of his claim that he worked as delisted mazdoor in Kankanee Colliery during the year 1973-74 and he should be given the job of miner/loader as took up the case of the concerned workman, stating that he had worked as delisted casual wagon loader in 1973-74 and had put more than 75 days attendance and he should be given the job of badli miner/loader. He failed to produce any paper in support of his case. He is not a genuine worker and making an attempt to enter into the services of the management through back door method with the help of some manipulated documents.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has asserted that there was no scheme

for giving employment as miner/loader to all kinds of workmen who had put in attendance of 75 days or more in 1973. The scheme was introduced for delisted/unlisted casual wagon loader to give them job of badli miner/loaders provided they had worked during the year 1973 to 1976 and had put in 75 days attendance as delisted/unlisted casual wagon loaders. The circular was issued on 4-8-80. The concerned workman is not entitled to get the job of miner/loaders.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the sponsoring union has denied each and every contention of the management and asserted that the concerned workman has not been trying to get into the employment of the management by any devious means.

6. In support of its demand, the sponsoring union has examined the concerned workman and laid an evidence a number of documents which have been marked Exts. W-1 to W-4. Besides, the union has submitted a photo copy of special meeting of the Central Consultative Committee held on 26-4-86 at Koyla Bhavan.

The management has examined neither any witness nor has it laid in evidence any document in refutation of the demand of the sponsoring union.

7. In his evidence the concerned workman has stated that in 1973-74 he worked as miner/loader in Kankanee Colliery and that in 1973-74 he had put in attendance for more than 75 days in each year. He has further stated that after 1974 he was not given any duty and his union took up the case with the management and the discussion ensued. In cross-examination he has stated that he was working as delisted casual workman and was working as miner/loader in underground mine. In the course of cross-examination of the concerned workman the management has not asserted that he was not employed in the Colliery. Thus from the evidence of the concerned workman it is evident that he was working in Kankanee Colliery during 1973-74 as casual miner/loader and in the process he had put in attendance for 150 days.

8. It appears that his case was taken up by the union and a discussion between the management and the union was held on 28-12-87. Record notes of discussion (Ext. W-3) indicates that the management agreed to examine and expedite the case of the concerned workman as per company's policy alongwith similar other cases. Admittedly the fall-out of the discussion achieved nothing and again the matter of the concerned workman was discussed by the union with the management. Note of discussion held on 17-5-85 (Ext. W-2) has been recorded as follows :

"Shri Bhavesh Jha was a delisted employee of Kankanee. As per Bonus register he had 76 days attendance during the year 1973 and 24 days attendance during the year 1974. It is regretted as nothing can be done now. However union can take up the matter at higher level."

Thereafter Shri G. D. Pandey, Joint General Secretary of the sponsoring union, wrote on 28-7-86 to the General Manager, M/s. B.C.C. Ltd. Area No. V, Sijua Area requesting for the job of badli miner/loader to Bhavesh Jha, a workman of Kankanee Colliery (Ext. W-1). In this letter Shri Pandey has written to state that the management had come forward to allow such persons to work as badli miner/loader provided they are not more than 45 years of age and medically fit. Shri Pandey requested the management to look into the matter so that the workman can resume his duty. It appears that nothing has come out of this letter.

9. Shri S. Bose, authorised representative of the sponsoring union has submitted before me that the concerned workman was a casual miner/loader in Kankanee Colliery and he may be deployed for duty as badli loader in terms of the circular of the management dated 4-8-80 (Ext. W-4). The circular of the management reads as follows :

"Ref. No. BCCL/IR/22(14)/80/51417—667 dated 4-8-1980

To

All General Managers,

All Colliery Managers/Superintendents/Agents.

Sub : Deployment of Badli Loaders.

Dear Sir(s),

It has been brought to our notice that absenteeism in general and particularly in the category of miners and loaders has gone up as a result of which production has been suffering. While it is necessary to take effective steps to overcome this situation by controlling absenteeism and explain to the workers as to how their absence works against their own interest in terms of loss of wages etc. It is also necessary that alternative steps are taken to ensure that production does not suffer on account of absenteeism of miners and loaders particularly at a time when the country needs coal so urgently.

2. This matter has been discussed with the members of the Central Trade Union Organisations and the consensus is that we may deploy Badli Loaders in place of permanent miners and loaders who are temporarily absent for one reason or the other. It may, however, be pointed out that employment of Badli Loaders will be only for the duration of the position of availability of miners and loaders is not improved. It is emphasised that the management would not take responsibility with regard to their deployment on a regular basis or for that matter they will have no claim whatsoever with regard to their employment.

3. It has, therefore, been decided that we may take in our employment as Badli Loader such of the delisted casual wagon loaders who have put in 75 days or more attendance during the period 1973, 1974, 1975 and 1976.

4. With a view to ensure that Badlis are deployed only when the work is available, the names of such badli workers should be properly recorded and identified. maintain a Register which would be called 'Badli Register' with following columns therein :

- (a) Name of the worker appointed as Badli.
- (b) Name of the person in whose place appointed.
- (c) Father's name
- (d) Age/Date of birth
- (e) Home address
- (f) Duration of employment
- (g) In case Badli has been deputed in place of a workman who has been granted authorised leave, the period of duration may be specifically indicated.

At the time of appointment, three copies of passport size photographs may be obtained by the Colliery duly attested by Mukhiya, Gram Panchayat and countersigned by the concerned B.D.O.

5. The Badli Register should be maintained at each unit where such Badli Loaders are engaged. They will receive their wages weekly. It has also been agreed that if there is no requirement of Badli Loaders in a particular Colliery or Area but there are such delisted casual wagon loaders who have put in requisite attendance of 75 days or more as stipulated in circular No. CM/PS/2310 dated 27-9-1978, they may be given employment in other Area/Colliery subject to availability of work. It may also be ensured that as far as practicable, the persons having higher attendance during the period 1973, 1974, 1975 and 1976 would be given preference in the matter of deployment as Badli Miner/Loader over those having lower attendances.

Yours faithfully,

Sd/- S. K. Choudhary,
General Manager (Personnel)"

Shri B. Joshi, Advocate for the management, has contended that this circular is applicable only in the cases of delisted casual wagon loaders who have put in 75 days or more attendance during 1973, 1974, 1975 and 1976. This circular by itself shows the contention of the management that the practice of engaging undelisted/delisted casual miner/loader was stopped in 1976 is not correct. Anyway, upon consideration of the circular as a whole it appears to me that while absenteeism in general and particularly in the category of miners and loaders was hampering production and so the management devised some ways and means to deploy delisted casual wagon loaders as badli loaders who have put

in 75 days or more attendance during the years 1973, 1974, 1975 and 1976. Even so, the circular envisages that a register should be maintained in every Colliery which would be called 'Badli Register'. The intention of this circular was not to exclude the casual miner/loader from the category of badli loaders. In my view the management felt the production of coal was being hampered as a result of absenteeism in general and particularly in the category of miner/loader and in order to get over this situation the management decided to engage badli loaders which includes delisted wagon loaders who have put in 75 days or more attendance during 1973-76 including casual miner/loaders. There can be no reason to exclude casual miner/loaders for employment as badli loaders when they had for sometime worked on that job. The concerned workman has also worked as casual miner/loader for more than 75 days in 1973 and 24 days in 1974 even as per showing of the management (Ext. W-2). In the connection I cannot but point out the minutes of special meeting of Central Consultative Committee held on 26-4-86. Although this is not an exhibited document, its authenticity has not been assailed by the management. An excerpt from the Minutes of the meeting reads as follows :

"Chairman/Managing Director apprised the members of the purpose for which the meeting had been convened. He said that the strength of Miners/Loaders in the year, 1975-76 was about 30,000 and the production of coal from underground mines was about 10 M.T. Over a gap of 10 years the strength of Miners/Loaders has gone down considerably to about 35,000. Of these 35,000 the effective attendance varies from 22,000 to 22,300 due to absenteeism and diversion.

10. From this evidence or record it is abundantly clear that the production of coal by M/s. B.C.C. Ltd. has gone down considerably because of decline in effective attendance of miner/loader. The concerned workman has stated in his testimony that he is capable to work as miner/loader. When he has been offering his service to the management and the management is in dire need of service of miner/loaders I failed to understand why the management has not accepted his offer and give him employment as badli miner/loader. In my view having regard to the target for increasing the production of the coal as envisioned by the management and the intention of the management to employ casual miner/loader including delisted casual wagon loader as badli miner/loaders, the concerned workman Bhavesh Jha should be given employment by the management as badli miner/loader in any Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

11. Accordingly, the following award is rendered—

The demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh for employment of the concerned workman in Kankana Colliery of Area No. V of M/s B.C.C. Ltd. is justified. The management of M/s. B.C.C. Ltd. is directed to put his name on 'Badli Register' as badli miner/loader and employ him as badli miner/loader in Kankana Colliery or in any other Colliery as and when exigency arises, provided he is found medically fit.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. I-20012/35/89-IR-Coal-I]

का.आ. 720— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स बी.सी. सी.एन. के कुसुण्डा क्षेत्र के के.ओ.सी.पी. के प्रबन्धनत्व में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1) धनबाद के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 720.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the annexure in

the industrial dispute between the employers in relation to the management of K.O.C.P. of Kusunda Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 11th February, 1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) AT DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 64 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of K.O.C.P. of Kusunda Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Kusunda, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

PRESENT :

For the employer—Shri S. C. Saneja Personnel Manager.

For the workmen—Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary, Janta Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 31st January, 1991

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/66/88-D.3(A) dated the 14th June, 1988 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of K.O.C.P., Dhanbad of M/s. B.C.C. Limited in dismissing Sri Sotim Ahir, Night Guard from service with effect from 10th December, 1986 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an Award should not be made on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an Award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the Award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. L-20012/66/88-D-III(A)/IR-Coal-I]

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Ref. No. 64/88

Employers in relation to the management of Dhan/KOCP.

AND

Their workmen.

Petition of Compromise

The humble petition on behalf of the parties to the above dispute most respectfully sheweth :—

1. That the above dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

Terms of Settlement

- (a) That the concerned workman Sri Sotim Ahir, Night Guard, Dhan K.O.C.P. will be taken into employment within two months from the date of this settlement when he will report for his duty.
- (b) That the continuity of service of the concerned workman will be maintained for the purpose of payment of gratuity; but he will not be entitled any wages and benefits for the period of his idleness on account of his dismissal from 10th December, 1986 till the period of his resumption of his duty. The period from 10th December, 1986 till his resumption of duty will be considered as leave without wages and benefits and will be treated as 'dies-non'.
- (c) That the concerned workman will be posted at any colliery within Kusunda Area at the discretion of the management. The concerned workman will not claim for his employment at Dhan/KOCP.

2. That in view of the above settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above, the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the workmen :

Sd/-

1. (Y. P. Singh)
(Area Sec. JMS)

Sd/-

2. (Sotim)
(Concerned workman)

For the Employers :

Sd/-

1. (U. Singh)
General Manager
Sd/-

2. (S. C. Saneja)
Personnel Manager

Witness :

1. Sd/-

2. Sd/-

Part of the Award

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का.आ. 721 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. की मिजुआ कोलियरी के प्रबन्धन में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1) धनबाद के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-2-91 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 721—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government

Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure is the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sijua Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company and their workmen, which was received by the Central Government on 12-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) AT DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 61 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sijua Colliery of M/s. Tisco Ltd., Jamadoba, Distt. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employers—Shri A. Hashmi, Personnel Manager.

For the workmen—Shri B. N. Sharma Joint General Secretary, Janta Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 31st January, 1991

AWARD

By Order No. I-12012/440/81-D.M. (A) dated, the 15th June, 1988, the Central Government in the Ministry of Labour, has in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the I. D. Act, 1947, referred the following for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of M/s. Tisco Ltd.'s Sijua Colliery in terminating the services of Shri Ramayan Thakur, Watchman is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. The case of the management of Sijua Colliery of M/s. Tisco Ltd., as disclosed in the W.S.-cum-rejoinder details apart is as follows :—

The present reference is not legally maintainable. Sri Ramayan Thakur, the concerned workman was employed as a temporary watchman in the year 1968 and was made permanent with effect from 10-8-70. During the month of July-August 1976 anonymous letters were received by Dr. S. C. Chawla, Pathologist, Tata Central Hospital, Jamadoba which contained threats on his life as well as the life of his family members. In the month of September, 1976 the Security Department detected that the above letters were written by Sri Ramayan Thakur. Shri Thakur was confronted with the anonymous letters and he admitted the same to have been written by him. The conduct of Ramayan Thakur as Security Personnel was unbecoming of an employee of the management and the management has lost confidence on him. His services were therefore terminated by letter dated 28-1-1977 with effect from 1-2-1977 by offering him one month's salary in lieu of notice as per condition of service envisaged in the certified Standing Order. It may be mentioned that a Watchman is expected to watch and guard the life and property of the employer and his staff and as such the anonymous letters containing threats on the life of the employees and their family members were considered grave and serious and as the workman was not found fit to be retained in the employment of the Security Department, The concerned workman raised an industrial dispute challenging the validity of termination of his services with effect from 1-2-77. The Central Government referred the

said dispute to this Tribunal by notification dated 14-9-78 for adjudication. The said reference was numbered as Ref. No. 28/78 and an Award was passed on 18-3-80. The relevant findings of the Tribunal are gleaned herein below :—

- (a) It is not disputed that the workman concerned belongs to the Security Department and as such he is to protect the life of the employees of the Company—and is to guard its property. That being so when a personnel in the Security Department of the Company himself threatens other employees he is bound to loss confidence and that of the Company.
- (b) On the basis of evidence it must be held that the termination is bona fide and there is nothing to show that it is the result of victimisation.
- (c) The termination of service of the workman has been found to be an order of retrenchment.
- (d) It is open to the management once again to pass an order of termination in accordance with the law."

The Tribunal permitted the management to retrench the concerned workman after complying with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act. He was held to continue in employment as the conditions precedent to retrenchment i.e. payment of notice pay and retrenchment compensation had not been complied with. The management implemented the Award and Shri Thakur was reinstated with effect from 1-2-77. The management terminated his services with effect from 14-8-80 and tendered payment of retrenchment compensation, notice pay, back wages and other dues. He was advised by letter dated 3-8-1990 of the General Manager (Collieries) to collect all dues on any day during office hours. One month's notice pay was sent by M.O. It was further clarified by letter dated 13-8-80 that he would be paid 3 months notice pay out of which one month's notice pay had been sent by M.O. and 2 month's notice pay would be paid along with other dues. The concerned workman received back wages, one month's notice pay sent through M.O., 2 month's notice pay and retrenchment compensation and all other dues. The Award dated 18-3-80 was fully implemented. In the circumstances, the management has submitted that its action in terminating the services of the concerned is bona fide, legal and justified and the concerned workman is not entitled to any relief.

3. The case of the concerned workman, as appearing in W.S. submitted on behalf of the concerned workman by the sponsoring union, Janta Mazdoor Sangh, briefly, states is as follows :—

Shri Ramayan Thakur, the concerned workman was working in the permanent post as Watchman in the Security Department of Tisco and he was posted at Sijua Colliery at the relevant time. His services were terminated with effect from 1-2-1977 illegally, wrongfully and in a mala fide manner without serving him with any chargesheet and service of notice of any enquiry. Thereafter an industrial dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad but the conciliation proceeding ended in failure and the Ministry of Labour was pleased to refer the dispute to this Tribunal which was numbered as Ref. 28/78. This Tribunal, by an Award in Ref. No. 28/78 set aside the order of termination of the management and passed order for his reinstatement in service with back wages. One Shri G. Prasad again terminated his services by letter dated 1-8-80 with effect from 14-8-80 and after making payment of back wages but without any justifiable ground. Shri Prasad had no legal authority to terminate the services of the concerned workman; he acted illegally and beyond jurisdiction by terminating the services of the concerned workman. The termination of the services of the concerned workman amounts to illegal retrenchment and mala fide action of the management

as conditions precedent to retrenchment as laid down in Section 25-F and 25-N of the I. D. Act, 1947 have not been complied with. Being aggrieved by the illegal order of termination the sponsoring union raised an industrial dispute before the ALC (C), Dhanbad by letter dated 11/19-5-1981. But no settlement could be arrived at and the ALC(C), Dhanbad sent failure report of conciliation to the Central Government New Delhi. The Central Government declined to refer the matter for adjudication to any Industrial Tribunal. The sponsoring union failed a Writ Petition before the Patna High Court, Ranchi Bench for quashing the order of the Central Government and prayed for issuance of a direction to the Central Government for making reference of the dispute to an Industrial Tribunal for adjudication. The Hon'ble Court directed the appropriate Government to reconsider the matter and to pass an order afresh in accordance with the law. In compliance of the direction of the Hon'ble High Court the Government of India, Ministry of Labour has referred the present dispute for adjudication by this Tribunal. The management of Tisco, did not implement the Award of Ref. No. 28/78 with good grace. The retrenchment in quick succession is demonstration of grudge, ill will, malice and clearly indicative of victimisation and revengeful act. It has been asserted that the termination of the services of the concerned workman tantamounts to illegal retrenchment as conditions precedent to retrenchment as per Section 25-F and 25-N of the I. D. Act, 1947, have not been complied with. The management applied to the Central Government for permission for retrenching the concerned workman which was refused. Thus the action of the management is in gross violation of the provisions of the I. D. Act. In the circumstances, the union has prayed that the Award be passed holding illegal termination of the services of the concerned workman illegal with a direction upon the management to reinstate the concerned workman in service with payment of full back wages.

4. In the rejoinder to the W.S. of the sponsoring union the management has denied and disputed the facts with regard to the Award of this Tribunal passed in Ref. No. 28/78 and submitted that the General Manager (Collieries) who was superior to the Agent of the Colliery was competent to terminate the services of the concerned workman. Shri G. Prasad did not sign the order of termination of the services of the concerned workman. The concerned workman was paid 3 months notice pay and back wages before 14-8-80 when the termination order came into effect. It is wrong to suggest that the Award was not implemented in good grace. In view of the Award passed in Ref. No. 28/78 there was no necessity for obtaining fresh permission from the Central Government and as a measure of abundant precaution the management took permission. Anyway the provision relating to the approval of retrenchment has been declared ultra vires by the Madras High Court. The Central Government, after going through the Award and other relevant documents, held the action of the management justified and impliedly granted permission for retrenchment. The present reference is due to the direction of the Hon'ble High Court in order to give a chance to the concerned workman to present his case before the Tribunal. All legal formalities relating to retrenchment were complied with in terms of the Award.

5. In rejoinder to the W.S. of the management the sponsoring union has reiterated the fact as contained in his W.S. and emphasized that the termination of the services of the concerned workman for loss of confidence is an act of misconduct for which no disciplinary proceeding was initiated. The action of the management is contrary to the provision of the certified standing orders and also in violation of the principles of natural justice.

6. The management, in order to justify its action has examined one witness namely MW-1 Shri S. N. Sinha, Chief Personnel Manager of Tisco, Collieries, Jamadoba and laid in evidence a sheaf of documents which have been marked Exts. M-1 to M-14. On the other hand the sponsoring union has not examined the concerned workman or any other

witness but has laid in evidence two items of documents which have been marked Ext. W-1 and W-2.

7. Admittedly Shri Ramayan Thakur, the concerned workman was employed as a temporary watchman in the Security department in 1968 and was made permanent with effect from 10-8-70. He was posted at Sijua Colliery. His services were terminated with effect from 1-2-77 by offering him one month's salary in lieu of notice as per conditions of service envisaged in the certified standing orders. The management terminated his services on the ground of loss of confidence in him as it transpired that he had written some anonymous letters to Dr. S. C. Chawla, Pathologist, Tata Central Hospital, Jamadoba which contained threats on his life as well as on the life of his family members. The concerned workman raised an industrial dispute over the issue of his termination of services and the dispute was referred to this Tribunal for adjudication and registered as Ref. No. 28/78. The dispute was adjudicated by Hon'ble Mr. Justice B. K. Ray who was then the Presiding Officer of the Tribunal. A copy of the Award has been produced by the management and marked as Ext. M-1. It appears from the Award that Mr. Justice Ray, upon consideration of evidence on record came to the following factual conclusion :—

"The evidence led by the management fully establishes its case that the workman concerned wrote three anonymous letters Ext. M-4, M-5 and M-6 threatening Dr. Chawla and the members of his family. I have also no hesitation in mind to hold that the workman himself admitted that he was the author of those letters and he made endorsement Exts. M-1, M-2 and M-3 in his own hand and under his own signatures in those letters. It is not disputed that the workman concerned belongs to the Security department and as such he is to protect life of the employees of the company and go guard its property. That being so, when a personnel in a security department of the company himself threatens other employees of the company as found in Exts. M-4, M-5 and M-6 he is bound to lose confidence and trust of the management. But merely because an order of termination of service of a workman on the face of it appears to be an order of termination simpliciter, still the Tribunal has to go behind the order to find out if the order is the result of bona-fide exercise of power vested in the management or is a mere cloak to cover a case of victimisation. Mr. Mukherjee concedes to this position of law but submits that if the evidence led by the management is accepted, there is nothing to show that the order of termination in question is not a bona-fide exercise of power by the management or is the result of victimisation. This contention of Mr. Mukherjee has sufficient force. I have already said that evidence of two witnesses examined by the management is trustworthy and on the basis of that evidence it must be held that the order of termination is bona-fide one and there is nothing to show that it is the result of victimisation."

Then again Mr. Justice Ray was pleased to hold as follows :—

"In the case of Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. V. Shambhu Nath Mukherjee (AIR 1978 SC 8) it was held that striking off the names of the workman from the rolls amount to retrenchment under Section 2(oo) of the Act. It was also held in that case that whenever the employer purports to terminate the services of an employee, which amounts to be retrenchment within the meaning of the Act the same has to be in conformity with the requirements of Section 25-F. If there is non-compliance, the order of termination shall be vitiated. This being the position of law I hold that the order of termination in the case before me amounts to an order of retrenchment and the provisions of Section 25-F not having been complied with the order cannot be sustained in law. The workman concerned is, therefore, entitled to reinstatement with all back wages from the date of termination till the date of his reinstatement.

I have already held that the impugned order of termination of services of the workman concerned is in bona-fide exercise of powers by the management

reserved to it is paragraphs 13 and 14 of the Standing Orders Ext. M-13, that the provisions in paragraphs 13 and 14 of Ext. M-13 are valid and enforceable that the workman who belonged to the Security Department of the management acted in a manner which resulted in loss of confidence in him by the management and that after loss of confidence in the workman it was open to the management to employment of the workman by an order of termination simpliciter. But as in view of the established position of law already indicated the order of termination of the services of the workman has been found to be an order of retrenchment and so the order has been held to be not sustainable, the provisions of Section 25-F of I. D. Act not having been complied with, it is open to the management once again in take recourse to its power in paragraphs 13 and 14 of Ext. M-13 and to pass an order of termination in accordance with law if it so likes. The reference is answered accordingly."

8. The net fall-out of the Award passed by Mr. Justice Ray is that since the management did not comply with the provision of Section 25-F of the Act, the order of termination of the services of the concerned workman which was found to be an order of retrenchment was not sustainable and it was open to the management once again to take recourse to its power in paragraphs 13 and 14 of Certified Standing Orders and to pass an order of termination in accordance with law, if it so liked.

9. It appears that the appropriate Government initially refused to refer the present dispute for adjudication but the matter was taken up by the concerned workman before the Hon'ble Patna High Court, Ranchi Bench and the Hon'ble Court directed the appropriate Government to reconsider the matter and to pass order afresh in according with law—Ext. M-6. Thereafter the present dispute has been referred by the appropriate Government for adjudication to this Tribunal.

10. It is the firm case of the management that the Award of this Tribunal was implemented and the concerned workman was reinstated in service with effect from 1-2-77 but again the management terminated his services with effect from 14-8-80 and paid him retrenchment compensation, notice pay and back wages and other dues.

The case of the sponsoring union is that the management did not implement the Award in good grace. Anyway the union has contended that one Shri G. Prasad again terminated the services of the concerned workman by letter dated 1-8-80 with effect from 14-8-80 and that Shri Prasad had no legal authority to terminate the services of the concerned workman. It has also been contended by the union that the termination of the services of the concerned workman amounts to illegal retrenchment and mala fide action of the management as the conditions precedent to retrenchment as laid down in Section 25F and 25M of the I.D. Act, 1947 have not been complied with.

11. From the pleadings of the parties it is evident that the management implemented the Award passed in Ref. No. 28/78. In otherwise, the concerned workman was reinstated in service with all back wages from the date of termination till the date of his reinstatement.

It is an undeniable position that the services of the concerned workman are again terminated with effect from 14-8-80 on the ground of loss of confidence in him by the management. The letter of the General Manager (Collieries) dated 8-8-80 addressed to the concerned workman reads Ex. M-3 as follows:—

"Reg.—Award dated 18th March, 1990 of the Central Govt. Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad arising out of Reference No. 28 of 1978.

In terms of the above Award dated 18-3-1980, you are hereby re-instated in Company's services with effect from 1-2-1977.

As per the observation of the Tribunal in the last paragraph of the above award we may inform you that since the management had lost confidence in you,

your services are against terminated with effect from 14th August, 1980. Please note that you are hereby paid a month's wages in lieu of notice which is being sent to you by money order to your home address.

You are also informed that you should be paid retrenchment compensation in accordance with Section 25F of Industrial Disputes Act.

You shall also be paid back wages for the period you remained idle between 1-2-1977 to 13-8-'980 in accordance with the above award.

You are, therefore, hereby advised to collect your back wages and the amount of retrenchment compensation mentioned above and other dues if any, from the office of the Manager (Opn), Sijua Colliery on any working day during office hours.

You are also advised to please handover the complete plastic folder and metal token etc. to the Manager (Opn), Sijua Colliery. Please also handover the vacant possession of the Co's quarter, if any, allotted to you during your employment in the company."

It appears from the evidence of MW-1 S. N. Sinha, Chief Personnel Manager in Tisco. collieries at Jamadoba that the management paid all the dues to the concerned workman before terminating his services, such as back wages, retrenchment compensation, Bonus and notice pay. He has proved the payment register of the establishment which shows that a sum of Rs. 23,201.62P. was paid to the concerned workman in settlement of all his dues Ext. M-8. The management prepared voucher for the amount Ext. M-9 and prepared a cheque for the amount Ext. M-14 and produced Banker's statement Ext. M-10 to show that the cheque was encashed by the concerned workman. Besides it appears that the management paid him one month's wages in lieu of notice through remittance by M.O. The voucher for M.O. remittance has been marked Ext. M-12. Thus from the evidence on record it is established that the concerned workman, upon reinstatement was paid back wages and on termination of his services, was paid compensation and one month's pay in lieu of notice as envisaged in Section 25F of the I.D. Act, 1947. Besides, he was paid 2 months pay in lieu of notice presumably in compliance with the provision of section 25N of the I.D. Act, 1947 as obtaining in 1980. The concerned workman has not come forward before me to deny and dispute that he did not receive payment of back wages and compensation for retrenchment and one month's pay in lieu of notice from the management.

It appears that a notice was sent to the appropriate Government by the management for approval of termination of services of the concerned workman Ext. M-4. But the appropriate Government declined to accord approval on the ground that there was no provision for obtaining post-facto permission for retrenchment under Section 25N of the I.D. Act, Ext. W-1. The provision of Section 25N of the I.D. Act, as obtaining in 1980 was struck down by a Division Bench of the Madras High Court in a case reported in 1981 Lab. I.C. 799 (K. V. Rajendran-vrs-Dy Commissioner of Labour Madurai) and also by Rajasthan High Court in a case reported in 1984 Lab. I.C. NCC 40 (J. K. Synthetics-vrs-Union of India). This being the position provision of Section 25F of the I.D. Act, 1947 as obtaining in 1980 shall be considered to be non-existent and so the refusal of the appropriate Government to accord permission for retrenchment is considered otiose. In the circumstances the provision of Section 25F of the I.D. Act, 1947 should hold the field. The management has complied with the provision of Section 25F of the I.D. Act before resorting to retrenchment of the concerned workman.

12. Shri B. N. Sharma, authorised representative of the concerned workman has submitted that in the case of termination of services on the ground of loss of confidence holding of domestic enquiry is necessary as loss of confidence casts stigma. In support of his contention he has referred to me a decision of the Hon'ble Supreme Court reported in 1985 LLJ Vol. 1 (Chandulal-vrs-Management of Pan American World Airways Inc.) page 181. The decision lays down the

proposition that want of confidence in an employee does point to an adverse fact in his character has failed to behave upto the allegation is that the employee has failed to behave upto the expected standard of conduct which has given rise to a situation involving loss of confidence. In any view of the matter this amounts to dereliction on the part of the workman and, therefore the loss of confidence amounts to a stigma. In the case of termination of service grounded upon the conduct attaching stigma disciplinary proceedings are necessary as condition precedent to infliction of termination as a measure of punishment. In other words loss of confidence attaches a stigma to an employee and in order to terminate his services grounded on loss of confidence disciplinary proceedings are considered necessary. In the present case no such disciplinary proceedings were initiated. Even so, according to Shri A. Hashmi, authorised representative of the management the present case shall be considered to be a case where no enquiry was held and in the circumstance both the parties were at liberty to adduce evidence in support of their respective cases.

I consider that there is much force in the contention of Shri Hashmi.

Both the management and the sponsoring union have led evidence to unfold their respective cases and upon consideration of the evidence on record, I have no hesitation to rely on the Award of Mr. Justice Ray that the management has proved satisfactorily its loss of confidence in the concerned workman. From the materials on record it appears that the management issued the order of termination of service of the concerned workman in a bonafide exercise of power and the order is not a result of victimisation. Then again Shri G. Prasad did not issue the letter of termination as contended by the sponsoring union Ext. M-2 but the General Manager of Colliery issued the letter of termination Ext. M-3. The sponsoring union has not taken the plea that the General Manager of the collieries had no authority to issue letter of termination to the concerned workman. There is nothing in evidence to indicate that the General Manager had no such authority.

13. Considering the evidence on record I come to the conclusion that the action of the management of M/s. Tisco. Ltd. Sijua Colliery in terminating the services of Shri Ramayan Thakur, Watchman, the concerned workman is justified. Accordingly, the following Award is rendered:—

“The action of the management of Tisco. Ltd.’s Sijua Colliery in terminating the services of Shri Ramayan Thakur, Watchman is justified and consequently the concerned workman is entitled to no relief.”

In the circumstances of the case I award no costs.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-12012/1440/81-D.III(A)/IR Coal-I]

का.प्रा. 722:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की बलिहारी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 722.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Balihari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 15-2-91

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 165 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Balihari Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. K. Verma, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 8th February, 1991

AWARD

By Order No. L-20012(28)/89-I.R. (Coal-I), dated, the 15th November, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in terminating the services of S/Shri Arjun Chandra, Mr. Raul, Kanabai Mukherjee, Md. Abid Hussain and Bipin Bihan w.e.f. 1983 is legal and fair? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to?”

2. The order of reference for adjudication of the industrial dispute was received in the office of this Tribunal on 27-11-89 and the same was registered as Reference No. 165 of 1989. Thereafter notices were served upon the parties. Both the parties made their appearance but did not file their respective written statement and on their prayer several adjournments were granted. Lastly, when the case was fixed for filing written statement by the workman, Shri D. K. Verma, Advocate for the workman, submitted before me that he was not interested to take any step in the industrial dispute and, as such, the case be disposed of according to law. I heard both the parties and it appears to me that there is no industrial dispute existing between the workman and the employer. In the circumstances, I am constrained to pass a ‘no dispute’ award in the present industrial dispute.

This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/28/89-IR(C-I)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1991

का.प्रा. 723:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-2-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th February, 1991

S.O. 723—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen which was received by the Central Government on 11-2-91

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

ID No 18/88

In the matter of dispute between

Shri Hari Singh,
Through The General Secretary,
Central Bank Workers Organisation,
Madhupura, Station Road, Aligarh.
Versus

The Regional Manager, Regional Office,
Central Bank of India, Agra.

APPEARANCES

Sh A K Kulshetra for the workman
Shri N K Kataria for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No L-12012/67/87 D II(A) dated 28-2-87 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Agra in terminating the services of Shri Hari Singh, Sub-staff with effect from 2-4-1986 and not considering him for further employment under Section 25H of the ID Act is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2 The case was fixed today for the evidence of the Management but the representative for the workman made statement that the Management has provided an opportunity to the workman for appearing in the recruitment test to be held on 3-2-91 so he wanted to withdraw the case and no dispute award may be passed

9 In view of the statement of the representative for the Management a No Dispute award is passed in this case leaving the parties to bear their own costs

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Govt for necessary action at then end.

January, 23, 1991

GANPATI SHARMA, Presiding Officer
[No L-12012/67/87-D II(A)]

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का.आ. 724—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिन्डिकेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबद्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 724—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of

the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 14-2-1991

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY (PRESIDING OFFICER JUSTICE S N KHATRI) REFERENCE NO CGIT 10 OF 1990

PARTIES .

Employers in relation to the management of
Syndicate Bank

AND

Their Workmen

APPEARANCES .

For the Management—Shri U V. Kulkilaya,
Personnel Manager.

For the Workman—Shri K. Srinivasa Baby,
Representative of the Union

INDUSTRY . Banking.

STATE . Maharashtra.

Bombay, the 4th February, 1991

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Syndicate Bank in relation to their Hotgi Road Branch, Solapur in dismissing the services of Shri S. G. Diddi a special assistant working in the said branch is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

2. Shri S. G. Diddi (hereafter 'the Workman') was working as a Special Assistant in the Hotgi Road Branch of the Syndicate Bank, Solapur (for short 'the Management') at all material times. On 15-3-86 he was served with a chargesheet Ex M-1 for committing acts "prejudicial to the interest of the Bank", amounting to gross misconduct within the meaning of Clause 19.5 (i) of the Bi-partite settlement dated 19th October, 1966. The allegations in the chargesheet run as follows :

"On 8-1-1986 you got debited the cheque No 928765 for Rs 6,000 to SB A/c No 3170 of Sri Kale and the same entry was checked in the ledger by you and that particular entry of Rs. 6000 was entered by you in the Manager's scroll.

On 8-2-1986 you yourself debited the cheque No 928770 for Rs 7000 to SB A/c No 3170 of Shri S. V. Kale and checked the ledger entry by yourself

In both the cases, it is reported that you have personally, directly collected the cash from the Cashier Sri S. G. Gadad by tendering tokens.

It is alleged that you have debited the S. B. Account No. 3170 of Sri S. V. Kale, both the times and subsequently you have scored out the said two entries in the said Sri S. V. Kale's Account and brought the credit balance to the original balance under your own signature/authority.

At the time of S.B. Balancing in January, 1986 you have taken the total of the S.B. Balancing as sum of Rs. 6000 less the shown the balancing as tallied even when there was a difference to the tune of Rs. 6000, since you yourself have committed the above fraudulent withdrawals. Further it is alleged against you that you have tallied all the necessary registers/ledgers/books without showing any difference, even though there is a difference in reality to the extent of your fraudulent withdrawals under your own signature with a mala fide intention to hite the fraudulent withdrawal of Rs. 6000 and Rs. 7000. And it is also alleged that you have destroyed the relevant slips/instruments after receiving the cash pertaining to those fraudulent withdrawals.

Your above act of fraudulent withdrawal taking cheque leaves without entering the same in the prescribed register and debiting the same amount to S.B. A/c. No. 3170 of Sri S. V. Kale and thereafter scoring out of the said two entries in the said account and destroying the said instruments/slips after receiving the cash and correcting to the original balance, tallying at all necessary ledgers/books/registers without the correct total or the differences under your own initial/signature/authority is highly objectionable and makes you liable for disciplinary action as the same is gross misconduct on your part as per the Bipartite Settlement. Therefore you are charged for gross misconduct of "Doing an act prejudicial to the interest of the Bank" vide clause 19.5 (i) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966."

3. The Workman's case is that the Enquiry Officer held him guilty of the charge, simply on the basis of his alleged confession in a letter dated 17th February, 1986 addressed to the Management. According to him a confession by itself cannot form valid basis of a finding of guilt, and the Management should have led evidence of material witnesses and also duly proved the documents on which they relied. He challenges the Disiplinary Authorities Order of dismissal dated 7th October, 1987 and the Order of Appellate Authority dated 28th February, 1988 confirming the penalty on the aforesaid identical ground. His next submission is that in any case the penalty is disproportionately harsh, considering his unblemished past record and the fact that he made good the amount of Rs. 13000 voluntarily, even before

the fraud (the Workman refers to it as 'irregularity') was deducted by the Management. He now seeks reinstatement with full back wages.

4. The Management resist the Workman's claim in toto. According to them, the Workman had confessed to his guilt not only in his letter dated 17th February, 1986 before the domestic enquiry was initiated, but also during the course of it on diverse occasions before the Enquiry Officer, the Disciplinary Authority and finally the Appellate Authority. The Management urge that there was nothing improper, much less illegal, in basing the finding of guilt on the confession and justify award of the extreme penalty, in view of the gravity of the circumstances of the case.

5. In his rejoinder, the Workman refers to the case of an Officer of the Bank, Shri Beliga, where far lenient punishment of withholding two increments only was awarded, although the charges proved against him were far more serious. According to him, the Management being 'State' within the meaning of Article 12 of the Constitution, is not entitled to discriminate him vis-a-vis an Officer.

6. The points for determination and my findings thereon are given below :

Points for determination	Finding
--------------------------	---------

1. Is the finding of guilt bad for the reason that it is based merely on the confession of the Workman ?	No. It is good. See last para for the award. See the last para.
--	---

2. Does the penalty awarded deserve any modification ?

3. What reliefs if any, is the Workman entitled to ?

REASONS FOR FINDINGS

7. The parties have not led any oral evidence. By consent, documents filed by them have been exhibited. I have also heard the representatives of the two sides—Srinivasa Babu for the Workman and Shri Kukkilaya for the Management.

8. Although the Workman has challenged the correctness of the finding of the guilt and the quantum of punishment, he is not challenging the validity and fairness of the enquiry. As such, I am proceeding straight to the merits. The main challenge to the finding of guilt is that it is based on the Workman's confession alone, which, according to him, is not permissible in Law. The second submission is that the Enquiry Officer should not have permitted the Management's representative to cross-examine the Workman, when the latter had not tendered himself as his witness. It is also urged that the Management should have examined the Cashier and Customer Kale

in respect of whole Savings Account, that the workman had committed the fraud. On consideration of the facts and circumstances of the case as a whole. I find no substance in any of these submissions.

9. There is no rule of Law or prudence against basing a finding of guilt in a domestic enquiry on the admission of the Workman alone, if the admission is voluntary. In the present case there are more than adequate materials on the record to uphold the admissions as absolutely voluntary. He admitted his guilt not only in his letter of 17-2-86, but also on atleast five subsequent occasions. Ex. M-3 is the letter dated 11-6-86 written by him to the Management in reply to the chargesheet. Ex. M-5 are the proceedings of the Domestic Enquiry held on 18-2-87. On both these occasions the workman admitted his guilt in all details and prayed for mercy on the ground that in a moment of weakness he had succumbed to the temptation of collecting money or paying off dowry to the parents of his would be son-in-law. Ex. M-8 is a notice by the Asstt. General Manager (Disciplinary Authority) to the Workman to show cause against the proposed penalty of dismissal. Ex. M-9 is the Workman's reply dated 22nd August, 1987. Ex. M-11 is his letter 16th November, 1987 to the General Manager, purporting to be the memorandum of appeal. Ex. M-12 are the proceedings of appeal, dated 17-2-88. On all these occasions the workman again admitted his guilt unequivocally and only prayed for mercy. Even here he has not retracted from his admissions. I am fully satisfied that the admissions are voluntary and true and that the Enquiry Officer did not go wrong in accepting and acting upon them.

10. It is true that the Enquiry Officer permitted the Management's representative to put some questions to the workman and exhibited the documents on the strength of his admissions. The Management also did not examine Customer Kale in respect of whose account the Workman committed the fraud and Cashier Gadad who made two payments to him. However, I am satisfied that those omissions have not caused any prejudice to the workman on merits. The questions put by the Management's representative to the workman related to the authenticity of various Bank documents connected with the incident. The workman candidly admitted those documents and also gave full details of the circumstances in which he fell a prey to the temptation of encashing the two cheques. Indeed, even left to himself, he would have been required to reveal most of these circumstances, in order to persuade the Disciplinary Authority to take a lenient view. In any case he had already admitted his guilt at least on two earlier occasions namely in his letters dated 17-2-86 and 11-6-86 (Ex. M-2 & Ex. M-3) before he made his statement in the domestic enquiry on 18-2-87. There was no purpose in examining the Customer and the Cashier also in the circumstances of the case. There is no substance in the workman's submissions.

11. The Enquiry Officer, Disciplinary Authority and Appellate Authority were absolutely right in accepting and acting upon the confession of the workman and finding him guilty on its basis. I answer issue no. 1 accordingly.

12. Point No. 2 : The allegations imputed to the workman and voluntarily admitted by him are no doubt grave. Normally dismissal would be quite justified in a case of defalcation. However in the present case it appears that the workman was caught in the meshes of a difficult situation, which was not an exclusive creation of his own. This is what he stated before the Enquiry Officer on 18-2-1987. - -

"On 4th December, 1985 my eldest daughter's marriage engagement has taken place. As per old custom we have to arrange for the payment of entire dowry amount which was agreed earlier should be paid on the day of engagement only. Since I was not having the dowry money I requested bridegroom people to give me one month time to arrange for the same, for which they agreed. But to my badluck I could not secure the necessary required amount to pay, as agreed earlier. Then again I have requested the bridegroom people to give me some more time to arrange for the payments. Then they have given the ultimatum to pay the amount within 3-4 days and they will break the engagement. All these non-availability of the fund and my financial difficulties came to be known by my daughter and she also started crying by saying all these troubles were due to her marriage and if she is not there then there would not be any problems to her father and hence she started telling at house that it is better to end her life. These literances, parental feelings and circumstances, and the time limit given by the bridegroom people and my total failure to secure money within three days from outside, forced me to do the above said one fraudulent withdrawal of Rs. 6,000 to arrange towards the past payments of the dowry money as agreed earlier. While paying the above said amount of Rs. 6,000 I requested one more month time to settle the dowry payments by making final payments. During the period of one month I tried from all available sources to secure the balance amount to settle the dowry issue of my daughter. But all my trials proved futile. And as such I was rather forced by the circumstances to withdraw Rs. 7,000 on 8-2-86 from the same S.G. Account of Shri S. V. Kale, vide S. B. A/c No. 3170 by fraudulently. Hence as explained above, I humbly submit, that I have done the above gross misconduct due to the circumstances prevailed at that time and the domestic problems which forced me to commit the above frauds."

13. It is not disputed that the workman had deposited the sum of Rs. 13,000 with the Bank by 20-2-86. The circumstances in which he was tempted to collect money by fraud speak for themselves. His claim that his past record has been clean has not been controverted by the Management. No evidence is available on the records to show that it is otherwise. Considering all the circumstances and facts of the case, while I must condemn the act of the workman, I feel

that interests of justice will stand squarely met, by substituting the order of dismissal by one of his reduction in rank from Special Assistant to Clerk with effect from 7-10-87, on which date the Disciplinary Authority passed this order. The Management will also be justified in posting him in any post where he may not be required to handle cash. The workman will be entitled to be considered for promotion after 7-10-91 on completion of 4 years in Clerk's grade. He will get his back wages after deducting Subsistence Allowance that has already paid to him.

14. Before parting with the case, I may briefly refer to the submission of the workman with regard to Baliga. According to him, because this Officer was treated more leniently by the Management, he also deserves to be similarly treated. For this submission he presses in aid, the fundamental right of equality enshrined in Article 14 of the Constitution. I must record my disapproval of this approach. I may make it clear that Baliga is not involved in the present fraud. Assuming that he had committed misconduct/s of equal or even grosser gravity, I do not think that will afford legitimate justification for the present workman to claim for himself undeserved mercy. If his plea was accepted, that would be tantamount to perpetrating one more wrong in order to ease the judicial conscience by the pretence that thereby the earlier wrong stands mitigated. If the Management have filtered in their duty to mete out just and adequate punishment to Baliga—this is not my consideration or even provisional impression—it is for the higher Authorities to see that could be done to right the matter. So far as their reference is concerned, I am clear that Article 14 or any other legitimate factor does not come in my way in doing full and complete justice in the case. On its own merits, without being influenced by the facts of Baliga's case. That is all.

15. I make the following Award :

The finding of guilt of the workman as recorded in the domestic enquiry and confirmed in appeal, is upheld to be justified. The penalty of dismissal is however modified, by substituting it by the workman's reduction in rank from Special Assistant to Clerk, with effect from 7-10-87 on which date the Disciplinary Authority passed his Orders. The workman will be entitled to get full back wages as Special Assistant till 6-10-87 and as Clerk from 7-10-87 onwards. The Substance Allowance already paid to him will of course be deducted from his dues. The period of his suspension shall be treated as on duty. He will be entitled to be considered for promotion after he completes 4 years in the reduced rank of Clerk—that is after 7-10-91. Liberty to the Management to post the workman in a post he will not be required to handle Cash. Parties to bear their costs as incurred.

S N. KHATRI, Presiding Officer
[No. I-12012/433/89-D II(A)]

का.ग्रा. 725 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार यनियन बैंक प्राफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, प्रबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

(सं. 2) बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 12-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/14 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the Management of
Union Bank of India.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management—Shri S. N. Verma,
Personnel Officer.

For the Workmen—Shri S. S. Paranjape, Re-
presentative.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra.
Bombay, the 4th February, 1991

AWARD

The Central Government by their Order No. L-12012/880-88-D-2-(A) dated 16-5-1989 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

"Whether the action of management of Union Bank of India in withdrawing the higher allowance post of machine operator assigned to Mrs. K. J. Mendjoge is justified. If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the concerned lady by name Mrs. K. J. Mendjoge, as disclosed from the statement of claims (Ex. 2) filed on her behalf by the Assistant Secretary of the Union Bank Staff Association, in short, is thus :—

The lady Mrs. K. J. Mendjoge was designated as Machine Operator and she was transferred from Bhavani Path Branch to Pune City Branch by order dated 26-5-1987. Accordingly she joined the service at Pune City Branch. She was appointed as Accounts Machine Operator in place of

Mr. M. S. Joshi who got higher assignment though she was not eligible to get the same and was under bar as per Promotion agreement. The management of the Bank used to publish the seniority list of clerks. The seniority list published on 1-1-1987 of clerks working in Western Zone II revealed that the other lady Mrs. M. S. Joshi was barred for promotion or for allowance post upto 21-8-1987 as she had refused higher assignment of Special Assistant. That bar was effective from 21-8-1985 to 21-8-1987. Though Mrs. Joshi was barred for higher assignment upto 21-8-1987 she was given promotion as Machine Operator during her bar period in contravention of the Promotion policy. When the management realised that the promotion given to Mrs. Joshi was illegal, it was withdrawn in May 1987 and Mrs. Mendjoge was appointed in her place, she being an eligible employee.

- (ii) Mrs. Mendjoge was working satisfactorily as a Machine Operator. However, after a lapse of five months all of a sudden Mrs. Mendjoge received an order dated 8-10-87 by which her appointment of Machine Operator was cancelled and higher assignment was withdrawn, and it was given to Mrs. Joshi. The said order of withdrawal of Special Allowance is illegal, improper and unjustified. When the post given to Mrs. Joshi was withdrawn in May 1987, a permanent vacancy of Machine Operator had arisen at Pune City. As per the promotion agreement, the said vacancy was to be filled in on the basis of simple seniority of eligible clerks in terms of Staff Circular No. 2547. At the relevant period i.e. in May 1987 Mrs. Mendjoge was the senior-most as per the agreement and was the senior eligible clerk, and as such she got the higher assignment post in May 1987. The order of Machine Operator given to Mrs. Mendjoge revealed that it was neither temporary, nor for a specific period, but it was permanent post. Further, as per Clause 5.289 of the Desai Award, a person who is employed permanently cannot be deprived of such allowance at the sweet will and pleasure of the Bank. As such the Bank management had no right to withdraw the said allowance post from Mrs. Mendjoge. Payment of Special allowance is a service condition under the provisions of the Industrial Disputes Act. The management cannot change the service conditions unilaterally. While changing the service conditions of Mrs. Mendjoge the Bank management has failed to comply with the provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act. The withdrawal of Special Allowance post from Mrs. Mendjoge is illegal, improper and unjustified.

in withdrawing the Special Allowance post of Machine Operator from Mrs. K. J. Mendjoge is illegal, and further the Bank be directed to pay special allowance to her from the date it was withdrawn.

3. The Bank management by their written statement (Ex. 3) contested the claim of the Union, and in substance contended thus :—

The other lady Mrs. Joshi who was working as a Clerk was offered the post of Special Assistant in July 1984. She refused to accept the assignment of that post and hence she was barred for higher assignment of Special Assistant as per the Memo. dated 12-9-1984. In the year 1985 a vacancy of Machine operator arose, and that vacancy was offered to Mrs. Joshi. She accepted that offer and she was posted as Machine Operator. The assignment of the post of Accounts Machine Operator to Mrs. Joshi was perfectly legal and as per the rules of the Bank. However, in the year 1987 the Bank, through oversight and under a mistaken belief that Mrs. Joshi was not eligible, withdrew the assignment of Accounts Machine Operator from Mrs. Joshi by the order dated 26-5-1987. After withdrawing the assignment of that post from Mrs. Joshi, that assignment of Accounts Machine Operator was offered to the lady in question i.e. Mrs. Mendjoge by Memo. dated 26-5-1987. After a period of 4½ months the Bank realised its mistake and found that the withdrawal of the assignment of Accounts Machine Operator from Mrs. Joshi was not correct. Hence the Bank with a view to rectify the error, withdrew the post of Accounts Machine Operator from Mrs. Mendjoge and re-assigned it to Mrs. Joshi. Mrs. Joshi who was rightly entitled to continue as Accounts Machine Operator and Mrs. Mendjoge, at the relevant time, was not eligible for the assignment of the post of Accounts Machine Operator. It is only because of the mistaken belief and through sheer oversight of the Bank that Mrs. Mendjoge enjoyed the assignment of Accounts Machine Operator for a period of 4½ months even though she was not entitled to that assignment. Mrs. Mendjoge became eligible for the assignment of Accounts Machine Operator in February 1989 and since then she is enjoying the assignment of Accounts Machine Operator along with Special Allowance attached to the said higher assignment. Mrs. Joshi had refused the offer of assignment of post of Special Assistant, and as such she was barred for being assigned the duties of Special Assistant, and she was not barred from assignment of the post of Accounts Machine Operator. **It is not true that Mrs. Mendjoge was offered the post of Accounts Machine Operator on permanent basis.** The withdrawal of the assignment of Machine Operator with a view to rectify

the mistake committed by the Bank management earlier within a short period of 4½ months does not constitute a change of service conditions for the purpose of Section 9A of the Industrial Disputes Act.

The Bank management therefore prayed for the rejection of the prayer of the Union, and further prayed that its action in the matter be held as just and proper.

4. Issues framed at Ex. 4 are :—

- (1) Whether the Bank management, while withdrawing the Machine Operator's post carrying higher allowance, from Mrs. K. J. Mendjoge committed a breach of the provisions contained in Section 9A of the Industrial Disputes Act ?
- (2) Whether the action of management of Union Bank of India in withdrawing the higher allowance post of Machine Operator assigned to Mrs. K. J. Mendjoge, is justified ?
- (3) If not, to what relief is the workman entitled ?
- (4) What Award ?

5. My findings on the above said issues are :—

- (1) Yes
- (2) No
- (3) As per Award below.
- (4) As per Award below.

REASONS

ISSUE NO. 1

6. The lady Mrs. K. J. Mendjoge filed her affidavit at Ex. 9 in support of her case. She was cross-examined on behalf of the Bank management. Shri U. B. Rairikar, the Manager (P) of the Bank, filed his affidavit at Ex. 11 in support of the contentions of the Bank management and he was cross-examined on behalf of the said lady. The material documentary evidence on record is thus :—

By the letter dated 12-9-1984 (Ex. 5) the Superintendent of the Bank had informed the lady Mrs. Joshi that as she had expressed her inability to accept the offer of higher assignment, she is deemed to have declined it, and as such she is barred for such higher assignment permanently as per the promotion policy. By the letter dated 29-6-1985 (Ex. 6) the Regional Manager of the Bank informed the said lady Mrs. Joshi that the Bank was pleased to offer the post of Current Account Machine Operator at Pune City Branch to her with effect from 1-7-1985 and she should communicate her willingness immediately. Accordingly Mrs. Joshi accepted that post. By the letter dated 26-5-1987 (Ex. 7) the Regional Manager again informed Mrs. Joshi that the previous letter of the Bank dated 29-6-1985 designating her as Accounts

Machine Operator is hereby treated as cancelled, as she is barred for any higher assignment upto 21-5-1987, as such she should cease to draw the special allowance of Rs. 216 with immediate effect. Thereafter the Regional Manager by the letter dated 26-5-1987 (Ex. 8) informed the lady in question, namely Mrs. Mendjoge, that she is designated as Accounts Machine Operator at Pune City Branch with immediate effect and she should convey her willingness immediately. It was further mentioned in that letter that as long as she was required to perform the duties of Machine Operator, she would be entitled to a Special Allowance of Rs. 216 per month. Therefore, according to the Bank management, the said post of Accounts Machine Operator assigned to Mrs. Mendjoge was not a permanent post and that she was to get the Special Allowance as long as she was required to perform the duties of Machine Operator. By the letter dated 8-10-1987 (Ex. 13) the Regional Manager of the Bank again informed Mrs. Mendjoge that the letter dated 26-5-1987 designating her as Accounts Machine Operator is hereby treated as cancelled and she will cease to draw the special allowance with immediate effect.

7. Therefore, the admitted facts are that the post of Accounts Machine Operator was firstly assigned to Mrs. Joshi, that it was then withdrawn from her and it was assigned to Mrs. Mendjoge, and that it was withdrawn from Mrs. Mendjoge, and was reassigned to Mrs. Joshi. According to the Bank management, the post of Accounts Machine Operator which was firstly assigned to Mrs. Joshi was later on withdrawn from her only through mistake. According to Bank management, Mrs. Joshi had refused the assignment of the post of Special Assistant, and not of the post of Accounts Machine Operator, and as such she was in fact entitled to the post of Accounts Machine Operator, and only through mistake it was withdrawn from her. Further, according to the Bank management, the post of Accounts Machine Operator, after withdrawing it from Mrs. Joshi was offered to Mrs. Mendjoge, that Mrs. Mendjoge was not entitled and eligible to that post and hence later on that post was withdrawn from her. In the present reference, we are only concerned with the assignment of the post of Accounts Machine Operator to Mrs. Mendjoge and its withdrawal from her. I find that while withdrawing the post of Accounts Machine Operator from Mrs. Mendjoge the Bank management had not complied with the provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act.

8. As per Section 9A of the Industrial Disputes Act, no employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change, (a) without giving to the workman likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected or (b) within twenty-one days of giving such notice: provided that no notice shall be required for effecting any such change

(c) where the change is effected in pursuance of any settlement or award; or.....". As per the items mentioned in the Fourth Schedule compensatory and other allowances relate to the conditions of service, for the change of which notice is to be given. In the present case the post of Accounts Machine Operator carries a special allowance of Rs. 216 per month. As such, the assignment of that post relates to the conditions of service. After the said post of Accounts Machine Operator was assigned to Mrs. Mendjoge, the Bank Management thought of withdrawing that post by the letter dated 8-10-87 (Ex. 13). However no notice as required and contemplated under Section 9A of the Industrial Disputes Act, was given by the Bank management to Mrs. Mendjoge before the said post was withdrawn from her. According to the Bank management, when the post of Accounts Machine Operator was offered to Mrs. Mendjoge, she was in fact was not entitled and was not eligible to it, and it was wrongly assigned to her. Even then, in my opinion, notice as required under Section 9-A of the Industrial Disputes Act should have been given by the Bank management before the necessary orders were passed. The Bank management had assigned the said post to Mrs. Mendjoge under the belief that she was eligible for the post and hence that post was assigned to her. According to the Bank management, through mistake that post was offered and assigned to Mrs. Mendjoge, and that mistake was later on rectified, and that post was withdrawn from her. However, as the said post was firstly offered to her on the ground that, according to the management, she was then eligible to that post. Therefore, the notice under Section 9-A of the Industrial Disputes Act was necessary. The Bank management should have informed her, and she should have been heard in the matter to her and that it was proposed to be withdrawn from her, and she should have been heard in the matter and then only the necessary orders should have been passed. However, this procedure has not been followed by the management before withdrawing that post from Mrs. Mendjoge. Further, the Bank witness Shri Rairikar admitted in his cross-examination that the posts of Accounts Machine Operators were filled in on permanent basis as per station-wise seniority, and that the post of Accounts Machine Operator was offered to Mrs. Mendjoge Station-wise seniority, and therefore that post was a permanent post, and not a temporary post, as urged by the Bank management. Therefore, a notice under Section 9-A of the Industrial Disputes Act was absolutely necessary before the order regarding withdrawal of that post was passed against her. I find that the Bank management had committed a breach of the provisions contained in Section 9-A of the Industrial Disputes Act in withdrawing the said post from Mrs. Mendjoge. Issue No. 1 is found in the affirmative.

ISSUES NOS. 2 AND 3

9. As the Bank management, while withdrawing the post of Accounts Machine Operator from Mrs. K. J. Mendjoge did not comply with provisions of Section 9-A of the Industrial Disputes Act, the action of the management in withdrawing the higher allowance post of Accounts Machine Operator from Mrs. Mendjoge is not just, valid and legal. Issue No. 2 is found in the negative. The relief, therefore, the employee Mrs. K. J. Mendjoge is entitled to receive the special Allowance of the post of Accounts Machine Operator from the date it was withdrawn from her till the date it was again assigned to her. Issue No. 3 is found accordingly.

ISSUE NO. 4

10. The following Award is therefore passed.

AWARD

- (i) The action of the management of Union Bank of India in withdrawing the higher allowance post of Machine Operator assigned to Mrs. K. J. Mendjoge is not just, valid and legal.
- (ii) The management is hereby directed to pay the necessary allowance of the post of Accounts Machine Operator to Mrs. K. J. Mendjoge from the date it was withdrawn from her till the date it was again assigned to her.
- (iii) The parties to bear their own costs of this Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-12012/880/88-D.II(A)]

का.आ. 726 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धन में संबंधित नियोक्तों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (स. 1) बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करना है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-2-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 726.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No 1 Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employer in relation to the Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 14-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

(PRESIDING OFFICER : JUSTICE S. N. KHATRI)

Reference No. CGIT-33 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Bank of India.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management : Shri P. Gopalkrishnan, Advocate.

For the Workmen : Shri V. T. Mirazdar, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra.

Bombay, dated 4th February, 1991.

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the Management of Central Bank of India in terminating the services of Mr. Kirtisingh S. Negi, Peon is justified? If not to what relief the concerned Workman is entitled?"

2. Kirtisingh Shurvirsingh Negi (hereafter 'the Workman' was employed as a Watchman by the Uhasnagar Branch of the Central Bank of India (hereafter 'the Management') from 30-1-84 on daily wages. He claims to have worked for more than 240 days from 30-1-84 till 15-12-84. On that day the Management terminated his services by oral order, without following the requirements of section 25F of the Act. He challenges the termination as improper and illegal, and claim reinstatement with full back wages.

3. The Management by their written statement deny the Workman's claim. They do not deny that the Workman was in their service from 30-1-84 to 15-12-84 or that he was working as a Watchman. The main contention is that the Workman was being employed as a Casual Worker on daily wages whenever the Bank needed his services. As such the termination of his service does not amount to retrenchment within the meaning of section 2(oo), being excepted under clause (bb). They deny that the Workman had worked for 240 days and as such was entitled to protection under section 25F. His claim for reinstatement and back wages is denied in toto. The points that arise for determination are given below with my findings thereon :

Points for determination

Findings

- | | |
|--|-----|
| 1. Does the termination of the Workman's service amount to retrenchment within the meaning of section 2(oo) of the Act ? | Yes |
|--|-----|

2. Does the termination fall under exception (bb) to Section 2(oo), of the Act ?	No
--	----

3. Does the workman prove that he actually worked for more than 240 days in the Calendar 12 months immediate by proceeding 15-12-84 ?	Yes
---	-----

4. Is the retrenchment illegal ?	Yes
----------------------------------	-----

5. Is the Workman entitled to reinstatement and back wages ?	Yes
--	-----

REASONS FOR FINDINGS

4. The Workman has filed his affidavit on his behalf, Shrikant Manohar Bhandarkar who was posted at Uhasnagar Branch during the material period initially as Branch Manager and later as Deputy Chief Officer, has filed his affidavit in rebuttal. Both witnesses have been cross-examined by the other side. Documents filed by them are exhibited by consent. Although in the statement of Claim, the Workman had complained of victimisation in the cross-examination he has given up the point. So I straight go to the merits.

Points 1 and 2 :

5. As these questions are inter-linked, it will be convenient to dispose of them together. The workman affirms that he was paid Rs. 10/- per day as daily wages for all working days except Sundays. According to him, after his services were terminated on 15th December 1984, he made a representation to the Branch Manager for confirmation. The Branch Manager recommended his case, but the Bombay Metropolitan Regional Officer turned down the representation on the ground that his recruitment was in violation of their recruitment policy. Resultantly the Workman was not given work after 3-5-85. He asserts that he was working continuously on all working days, except Sundays. He denied that employment was given to him sporadically only when need arise on a particular day. As against this, Bhandarkar affirms that the Workman was being engaged as and when his services were needed and that his work was purely of a casual nature. Indeed, he even denies that the Workman was engaged as a Watchman. According to him, the Workman's duty related mainly to bringing records and documents from the godown, and carrying of papers, records and documents from one table to other. Bhandarkar's claim that the Workman was not employed as a Watchman, cannot be accepted for the reasons that in the written statement, the Management do not deny the averments in para 1 and 2 of the Workman's Statement of Claim to the effect that he was employed as a Watchman, and he was not seriously cross-examined on this aspect. I proceed on the basis that he was working as a Watchman.

6. The Workman's claim that his employment was more or less on a continuous basis, is corroborated by the data given by Bhandarkar in paras 7 to 11 of his affidavit, regarding the number of days the Workman

had actually worked. The date is as follows :—

- From 30-1-84 to 4-5-84—(12 days).
- From 14-5-84 to 4-8-84—(71 days).
- From 20-8-84 to 15-12-84—(92 days).
- From 26-1-85 to 16-2-85—(17 days).
- From March to 2-5-85—(37 days).

7. [The above figures show that the Workman had worked for as many as 12 days between 30-1-84 and 4-5-84 and again for 217 days from 14th May 1984 upto 2nd May, 1985. It can also be safely inferred that apart from Sundays which were admittedly off days and short quarterly breaks of 10 days or so, the Workman had worked on almost all working days. The contract of employment was admittedly not in writing. The above analysis of the pattern of the Workman's attendance negatives the existence of facts necessary to attract exception (bb) to section 2(oo). The placement of the short breaks once in a quarter of the year, is more consistent with the Management's anxiety to prevent the Workman from getting eligible under section 25-B(2)(a)(ii) of the Act, rather than with there being no work available for him during the breaks. For all these reasons, I return an affirmative finding on the first issue and a negative one on the second.

8. Point No. 3 : I will clear a short but vital point before I proceed to decide whether the Workman had worked for more than 240 days in the 12 months preceding the termination of his service. It is with regard to the date of termination. In the Statement of Clanni, this date is expressly stated to be 15-12-84. The Management have not denied this fact in their written statement. Now at the evidence stage they have taken the stand that the date of termination was 3-5-85. Obviously the Management cannot be allowed to make such a vital shift on an admitted position. It is true that the Workman was again engaged on 26-1-85 and he continued to work with two breaks till 2-5-85, while correspondence was going on between the Management and their Metropolitan Head Office at Bombay, regarding his absorption in the regular cadre. The proposal was ultimately not okayed by the Bombay Office and Management did not retain the Workman after 2-5-85. However, these circumstances do not detract from the admitted stand in the pleadings that the crucial date of termination is 15-12-84. For computing the number of days for which the Workman had actually worked, 12 Calendar months preceding this date will be material. I am proceeding further on this basis.

9. The Workman affirms in his affidavit that he had worked for 253 days during the period 30-1-84 to 15-12-84. He claims to have reached this figure after verifying the vouchers. No direct suggestion is made in the cross-examination that his calculations are wrong. Only a general question is put to him whether he had copies of the vouchers with him. The Workman replied in the negative. Obviously the vouchers would be in the custody of the Management and not the Workman.

10. In rebuttal, Bhandarkar has given a tally of the Workman's actually working days in paras 7 to 11 of his affidavit. The details are already extracted in para 6 supra. If Bhandarkar's evidence is believed at its face value the tally for the period 30-1-84 to 15-12-84 comes to 235 days. It is not explained why

the Management did not produce the record that was available with them on this vital question, particularly when Bhandarkar affirms to have based his affidavit on it. I may also add that even otherwise I am not much inspired by the infallibility of the Management's record. In their letter dated 30-12-85 (Ex. M-1) addressed to their Chief Manager, the Management admit that the details given by them in their earlier letter of 21-11-85 about the number of days on which the Workman had worked, were wrong and in fact he had worked for 10 days more. All the same, the fair and prudent course for the Management would have been to produce the record whatever worth it was before the Tribunal. This was not done. The cross-examination of the Workman is also casual. In 1982 1 LLJ 35 Workmen of M/s. Williamson Magor and Company Limited and M/s. William Magor & Company Limited and another. The Supreme Court has ruled that where there is reasonable doubt on facts, it should go to the weaker sections of the society. For all these reasons, I would prefer the testimony of the Workman to that of Bhandarkar and hold that the former had actually worked for 253 days upto 15-12-1984.

11. There is one more reason in support of the Workman's case. A look at the data reproduced in para 6 supra, will show that the Workman has practically worked for 40 full weeks, inclusive of Sundays. Admittedly Sundays are off days for the Bank in question. Normally the Management would have welcomed him to work on these days also, had they not been declared compulsorily closed days under section 18 of the Bombay Shops and Establishments Act. In their written submissions the Management claim that the provision of the aforesaid Act will not apply to a Nationalised Bank, which the Management admittedly are. [They rely on a ruling of the Madras High Court reported in 55 company cases 358 Union Bank of India Vs. Additional Commissioner for Workmen's Compensation. This decision in fact supports the Workman. The question for decision before the learned Single Judge was whether the exemption granted under section 4(1)(c) of the Tamil Nadu Shops and Establishments Act to "Establishments under the Central Government", applied to Nationalised Banks also. The learned Judge underlined the difference between 'an Establishment under the Central Government' and 'an Establishment of the Central Government' and held that Nationalised Banks fell under the former category and not the latter and as such they were entitled to exemption. Under the Bombay Shops and Establishments Act, exemption is granted to the establishments of the Central Government. So the exemption from compulsory weekly paid holidays will not apply in Maharashtra to Nationalised Banks, as they are not establishments of the Central Government. Thus the Management were under section 18 of the B.S.E. Act, obliged to give one paid holiday to the Workman after extracting work from him for 6 days. If due consideration is given to this aspect the number of working days for the Workman upto 15th December 1984 rises to 275, even on the assumption that he had actually worked for 235 days only, as claimed by Bhandarkar. Viewed from any angle I am satisfied that the Workman had actually worked for more than 240 days during the crucial period of 12 months preceding 15-12-84. I return an affirmative finding on this point.

12. Pont No 4 : The retrenchment of the Workman is obviously illegal and improper in view of the Management's failure to comply with the provisions of section 25-F of the Act. He is entitled to reinstatement. He affirms that he did not get alternative employment after December 1984, except the work given by the Management. A suggestion was made to him during cross-examination that he was working on some tempo. He had denied the same. There is no evidence in rebuttal. In the circumstances, he will also be entitled to get back wages from 15-12-84, minus the wages he might have received from the Bank between 25-1-85 to 2-5-85. The Management shall also pay him Rs. 1500 by way of Costs. I make the following award.

13. The termination of service of the Workman by the Management with effect from 15-12-84 is held to be illegal and improper and is hereby set aside. The Workman is directed to be reinstated in service with effect from 15-12-84 with full back wages. Of course the Management shall be entitled to deduct the wages they have paid to him during the period 25-1-85 to 2-5-85. The Management shall bear their own costs and pay Rs. 1500 as costs to the Workman.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. L-12012/669/87-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1991

का.प्र. 727.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धन से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-2-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th February, 1991

S.O. 727.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-2-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,

TAMILNADU, MADRAS

Friday, the 25th day of January, 1991

PRESENT :

Thiru M. Gopalaswamy, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 59 of 1985

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of the Food Corporation of India, Madras-72).

BETWEEN

Shri P. Adaikkan, C/o S. Kanagasabai, MABL, No. 176, 1st Floor, Venketrengampillai Street, Triplicant, Madras-5.

AND

The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, 5/54, Creams Road, Madras-600072.

REFERENCE :

Order No. L-42012(37)/83-D.II(B)/D.IV B/D.V, dated 3-4-84 of Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute after restoration coming on this day for final disposal upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record and the workman in person having made an endorsement for withdrawing the dispute, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workmen and the management of the Food Corporation of India, Madras, arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-42012(37)/83-D.II(B)/D.IV.B/D.V, dated 3-4-1984 of the Ministry of Labour & Rehabilitation for adjudication of the following issue :—

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India, Madras in terminating the services of Shri Adaikkan, NMR workman at their Avadi Depot Madras (Construction and maintenance) w.e.f. 28-9-76 and not absorbing him as messenger (Depot) on regular basis alongwith his juniors w.e.f. 22-3-1979 is justified—If not, to what relief he is entitled to."

2. Parties were served with summons.

3. The Petitioner-workman Thiru Adaikkan filed his claim statement on 14-5-1986 putting forth his claim. The respondent management was absent and not represented and set ex-parte. No counter statement was filed. The petitioner was examined as W.W. 1 and an award was passed on 22-8-1986 holding the termination of the petitioner as illegal and directing his reinstatement with back wages, continuity of service and other attendant benefits.

4. On 29-8-1986, the respondent management filed a Miscellaneous Application No. 94/1986 with counter statement praying to set aside the ex-parte award passed on 22-8-1986. On 2-2-1987 this Tribunal has passed an order setting aside the ex parte order and allowing the application.

5. At this stage, the Petitioner-workman filed Writ Petition No. 7224 of 1987 in the High Court praying to implement the award passed by this Tribunal on 22-8-1986. The Writ Petition was dismissed by the High Court on 13-8-1987. Against the order of the High Court, the petitioner workman preferred an appeal in W.A. No. 403/1988 before the High Court, Madras. Again the Writ Appeal was also dismissed.

6. After several adjournments, with the dispute was taken up today for enquiry, the petitioner workman has made the following endorsement :

"The petitioner has been served with an order of appointment dated 7-1-91, subject to the condition that he should withdraw the above Industrial Dispute. The Petitioner has accepted the said order and hence he is not pressing the Industrial Dispute and request to dispose the Industrial dispute accordingly.

7. In view of the above endorsement, Industrial Dispute is dismissed as withdrawn.

Dated, this 25th day of January, 1991.

M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal
[No. L-42012/37/83-D.II(B)|D.IV(B)|D.V]
RAJA LAL, Desk Officer

WITNESSES EXAMINED

Before restoration :

For workman : W.W 1—Thiru P. Adaiklan

For Management : None

After restoration :

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

Before and after restoration :

For both sides : Nil.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1991

का आ. 728 :- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के सेक्शन 2 के खण्ड (के बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1990 को भारत सरकार के असामान्य राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड ii में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. 533 (ई) दिनांक 29 जून, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् -
उक्त सूचना की अधिसूची में

- (1) क्रम संख्या 1 के सामने कालम 3 के अंतर्गत हुई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का येनम क्षेत्र।"

- (2) क्रम संख्या 2 के सामने कालम 2 के अंतर्गत की गई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"श्री अजीत कुलश्रेष्ठ,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड II)
पटना।"

- (3) क्रम संख्या 3 के सामने कालम 2 के अंतर्गत हुई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"श्री मंजीत सिंह,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड II),
दिल्ली।"

- क्रम संख्या 7 के सामने कालम 3 के अंतर्गत हुई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माह क्षेत्र।"

- (5) क्रम संख्या 10 के सामने कालम 2 के अंतर्गत हुई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"श्री बी.एन. शर्मा,

क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त (ग्रेड-II)
बम्बई।"

[संख्या आर. 11013(2)/90-एस एस.-11]

New Delhi, the 14th February, 1991

S.O. 728.—In exercise of the powers conferred by clause (kb) of section 2 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Labour No. S.O. 533(E), dated the 29th June, 1990, published in Part. II Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 3rd July, 1990, namely :—
In the schedule to the said notification,—

- (i) against serial No. 1, for the entry under column (3), the following shall be substituted, namely :—

"The State of Andhra Pradesh and Yamna area of Union Territory of Pondicherry."

- (ii) against serial No. 2, for the entry under column (2), the following shall be substituted, namely :—

"Shri Ajit Kulshreshta,
Regional Provident Fund Commissioner
(Grade-II),
Patna."

- (iii) against serial No. 3, for the entry under column (2), the following shall be substituted, namely :—

"Shri Manjeet Singh,
Regional Provident Fund Commissioner
(Grade-II),
Delhi."

- (iv) against serial No. 7, for entry under column (3) the following shall be substituted, namely :—

“The State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep and Mahe, area of Union Territory of Pondicherry.”;

- (v) against serial No. 10, for the entry under column (2), the following shall be substituted, namely :—

“Shri V. N. Sharma,
Regional Provident Fund Commissioner
(Grade-II),
Bombay.”

[No. R. 11013(2)/90-SS.II]

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1991

का. आ. 729 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा 1-3-1991 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्न-लिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला जयपुर में सांगानेर नगर पालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”।

[संख्या-एम. 38013/7/91-एम. एम. I]

ऐ. के. भट्टाराई, अव्वर सचिव

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 729.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 1991 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan namely :—

“The areas comprising within the Municipal Limits of Sanganer in Jaipur District.”

[No. S-38013/7/91-SS.I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1991

का. आ. 730 :—चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1973 के नियम 3 के उप-नियम (2) के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत

के राजपत्र दिनांक 29 मार्च, 1986 के भाग-II खंड 3 उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1317 दिनांक 10 मार्च, 1986 का अतिरिक्त करने हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य के लिये सलाहकार समिति गठित करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

1. मंत्री —अध्यक्ष
श्रम और प्रशिक्षण
बिहार।
2. कल्याण आयुक्त, —उपाध्यक्ष (पदेन)
श्रम कल्याण संगठन,
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
जिला हजारीबाग (बिहार)
3. श्री भिरीवर पाण्डा —विधान सभा प्रतिनिधि
सदस्य विधान सभा
भानपुर, डाल्टेनगंज
4. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.) —केन्द्रीय सरकार के
पटना प्रतिनिधि
5. श्री आर. एम. सिंह, —नियोजकों के प्रतिनिधि
परियोजना प्रबंधक,
बिहार राज्य का खनिज विकास
निगम लि., डाल्टेनगंज,
जिला पालमू
6. श्री डी. एम. भंडारी, —नियोजकों के प्रतिनिधि
कार्यकारी निदेशक,
कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री लि.
बंजारी — जिला रोहतास।
7. श्री जयेश्वर प्रसाद सिंह —श्रमिकों के प्रतिनिधि
महामंचिव,
कमायूं क्षेत्र खदान श्रमिक संघ
(इंटक) बंजारी, जिला रोहतास।
8. श्री अनिल कारकोला —
बिहार राज्य स्टोनब्रेकिंग
श्रमिक संघ,
डाल्टेनगंज, जिला पालमू
9. श्रीमती सुषमा मसीह —महिला प्रतिनिधि
नवाडी डाकघर चुनपुर,
जिला पालमू
10. कल्याण प्रशामक —सचिव
श्रम कल्याण संगठन, श्रम मंत्रालय
भारत सरकार, फरमा जिला
हजारीबाग, (बिहार)

केन्द्रीय सरकार उक्त समिति का मुख्यालय पटना निर्धारित करती है।

[सं. यू - 19012/1/89 - डब्ल्यू. 2 (सी)]

New Delhi, the 19th February, 1991

S.O. 730.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 and in supersession of the notification No. S.O. 1317 dated 10th March, 1986 of Ministry of Labour Government of India published in Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated the 29th March, 1986 the Central Government hereby constitutes the Advisory Committee for the State of Bihar consisting of the following members, namely :—

- | | |
|---|---|
| 1. Minister,
Labour, Employment and Training
Bihar. | Chairman |
| 2. Welfare Commissioner,
Labour Welfare Organisation,
Ministry of Labour,
Government of India,
Karma,
District Hazaribagh (Bihar) | Vice Chairman
(Ex-officio) |
| 3. Shri Grivar Panda,
Member of Legislative Assembly,
Bhanathpur, Daltongunj. | Legislative
Assembly
Representative |
| 4. Regional Labour Commissioner(C),
Patna. | Central Govt.
Representative |
| 5. Shri R.S. Singh,
Project Manager,
Bihar State Minerals Development,
Corporation Limited, Daltongunj,
District Palamau. | Employers'
Representatives |
| 6. Shri D.M. Bhandari,
Executive Director,
Kalyanpur Cement Factory Ltd.,
Banjari, District Rohtas. | |
| 7. Shri Jayeshwar Prasad Singh,
General Secretary,
Kamanyu Range Quarries Labour
Union 'INTUC', Banjari,
District Rohtas. | Workers'
Representatives |
| 8. Shri Anil Karketta,
Bihar State Stone Breaking Labour
Union, Daltongunj,
District Palamau. | |
| 9. Smt. Sushma Masih,
Nawadih, Post Office Chunpur,
District Palamau. | Representative of
Women |
| 10. Welfare Administrator,
Labour Welfare Organisation,
Ministry of Labour,
Government of India
Karma,
District Hazaribagh (Bihar) | Secretary |

The Central Government hereby fixes Patna to be the headquarter of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/1/89-W. II(C)]

डब्ल्यू-II(सी) अनुभाग

का. प्रा. 731.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 तथा नियम 16 के उपनियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के दिनांक 4 मई, 1985 के राजपत्र के भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. प्रा. 1941 दिनांक 23 474 GI/91-17

अप्रैल, 1985 का अतिक्रमण करते हुए, इस अतिक्रमण से पहले जो कुछ हो चुका है या जो कुछ नहीं किया गया है को छोड़कर केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए सलाहकार समिति गठित करती है जिसे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. श्रम मंत्री
महाराष्ट्र सरकार | —अध्यक्ष |
| 2. कल्याण आयुक्त
श्रम कल्याण संगठन, नागपुर | —उपाध्यक्ष (पदेन) |
| 3. श्रम आयुक्त,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई | —सदस्य (पदेन) |
| 4. डा. मधुकर बासनिक
विधान सभा सदस्य। | —विधान मंडल के प्रति-
निधि |
| 5. श्रीनिवास वसन्तराव ठाकुर
निवेशक, ठाकुर सौदेकर एंड कं.
लि., 372, गुडवार पेठ-पुणे-2 | —नियोजकों के प्रतिनिधि |
| 6. श्री दीप डी. पटेल
पार्टनर मै. देवेन्द्र ट्रेडिंग कं.,
रेलतोली, गोडिया, जिला-भंडारा | |
| 7. कुमारी सुलेखा ताई कुम्भारे
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य बीड़ी मजदूर संघ
हरदामनगर काम्पली जिला नागपुर | —श्रमिकों के प्रतिनिधि |
| 8. श्री एम. ए. गम्कार, महामंचिव,
महाराष्ट्र राष्ट्रीय बीड़ी कामगार
संघ (इटक) खोंखोडपुरा—
औरंगाबाद | |
| 9. कल्याण प्रशासक,
श्रम कल्याण संगठन, नागपुर | —सचिव |

2. केन्द्रीय सरकार नागपुर को इस समिति या मुख्यालय निर्धारित करती है।

[सं. यू - 19012/1/88-डब्ल्यू. - 2 (सी)]
W-II(C) Department

S.O. 731—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), read with sub-rule (2) of rule 3 and rule 16 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1941, dated the 23rd April, 1985 and published in the Gazette of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 1985, the Central Government hereby appoints the following persons to the Advisory Committee for the State of Maharashtra, namely :—

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Minister of Labour,
Government of Maharashtra. | —Chairman |
| 2. The Welfare Commissioner,
Labour Welfare Organisation,
Nagpur. | Vice-Chairman
(Ex-officio) |

3. The Commissioner of Labour Government of Maharashtra, Bombay	Member (Ex-officio)
4. Dr. Madhukar Wasnik, M.L.C.	Representative of State Legislature
5. Shri Srinivas Vasantrao Thakur, Director, Thakur-Sawdekar & Co. Ltd. 377, Gurwarpath, Pune-2	Employers' Representatives
6. Shri Deep D. Patel, Partner, M/s. Devendra Trading Co., Railtoli, Gondia, District Bhandara	
7. Kum. Sulekhatai Kumbhare, President Maharashtra Rajya Beedi Mazdoor Sangh, Hardanagar, Kamptee, District Nagpur	Workers' Representatives
8. Shri M.A. Gatar, General Secretary, Mharabwada Rahrriya Beedi Kamgar Sangh (INTUC) Khokadpura, Aurangabad	
9. Welfare Administrator, Labour Welfare Organisation, Nagpur	Secretary

2. The Central Government hereby fixes Nagpur to be the headquarters of the said Committee.

[No. U-19012/1/88-W. II(C)]

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

का. ग्रा. 732.—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (ii) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 अक्तूबर, 1986 में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3822 के क्रम में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अधिनियम और लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) के प्रयोजन के लिए धातुक में कारखाने घोषित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

- एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड,
सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे मार्ग,
मुम्बई-400020
(कारखाना जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में है)
- वीनस सीमेंट लिमिटेड,
डाकघर पोखरी,
जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश)
- मधु चन्द्र टेक्नों, केम कम्प्लेक्स (प्रा.) लिमिटेड
बिन्दकी, डाकघर अंग,
जिला फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स बुड बर्न कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
120/293, लाजपत नगर,
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स एम. जो. मैन्युफैक्चरर्स,
120/293, लाजपत नगर,
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स बैलवेज इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
5/42, बिरहना मार्ग,
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स भारतीय कैमिकल्स,
58/42, बिरहना मार्ग,
कानपुर (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स यूनिकेम इंडिया,
जी. टी. रोड, चौबेपुर,
कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स कंचनजंगा कैमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी III, सैक्टर 22, मेरठ मार्ग,
औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स एच. डी. अनाज प्राइवेट लिमिटेड,
ई-16, बुलन्दशहर मार्ग, फेज सं. ,
औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद
- मैसर्स के. यू. कैमिकल्स, अमीनगंज,
परेड, कानपुर-1
- मैसर्स अशोक कैमीकल्स (प्रा.) लिमिटेड,
ई-17 पांकी औद्योगिक क्षेत्र, स्यन सं. 1,
कानपुर-208020 (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स एरोलन एन्जनीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
के-1, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली - 110016
- मैसर्स भारत थर्मिट एंड मैटल पाउडर इण्डस्ट्रीज
ई-32, सैक्टर 8, नौरडा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- मैसर्स बाल्स एंड मिलनेक्स लिमिटेड,
बिजोनी औद्योगिक क्षेत्र,
ललितपुर मार्ग, झांसी (उत्तर प्रदेश)
- मंत्रास सीमेंट लिमिटेड,
जयन्तीपुरम-521175, जगन्मयपेट (टी. क्यू.)
जिला कुण्ड (आन्ध्र प्रदेश)
- महावीर सीमेंट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड,
राज भवन, रेलवे रोड, सहारनपुर
(उत्तर प्रदेश)
- शकुनबरी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
राज भवन, रेलवे रोड, सहारनपुर
(उत्तर प्रदेश)
- कैप स्टील लिमिटेड, इन्द्याडिया कोधुर
36 वां कि. मी. हैदराबाद, महबूबनगर मार्ग,
जिला महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश)

20. शिवा मिनरल्स एंड केमिकल्स,
कचेरी मार्ग, राउरकेला (उड़ीसा)
21. ओ. एम. सी. अलायज लिमिटेड,
झाकधर बनानीपाल, जिला क्योन्सर (उड़ीसा)
22. ओरीचेम लिमिटेड, झाकधर माउथ बालदाना,
जिला धेन्कनल (उड़ीसा)
23. गणपति मिनरल्स रिफ़ैक्टरीज रागैर कालोनी,
झाकधर राजगंगपुर, जिला मून्दरगढ़ (उड़ीसा)
24. कर्ब्स एंड साई इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड,
केमिकल्स वर्क्स डिवीजन, झाकधर रुन्गा,
जिला मयुरभंज (उड़ीसा)
25. ईस्टर्न मैटल्स एंड फेरो अलायज लिमिटेड,
झाकधर हरीदासपुर, जिला कटक (उड़ीसा)
26. मैसर्स पहलादराय हैवी केमिकल्स,
83/141, जूही, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
27. मैसर्स यू. पी. सेरामिक्स,
जे. 12/81, धूपचन्दी,
वाराणसी-221002

[फा. सं. एम - 23025/1/89-डब्ल्यू. - II]

बी. डी. नागर, अवर सचिव

New Delhi, the 20th February, 1991

S.O. 732.—In pursuance of sub-section (ii) of Clause (g) of section 2 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) and in continuation of this Ministry's Notification No. 3822, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 27th October, 1986, the Central Government hereby declares the factories specified in the schedule below to be metallurgical factories for the purposes of the said Act, and the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976 (55 of 1976), namely :—

SCHEDULE

1. Associated Cement Companies Ltd.
Cement House,
121 Maharishi Karva Road,
Bombay-400020,
(Factory in District Bilaspur).
2. Venus Cement Limited,
P.O. Pokhari,
Distt. Dehradun (U.P.).
3. Madhu Chandra Techno,
Chem Complex (P) Ltd.
P.O. Aung,
Distt. Fatehpur (U.P.).
4. M/s. Wood Burn Chemicals Pvt. Ltd.,
120/293, Lajpat Nagar, Kanpur (U.P.).
5. M/s. S. O. Manufacturers,
120/293 Lajpat Nagar, Kanpur (U.P.).
6. Wellways Industries Pvt. Ltd.,
5/42 Birhana Road,
Kanpur.
7. Bhartiya Chemicals,
58/42 Birhana Road,
Kanpur.
8. M/s. Unichem India,
G. T. Road, Chaubepur,
Kanpur Dehat.
9. M/s. Kunchanjunga Chemicals Pvt. Ltd.,
Plot No. C/111, Sector 22,
Meerut Road, Industrial Area,
Ghaziabad-201003.
10. M/s. H.D. Alloys Pvt. Ltd.,
E-16 Bulandsahar Road,
Phase No. I, Industrial Area,
Ghaziabad.
11. M/s. K. U. Chemicals,
Aminganj, Parade, Kanpur-1.
12. Ashok Chemicals (P) Ltd.,
E-17, Panki Industrial,
Area, Site No. 1,
Kanpur-208020.
13. M/s. Agrons Agencies,
(India) Pvt. Ltd., K-1,
Green Park Extension,
New Delhi-110016.
14. M/s. Bharat Tharmit &
Metal Powder Industries,
E-32, Sector-8,
Noida, Ghaziabad.
15. Balls & Cylinders Ltd
Bijoli Industrial Area,
Lalitpur Road,
Jhansi (U.P.).
16. Madras Cement Ltd.,
Jayanthipuram-521175,
Jaggayyapet (TQ),
Krishna District (A.P.).
17. Mahavir Cement Works Pvt. Ltd.,
Jai Bhawan, Railway Road,
Saharanpur (U.P.).
18. Shakunbri Cement Pvt. Ltd.,
Raj Bhawan, Railway Road,
Saharanpur (U.P.).
19. Kap Steel Limited,
India, Kothur,
36th KM Hyderabad-Mahaboobnagar Road,
Mahaboobnagar District (A.P.).
20. Shiva Minerals & Chemicals,
Kacheri Road,
Rourkela (Orissa).
21. O.M.C. Alloys Ltd.,
P.O. Bananipal District,
Keonjhar (Orissa).
22. Orichem Ltd.,
P.O. South Balanda,
District Dhenkanal (Orissa).
23. Ganpathi Minerals Refractories,
Rathor Colony, P.O. Rajgangpur,
District Sundargarh (Orissa).

24. Kerbs & Cie India (P) Ltd.,
Chemicals Works Division,
P.O. Kalma,
District Mayurhanj (Orissa).
25. Eastern Metals & Ferro Alloys Ltd.,
P.O. Haridashpur,
District Cuttack (Orissa).

26. M/s. Pahaladarai Heavy Chemicals,
83142, Juhi, Kanpur (U.P.).

27. M/s. U.P. Ceramics,
J. 12/81, Dhoopchandi,
Varanasi-221002.

[F. No. S-23025/1/89-W.II]
V. D. Nagar, Under Secy.